

UPSC IQ

www.upsciq.com

नवम्बर 2018



टॉपर्स टॉक



बर्निंग इश्यूज़



प्रीलिम्स कैप्सूल



मैन्स आंसर राइटिंग



स्पाइस ऑफ़ द मंथ



AIR 13
CSE 2017

सूची

टॉपर्स से वार्ता	(1-5)	9) रुपए-मास्टरकार्ड का विवाद	48
अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध		10) 12 छोटे उद्योगों की पहल	49
1) ईरान के तेल पर भारत को छूट	6	11) मार्च 2019 तक आधे एटीएम बंद	50
2) चीन और पाकिस्तान के बीच बस सेवा	7	भूगोल और पर्यावरण	
3) पूर्वी एशिया एवं आसियान सम्मलेन 2018	8	1) 2050 तक कोआला ऑस्ट्रेलिया में विलुप्त	52
4) भूतान में चुनाव और भारत	9	2) डब्ल्यूडब्ल्यूएफ:लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018	53
5) भारत - कोसोवो विवाद	10	3) ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ क्या है?	54
6) आसिया बीबी का मामला और पाकिस्तान	12	4) महाराष्ट्र राज्य में सूखा	55
7) क्या भारत एक 'सॉफ्ट स्टेट' है?	13	5) ऑस्ट्रेलिया:वन्य जीवन पर सूखे का प्रभाव	56
8) अमेरिका में जन्म और अमेरिकी नागरिकता	14	6) रैपिड महासागरीय तापन - आईपीसीसी रिपोर्ट	56
9) विश्व का पहला आर्थिक 'ब्लू बैंड'	15	7) वन्यजीव अपराध नियंत्रण, भारत को पुरस्कार	57
10) 'ब्रेक्जिट' का समझौता, यूरोप और दुनिया	16	8) ओजोन परत में सुधार	58
11) ब्रिटेन-स्पेन का जिब्राल्टर विवाद	17	9) उत्तर भारत में जलती पराली	59
12) 'मास्को फॉर्मेट' बैठक और तालिबान	18	11) 'ग्रीन पटाखे' क्या है?	60
13) डब्ल्यू०एच०ओ का तम्बाकू नियंत्रण	19	12) सम्बन्ध:पृथ्वी पर जीवन और महाद्वीपों का घूमना	60
विज्ञान और तकनीक		13) पृथ्वी का अभ्यंतर और भूजल में खींचाव	61
1) एक साथ 31 सैटेलाइट लॉन्च	20	14) प्रशांत महासागर में आवृत्ति और टाइफून	62
2) ब्लैक होल की खोज इसरो-नासा द्वारा	21	15) होप आइलैंड पर दिखा फ्लेमिंगो	63
3) आईएनएस अरिहंत भारत की ताकत	22	16) अमेरिकी सैलानी की सेंटिनल द्वीप पर हत्या	64
4) मंगल के चन्द्रमा में गड्ढे	23	स्पाइस ऑफ़ द मंथ	(65-76)
5) मानव शरीर में एंटी-ऑक्सीडेंट की भूमिका	24	प्रीलिम्स कैप्सूलस	(77-84)
6) नासा का केप्लर टेलिस्कोप रिटायर	25	मेन्स प्रश्न	85
7) इसरो का जीसैट-29 सैटेलाइट लॉन्च	26	प्रीलिम्स प्रश्नों के हल	86
राजनीति			
1) सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद	27		
2) सीबीआई बनाम राज्य विवाद	28		
3) प्राइवेट मेम्बर बिल क्या है?	29		
4) महाराष्ट्र में चुनावी सुधार	30		
5) करतारपुर कॉरिडोर, कैबिनेट की मंजूरी	31		
अभिशासन और सामाजिक मुद्दे			
1) गुजरात: प्रवासियों का पलायन	32		
2) भारत में आंतरिक प्रवासन	33		
3) भारतीय मुसलमानों की आर्थिक स्थिति	34		
4) पोलियो और इसके उन्मूलन	35		
5) नाइजीरिया में हैज़ा का प्रकोप	36		
6) उम्रवृद्धि पर आयुर्वेदिक रोक	37		
7) निमोनिया और डायरिया रिपोर्ट 2018	38		
8) मराठा आरक्षण प्रस्ताव	39		
9) अलायड और हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल	40		
अर्थव्यवस्था			
1) 'ईज़ ऑफ़ ड्रिंग बिज़नेस', भारत 77वाँ	41		
2) सेवा क्षेत्र में तेजी और इसके निहितार्थ	42		
3) भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग	43		
4) बैंकिंग क्षेत्र में असुरक्षित ऋण	44		
5) माँग: सरकार की आरबीआई से 3.6 लाख करोड़	44		
6) आरबीआई अधिनियम की धारा 7	45		
7) दालों की बढ़ती कीमतें	46		
8) किसान क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल	47		

टॉपर्स से वार्ता

परिचय

आपकी असाधारण उपलब्धि के लिए Study IQ की टीम की ओर से बधाई। हमें खुशी है कि आपके प्रयासों को एक भव्य तरीके से पुरस्कृत किया गया है।

► चलिए हम यह पूछ कर शुरूआत करते हैं कि आपने भारत की इस सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयारी करने का फैसला कब किया?

जब मैं 2015 में सैमसंग रिसर्च इंडिया के साथ काम कर रहा था, तब सिविल सेवा में शामिल होने की इच्छा सब से पहले मन में आयी। उसी समय मैंने इसके लिए तैयारी करने का फैसला किया।

► क्या आपका बचपन से सपना था कि आप एक अधिकारी बनें? यह वास्तव में बचपन का सपना नहीं था, लेकिन मेरा झुकाव लंबे समय से सरकारी नौकरियों की ओर था।

► जब आपने टॉपर्स सूची में अपना नाम देखा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी?

जब हमने सूची में मेरा नाम खोजना शुरू किया मैं, मेरा भाई और मेरा मित्र प्रकाश चंद्र शुक्ला एक साथ थे। मेरी प्रतिक्रिया शुरूआत में अविश्वास की थी। जितना मैंने अपने लिए अपेक्षित किया था रैंक उससे काफी ऊपर थी। पहले तो हम खूब तेज़ चिल्लाये, एक-दूसरे को गले लगाया। हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया। और फिर कभी खत्म ना होने वाली फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया।

► क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं जैसे अपनी पृष्ठभूमि, अपने परिवार, स्कूल, काम इत्यादि के बारे में कुछ बताएंगे? मैं बिहार के सहरसा जिले के एक मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ। मैंने आईआईटी बीएचयू, वाराणसी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है। मैंने सैमसंग आर एंड डी बैंगलोर में अगस्त 2015 से जनवरी 2016

तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। सैमसंग छोड़ने के बाद, मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। इस बीच, मैंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2016 में आल इंडिया रैंक 1 के साथ सफलता प्राप्त की।

आपके अनुसार ऐसा क्या है निजी क्षेत्र की आकर्षक नौकरियों के प्रसार के बावजूद युवाओं के बीच सिविल सेवा को एक लोकप्रिय परीक्षा बनाता है?

एक सिविल सेवक बनने के पीछे मेरी प्रेरणा ज़िन्दगी में जल्दी ही एक पहचान प्राप्त करना था ताकि बाद में उसे और बेहतर किया जा सके। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और इसीलिए शुरूआत से ही मेरी आकांक्षाएँ सीमित थीं। यही कारण था कि मैं शुरूआत में बंगलौर में सैमसंग रिसर्च इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी से खुश था। हालांकि यह अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी थी पर इसमें पहचान बनाने में संघर्ष था। हमारी बिल्डिंग में ५ हज़ार लोग काम करते थे और मैं उनमें से एक था। मैं चाहता था कि चीज़ें बेहतर और थोड़ी और चुनौतीपूर्ण हों। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी संभालने के लिए 20-30 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि सिविल सेवा एक ऐसा करियर विकल्प है जो हमें 25 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक जिले के प्रशासन करने का अद्वितीय अवसर देती है। सिविल सेवा में शामिल होने के लिए यह मुख्य प्रेरणा थी।

रणनीति के बारे में

► जब आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपकी दिनचर्या क्या होती थी?

मैं सुबह 8 बजे उठता था। मेडिटेशन मेरी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था। मैं नियमित रूप से The Hindu पढ़ता था। इसके उपरांत मैं शेष समय को सामान्य अध्ययन और अपने वैकल्पिक विषय गणित के लिए समर्पित करता था। सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक अध्ययन में संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है।

► तैयारी के वक़्त आपकी विधि और शैली क्या थी? नोट्स बनाना तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपकी रणनीति क्या थी?

सीमित स्टडी मैटेरियल और बार-बार रिविज़न कर मॉक टेस्ट देना मेरी शैली थी। मैंने पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषयों के लिए संक्षिप्त नोट्स बनाए और उन्हें कई बार संशोधित किया। मैंने मानक पाठ्यपुस्तकों जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और आधुनिक

भारत के इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम इत्यादि जैसी पुस्तकों के नोट्स बनाने से बचना शुरू किया।

► हमने देखा है कि कई उम्मीदवार सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र के बारे में शिकायत करते हैं कि विशेषकर पिछले दो वर्षों में, यह प्रश्नपत्र कठिन रहा है। आप प्रीलिम-2019 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को क्या सुझाव देंगे? उन्हें सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? पहले मानक पाठ सामग्री खत्म करें। फिर करंट अफेयर्स को 2 या अधिक स्रोतों से कवर करें। प्रीलिम्स के लिए, अधिक से अधिक मॉक पेपर हल करें। अपनी आंखें और कान खुले रखना महत्वपूर्ण है। नेट सर्फिंग जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है।

► क्या आपको लगता है सफलता के लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है?

► प्रारंभिक परीक्षा

2015 में मैंने एक भी प्री-टेस्ट पेपर हल नहीं किया था। मैं 11 अंकों से असफल रहा। 2016 में मैंने इनसाइट टेस्ट सीरीज़ के केवल 4 या 5 टेस्ट पेपर हल किए और मैं 7 अंकों से असफल रहा। 2017 में मैंने बहुत सी टेस्ट सीरीज़ के पूरे प्रश्नपत्र हल किए। मैंने 15 अंकों के मार्जिन के साथ प्रीलिम्स परीक्षा निकाली।

निष्कर्ष: जितना ज्यादा करो उतना बेहतर।

► मुख्य परीक्षा

मुझे उत्तर लेखन में संरचना, भाषा आदि के संदर्भ में विश्वास था। मैंने सिर्फ 8 फुल लेंथ टेस्ट दिए। मेरे पास वैकल्पिक विषय गणित था। मैंने टेस्ट सीरीज़ की समय-सारिणी का सख्ती से पालन किया।

► निष्कर्ष: टेस्ट सीरीज़ की संख्या के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। कुछ लोग कम लिखते हैं, कुछ ज्यादा। बस अपनी जरूरतों को जानें और तदनुसार तैयार करें

मुख्य परीक्षा

► निबंध के प्रश्नपत्र के लिए आपने कैसे तैयारी की?

मैंने किसी भी निबंध टेस्ट सीरीज़ में नामांकन नहीं किया था। मैंने स्वयं ही 5-6 निबंध लिखे और हैं। कुछ उद्धरण सीख लिया। कुछ टॉपिक्स के निबंध पढ़ें।

► आपने अपनी परीक्षा के दौरान कौन से दो निबंध लिखे थे?

मैंने निबंध लिखे: कृषि ने भारत के अधिकांश किसानों के लिए निर्वाह का स्रोत बनने की क्षमता खो दी है। भारत में 'नई महिला' की पूर्ति एक मिथक है।

► आपने सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1, 2, 3 और 4 के लिए कैसे तैयारी की?

मैंने पाठ्यक्रम में उल्लिखित एक एक टॉपिक को कवर किया। मैंने उनके लिए संक्षिप्त नोट्स बनाए और समय-समय पर करेंट अफेयर्स के हिसाब से अपडेट करता रहा। सभी विषयों में, रिविज़न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

► क्या आप मुख्य परीक्षा के लिए उपयुक्त उत्तर लेखन रणनीति का सुझाव दे सकते हैं?

एक बार में अधिक से अधिक उत्तर लिखना धैर्य की कुंजी है। वास्तव में यह प्रयास किया जाना चाहिए कि एक बार में 20 प्रश्नों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से लिखा जाये। हमेशा याद रखें कि आदर्श उत्तर जैसा कुछ नहीं होता।

► फिक्स्ड स्पेस उत्तर पत्रिका के बारे में आप क्या सोचते हैं?

फिक्स्ड स्पेस उत्तर पत्रिका पत्रक के साथ आपका अनुभव कैसा रहा?

हर उत्तर के लिए हमेशा पर्याप्त जगह होती है। हालाँकि इंजीनियरिंग और गणित जैसे वैकल्पिक विषय में, गलत गणना की स्थिति में निश्चित स्थान के समाप्त होने का जोखिम है, लेकिन इसे पर्याप्त अभ्यास के साथ प्रबंधित किया जा सकता है।

► क्या आप बुलेट या पैराग्राफ में लिखने का सुझाव देते हैं?

हमें उन प्रश्नों को कैसे लिखना चाहिए जिनमें 'परीक्षण, चर्चा, टिप्पणी, स्पष्ट करने' को कहा जाता है?

बुलेट में लिखना उचित है क्योंकि इससे परीक्षक के लिए आसानी होगी। मैंने कभी सजेस्टिव कीवर्ड के लिए बहुत चिंता नहीं की। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को उत्तर में शामिल करूँ और फिर एक उपयुक्त निष्कर्ष दूँ।

► क्या आपको लगता है कि उचित 'इंट्रोडक्शन-बॉडी-

कन्क्लूज़न' प्रारूप बेहतर काम करता है? कई छात्रों ने साझा किया कि समय की कमी के कारण उन्होंने बजाय इस प्रारूप का पालन करने के केवल उन बिंदुओं को लिखा है जिन्हें वे याद रख सकते हैं। उम्मीदवारों को आप क्या सलाह देंगे? हाँ। यदि किसी के पास समय है, तो उम्मीदवार को 'इंट्रोडक्शन-बॉडी-कन्क्लूज़न' प्रारूप का पालन करना चाहिए।

मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय

► आपका वैकल्पिक विषय क्या था और आपने इसका चयन क्यों किया?

मेरा वैकल्पिक विषय गणित था। मेरे पास इस विषय में वास्तविक रुचि और पृष्ठभूमि थी, इसलिए मैंने गणित को चुना।

► एक वैकल्पिक विषय का चयन करते समय उम्मीदवार को किन कारकों पर विचार करना चाहिए?

जिन कारकों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए उनमें मुख्य हैं: विषय में रुचि, स्नातक में पृष्ठभूमि, पाठ्यक्रम का आकार, पूरा करने के लिए आवश्यक समय, उपलब्ध मार्गदर्शन और संसाधन तथा सामान्य अध्ययन में विषय की उपयोगिता इत्यादि।

► क्या आप अपने वैकल्पिक विषय के लिए सन्दर्भों की सूची साझा कर सकते हैं?

मैंने गणितीय विज्ञान संस्थान (आईएमएस) की कक्षाओं, अध्ययन सामग्री और टेस्ट सीरीज़ का उपयोग किया। मैंने मानक किताबें हल नहीं कीं।

► क्या आप वैकल्पिक विषय के लिए 10 साल के प्रश्नपत्र हल करने की सलाह देंगे?

हां, मैं यह सलाह दूंगा क्योंकि यह मेरे लिए कारगर था।

► क्या कोई वैकल्पिक तैयार के लिए किताबों और नोट्स पर भरोसा कर सकता है या क्या आप उम्मीदवारों को इंटरनेट का लाभ उठाने की भी सलाह देंगे?

गणित से अलग जिन विषयों का पाठ्यक्रम गतिशील है, उन्हें इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी।

► वैकल्पिक विषय का मुख्य पाठ्यक्रम समाप्त करने के लिए आपको कितने महीने लगे?

गणित लंबा विषय है और तैयारी के लिए एक वर्ष की आवश्यकता है।

► क्या आपने वैकल्पिक विषय के रिविज़न के लिए स्वयं-नोट्स बनाए हैं? यदि हां तो आपने किस प्रारूप में नोट्स

बनाये-इलेक्ट्रॉनिक या हस्तलिखित?

हां, मैंने प्रत्येक अध्याय के लिए फार्मूला शीट तैयार की और अवधारणात्मक प्रश्नों के लिए नोट्स बनाए।

► क्या आपने किसी भी पेपर मसलन GS 1 में भूगोल, में आरेख बनाये थे? क्या आपने उन्हें पेन या पेंसिल से खींचा था? क्या आपने चित्र में रेखा खींचने के लिए रूलर का उपयोग किया था? हां, मैंने आवश्यकतानुसार चित्र बनाये। मैंने उन्हें आकर्षक बनाने के लिए पेन का इस्तेमाल किया। मेरे द्वारा कहीं भी रूलर का इस्तेमाल नहीं किया गया।

► क्या आपने अपने उत्तरों को लिखते समय स्केच पेन या हाइलाइटर्स या मार्कर का उपयोग किया था? मैंने बस अपने उत्तर के महत्वपूर्ण भागों को हाइलाइट करने के लिए उन्हें अंडरलाइन किया।

► आपने नीले पेन से उत्तर दिए अथवा काले से? मैंने ब्लू पायलट वी 5 जेल पेन का प्रयोग किया।

साक्षात्कार

► साक्षात्कार के दौरान आपका दृष्टिकोण क्या था? साक्षात्कार के लिए आपने कैसे तैयारी की?

मैंने अपने DAF से संभावित प्रश्नों की एक सूची तैयार की, उनके लिए जवाब लिखा और उनका अभ्यास किया। मैंने शौक, गृह राज्य, वर्तमान मामलों, स्नातक के विषय और वैकल्पिक विषय आदि महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया।

► क्या आपने किसी मॉक इंटरव्यू में भाग लिया था? मॉक इंटरव्यू, ऑफिसियल इंटरव्यू के समान होते हैं या अलग? क्या आप उम्मीदवारों को मॉक इंटरव्यू लेने की सलाह देते हैं? हाँ। मॉक इंटरव्यू कई पहलुओं में समान थे। मैं 4-6 मॉक इंटरव्यू देने की सलाह देता हूँ।

► आपने पैनल पर अपने पहले प्रभाव को बेहतर कैसे किया? आपने साक्षात्कार के लिए क्या पहना था? मैंने सम्मान के साथ सदस्यों को बधाई दी और पूरे समय सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखने की कोशिश की। मैंने एक नेवी ब्लू सूट, एक आसमानी शर्ट और नीली टाई पहनी थी।

► आपके साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? प्रो पीके जोशी

► साक्षात्कार कब तक चला? 30-35 मिनट

► पैनल ने आपसे क्या प्रश्न पूछे और पूछे गए प्रश्नों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको साक्षात्कार के दौरान कोई अप्रिय क्षण मिला? कृपया अपना पूरा साक्षात्कार बताएं। मैं उत्सुकता से सेंट्रल हॉल में इंतजार कर रहा था। घंटी बजी। मुझे साक्षात्कार हॉल में एक चौकीदार द्वारा ले जाया गया। हॉल में प्रवेश करने के बाद, मैंने पहले अध्यक्ष को विश किया, फिर महिला सदस्य को और उसके बाद एक साथ 3 अन्य सदस्यों को।

साक्षात्कार की दिनांक और समय: 28 फरवरी 2018 को पूर्वाह्न। मैं 6 में से तीसरा उम्मीदवार था।

अध्यक्ष (डॉ पीके जोशी)

प्रश्न 1 : Xth बोर्ड में गणित में 100 अंकों की सराहना करने के बाद, अध्यक्ष सर ने पूछा, "कक्षा XII में गणित में आपको कितने अंक मिले?"

उत्तर: सर, 9 6

प्रश्न 2 : आपको CAPF में कौन सी फ़ोर्स आवंटित की गयी है?

उत्तर: सर मुझे सशस्त्र सीमा बल (SSB) आवंटित हुआ है।

प्रश्न 3h: CAPF के टॉपर होने के नाते, आपको कोई भी फ़ोर्स मिल सकता था, आपने सशस्त्र सीमा बल (SSB) का चयन क्यों किया? कोई विशेष कारण?

उत्तर : सर, SSB को भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा का काम सौंपा गया है। मैं बिहार से आया हूँ जो नेपाल के साथ लंबी सीमा साझा करता है। चूंकि मुझे स्थानीय स्थितियों के बारे में पता है, इसलिए मैंने SSB चुना है। इसके अलावा, मेरी मातृभाषा मैथिली है जो नेपाल में अच्छी संख्या में बोली भी जाती है, इसलिए मैं उनके साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकता हूँ।

प्रश्न 4 : जब हमारे पास सीमा सुरक्षा बल के रूप में BSF है, तो SSB की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर : सर, BSF को भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। भारत-पाकिस्तान

सीमा की भौगोलिक स्थिति भारत-नेपाल सीमा या भारत-भूटान सीमा से काफी अलग है। भारत-पाकिस्तान मामले में, सीमा को बंद कर दिया गया है जबकि भारत नेपाल और भूटान के साथ छिद्रपूर्ण सीमा साझा करता है। इसके अलावा सर, भटनागर समिति की एक रिपोर्ट थी जिसने एक सीमा के लिए एक बार बल अवधारणा की सिफारिश की थी, तदनुसार हमारे पास प्रत्येक सीमा के लिए अलग-अलग सैन्यबल हैं।

प्रश्न 5 : कल्पना कीजिये कि आप किसी जिले के DM हैं और एक गांव के स्कूल में आपको कक्षा 8 से 12 वीं के बच्चों को सम्बोधित करने को कहा गया है। आप उन छात्रों को गणित पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहेंगे जिन्हें गणित पढ़ना अच्छा नहीं लगता है?

उत्तर: सबसे पहले तो मैं उन्हें भारतीय गणितज्ञों के योगदान के विधाय में बताऊंगा और उन्हें प्रोत्साहित करूंगा कि इसी तरह वे भी अपने राष्ट्र को सम्मान दिलाने के लिए ऐसे या बेहतर उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद, मैं उन्हें करियर विकल्प के रूप में गणित की संभावनाओं के संबंध में बताऊंगा। अंततः, मैं उन्हें रोज़मर्रा के जीवन में गणित के अनुप्रयोगों के विषय में बताऊंगा।

प्रश्न 6: पेन-पेपर लेकर इस प्रश्न को हल कीजिये:

गणित का पहला प्रश्न: यदि कोई श्रमिक पहले दिन 75 रुपये कमाता है और दूसरे दिन 85 रुपये कमाता है तो उसकी औसत मजदूरी क्या होगी?
उत्तर: पेन-पेपर पर हल करने के बाद, 85 रुपये सर।

प्रश्न 7 : इसका उत्तर 50 kmph क्यों नहीं है?
उत्तर: सर इस केस में त्वरण स्थिर नहीं है। बस दिशा परिवर्तित कर रही है। इसलिए हम दो वेगों का समांतर माध्य नहीं ले सकते।

प्रश्न 8 : यहाँ आपने कौन सा माध्य प्रयोग किया?
उत्तर: मैंने उत्तर दिया, " सर, क्या मैं गेस कर सकता हूँ? मैं पूरी तरह शयोर नहीं हूँ।"

उन्होंने कहा, "प्लीज़"
मैंने कहा, "हरात्मक माध्य"
उन्होंने स्वीकृति में सर हिला दिया और मुझे सुकून मिला।

प्रश्न 9 : IT BHU को IIT BHU कब बनाया गया? इससे क्या परिवर्तन हुआ?
उत्तर : यह वर्ष 2012 में किया गया। उन्होंने पूछा, "क्या आपको पूरा भरोसा है?" मैंने कहा "जी सर" फिर मैंने कहा, IIT का टैग इस संस्थान को वैश्विक स्तर तक ले आया है। इसके साथ ही इसके बाद केंद्र सरकार से मिलने वाले वित्तपोषण में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

सदस्य 1 (महिला सदस्य)

प्रश्न 1 : मुंगेर किस लिए प्रसिद्ध है? (इस प्रश्न से मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं बिहार में सहरसा से हूँ।)
उत्तर: मैडम, मुंगेर की मिट्टी को खरवा मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम नाइट्रेट या गनपॉवडर की मात्रा अधिक होती है। इसलिए इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर बंदूकें बनाने में किया जाता है। इसके बाद उन्होंने मुझे आगे बोलने का आग्रह किया और मैंने यह भी बताया कि मुंगेर में एक प्रसिद्ध योग विश्वविद्यालय भी है।

प्रश्न 2 : क्या आप योग करते हैं?
उत्तर: जी, मैडम।

प्रश्न 3: बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है? क्या आपको लगता है कि आपके महिलाओं को राज्य में सशक्त बनाया गया है?
उत्तर: मैडम, हाल के वर्षों में बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए साइकिल योजना, राज्य में शराब पर प्रतिबंध आदि जैसी कई पहलें की हैं।

राज्य सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भी प्रदान किया है।

प्रश्न 4 : जवाबदेह सरकार का क्या अर्थ है?
उत्तर: मैडम, इसका आशय शासन के ऐसे तरीके से है जिसमें सरकार अपने नीतिगत निर्णयों के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रश्न 5 : सरकार की जवाबदेहिता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है?
उत्तर: मैडम, शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाकर सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है। वर्तमान में, नागरिकों की भागीदारी चुनाव के दौरान मतदान तक सीमित है। इसे परिवर्तित करना होगा। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया शासन में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है।

सदस्य 2

प्रश्न 1 : आपने सैमसंग में किस प्रोजेक्ट पर काम किया?
उत्तर: सर, मैं आईरिस ऑथेंटिकेशन पर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे जो दर्शक के मोबाइल स्क्रीन से दूर दिखने पर वीडियो को ऑटोमेटिक रूप से रोक देगा। यह आईरिस का उपयोग कर ऑथेंटिकेशन के विचार पर आधारित था।

प्रश्न 2 : भारत में R&D की स्थिति क्या है?
उत्तर: सर, वर्तमान में भारत R&D पर अपनी GDP के का करीब 0.5-0.6% भाग व्यय कर रहा है जोकि BRICS देशों की तुलना में बहुत कम है।

प्रश्न 3: जबकि हमारी बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो सकी हैं, तो ऐसे में अत्याधुनिक R&D की आवश्यकता क्या है?
उत्तर: सर, अत्याधुनिक R&D के अनुप्रयोग निचले स्तरों पर भी हैं। उदाहरण के लिए, सुपरकंप्यूटर का उपयोग कर उन्नत मौसम पूर्वानुमान फसल के नुकसान को रोकने में मदद कर सकता है। इसलिए हमें R&D पर दो-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सदस्य 3

प्रश्न 1: क्या हमें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत कानून बनाने चाहिए?
उत्तर: सर, मुझे लगता है कि दंड की गंभीरता से अधिक दंड की निश्चितता है जो अपराध को रोकती है। इसलिए, मुझे

लगता है कानून बनाने से कहीं ज्यादा उनका सुदृढ़ क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 2 : क्या दहेज के खिलाफ कानून पर्याप्त हैं? उनका दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? दहेज कानून में हालिया

बदलाव क्या है?

उत्तर: सर, दहेज से निपटने के लिए पर्याप्त कानून हैं। लेकिन इन कानूनों को सामाजिक जागरूकता अभियानों द्वारा पूरकता प्रदान करने की आवश्यकता है। यथा महिलाओं को उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मानव श्रृंखला अभियान। हालाँकि महिलाओं द्वारा गलत उद्देश्यों के लिए धारा 498A दुरुपयोग किया गया है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला स्तर पर परिवार कल्याण समितियों को स्थापित किया जाना चाहिए जो किसी भी पुलिस कार्रवाई से पहले दहेज से संबंधित शिकायतों की सत्यता की जाँच करेंगी।

प्रश्न 3: परिस्थिति-आधारित प्रश्न: मान लीजिए कि आपकी नौकरानी आपके पास आती है और अपने शराबी पति के बारे में शिकायत करती है जो शराब पीकर काम से घर आता है और उसे पीटता है। आप इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करेंगे? उत्तर: मैं पति के नियोक्ता से बात करूँगा और उसे कार्यस्थल पर पीने को प्रोत्साहित नहीं करूँगा। मैं उसके नियोक्ता को कार्यस्थल पर संवेदनात्मक सत्र आयोजित करने की सलाह दूँगा ताकि कर्मचारियों को शराब पीने के साथ जुड़ी हानियों के बारे में बताया जा सके। अगर इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो मैं घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज करने में पीड़िता की सहायता करूँगा।

सदस्य 4

प्रश्न 1: BHU का पुराना नाम क्या था?

उत्तर: मुझे पता नहीं है सर।

प्रश्न 2: इसकी स्थापना किसने की?

उत्तर: सर, इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी।

प्रश्न 3: BHU की स्थापना के लिए धन किसने दिया था?

उत्तर: बनारस के महाराजा, काशी नरेश ने मालवीय जी और एनी बेसेंट के आग्रह पर धन दिया।

प्रश्न 4: AMU की स्थापना किसने और कब की?

उत्तर: सर सैयद अहमद खान ने AMU की स्थापना की। मैं स्थापना के वर्ष के बारे में निश्चित नहीं हूँ।

प्रश्न 5: क्या आपको नहीं लगता कि अंग्रेजों ने एक हिंदू विश्वविद्यालय और एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में मदद करके विभाजन के बीज बोए?

उत्तर: सर, मैं आपके तर्क से सहमत हूँ। लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि आधुनिक शिक्षा उस समय की आवश्यकता थी।

प्रश्न 6: वाराणसी का नाम कैसे पड़ा?

उत्तर: वरुणा और असी नाम की दो नदियाँ इस शहर से होकर बहती हैं, इसलिए शहर को वाराणसी नाम दिया गया था।

प्रश्न 7: IIT बीएचयू क्यों अच्छा नहीं कर पा रहा है? (हिंदी में पूछा गया)

उत्तर: सर, यह सच है कि हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में IIT बीएचयू की रैंक में गिरावट आयी है। और कुछ अवसंरचनात्मक समस्याएँ भी हैं। फिर भी प्लेसमेंट के मामले में हम पुराने 5 IITs के समान ही प्रदर्शन कर रहे हैं। (हिंदी में जवाब दिया)।

प्रश्न 8: काशी इतना प्रसिद्ध क्यों है?

उत्तर: काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा के शांत घाट आदि के लिए काशी प्रसिद्ध है। सदियों से काशी को ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता है जहाँ लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के अंतिम हिस्से में आते हैं।

प्रश्न 9: पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति क्या है?

उत्तर: तीसरी औद्योगिक क्रांति इंटरनेट से सम्बंधित है। दस्य ने यह कहते हुए बाधा डाली, "नहीं, तुम गलत हो!" मैंने जवाब दिया, "क्या मैं सही जवाब जान सकता हूँ, सर?"

मुझे बताया गया कि तीसरी औद्योगिक क्रांति कंप्यूटर से संबंधित थी। मैंने सदस्य का धन्यवाद किया और कहा कि दूसरी औद्योगिक क्रांति बिजली और स्टीम इंजन के साथ संबंधित थी। इसके बाद, मुझे अध्यक्ष ने बताया कि मेरा साक्षात्कार खत्म हो गया। मैं खड़ा हुआ, पहले अध्यक्ष का धन्यवाद किया और फिर सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। मैंने मिश्रित भावनाओं के साथ कमरे छोड़ दिया। मेरे अवलोकन: मैंने बोर्ड को सौहार्दपूर्ण पाया। मुझे अंतिम सदस्य से थोड़ा डर लगा। मेरी हॉबी पर कोई सवाल नहीं पूछा गया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया कि आईपीएस पहली प्राथमिकता क्यों है! मैं उन प्रश्नों को संभालने के तरीके पर अच्छी तरह से तैयार था। मैंने पुलिस सुधारों, पुलिस व्यवस्था में मुद्दों आदि के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन यूपीएससी कई बार अप्रत्याशित होता है। परिणाम बाहर हैं। मैंने साक्षात्कार में 167 अंक प्राप्त किये और सिविल सेवा परीक्षा 2017 में अखिल भारतीय रैंक 13 प्राप्त की।

► उम्मीदवारों को ध्यान भटकने की समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए? चूंकि एकसमान लय बनाये रखना अधिकांश उम्मीदवारों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और उनमें स्थिरता की कमी होती है।

एक उम्मीदवार को सोशल मीडिया से बाहर रहना चाहिए। एकाग्रता को बनाए रखने के लिए योग, ध्यान आदि करना उचित है। खेल और संगीत पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

► क्या आप पाठकों के साथ उन लोगों के बारे में जानकारी साझा करना चाहते हैं जो आपके शानदार प्रदर्शन के पीछे हैं? जैसे पारिवारिक सदस्य, दोस्त, शिक्षक, सलाहकार इत्यादि। मैं जीएस पेपर IV के लिए पवन कुमार सर और गणित के लिए वेंकन्ना सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे माता-पिता और मेरे परिवार ने असफलताओं पर काबू पाने में मुझे बहुत मदद की। यहाँ मेरे पिता का उल्लेख करने की ज़रूरत है क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो यह समझ सकते थे कि मैं दो अंकों में रैंक सुरक्षित करूँगा।

► क्या आपने परीक्षा के लिए अपनी तैयारी के दौरान Study IQ प्लेटफॉर्म से लाभ उठाया था?

मैं StudyIQ प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल से करेंट अफेयर्स के वीडियो देखा करता था। मुझे इससे फायदा हुआ।

धन्यवाद

सागर कुमार झा

AIR 13, CSE 20

अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के तेल पर भारत को छूट प्रदान की गयी

सन्दर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के तेल आयात पर भारत समेत 8 देशों को छूट दी है। इसने अगले 6 महीनों के लिए अपने प्रतिबंधों पर रोक लगा दी है।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के साथ ओबामा प्रशासन द्वारा प्रस्तावित संधि से स्वयं को अलग कर लिया है। इसका पूरा विश्लेषण वीडियो से देखा जा सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आरोपित प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान को CAATSA अधिनियम (कॉउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट) में सूचीबद्ध करना तथा उसे वैश्विक व्यापार से अलग-थलग करना था। इस सन्दर्भ में पूरी जानकारी उल्लिखित शीर्षक के वीडियो में है।

अमेरिका ने खत्म की ईरान से डील



प्रतिबंधों की मूल बातें:

प्रतिबंधों के दो सेट - पहला सेट

- ईरान द्वारा अमेरिकी मुद्रा की खरीद
- सोने और अन्य कीमती धातुओं में ईरान का व्यापार
- ऑटो पार्ट्स, वाणिज्यिक यात्री विमान, और संबंधित पार्ट्स और सेवाओं को ईरान को बेचना।

दूसरा सेट:

- 5 नवंबर से शुरू
- ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री को
- प्रतिबंधित करता है।
- अगर कोई देश, या कंपनी, अमेरिका की सहमति के बिना
- ईरान के साथ व्यापार करती है तो उसे अमेरिकन वित्तीय
- प्रणाली से निकाले जाने का खतरा रहेगा।

भारत-ईरान के संबंध

भारत ईरानी तेल का एक प्रमुख आयातक है। 2017-18 में भारत द्वारा आयातित 220.4 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल में से 9% से अधिक ईरान से था। भारत ने 2017-18 में ईरान से लगभग 22 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया था और 2018-19 में इसे 30 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई थी।

ट्रम्प प्रशासन आठ देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी सीमित मात्रा में ईरानी तेल आयात करने की अनुमति देगा।

आठ देश

चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, तुर्की, इटली, संयुक्त अरब अमीरात और जापान ईरान के तेल के शीर्ष आयातक रहे हैं। हालाँकि ताइवान कभी-कभी ईरानी कच्चे तेल के कार्गो खरीदता है लेकिन यह एक प्रमुख खरीदार नहीं है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री ने रिपोर्टर को बताया है कि इराक की तरह उसे भी अस्थायी रूप से ईरानी तेल खरीदने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह ईरान को अमेरिकी डॉलर में भुगतान न करे।

प्रमुख लाभ:

इस छूट से दो सबसे बड़े ईरानी तेल उपभोक्ताओं, इंडियन आयल तथा मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) को बड़ी राहत मिलेगी। दोनों कंपनियों ने एक साथ नवंबर में ईरान से 1.25 मिलियन कच्चे तेल का आर्डर दिया है।

स्विफ्ट (SWIFT) वित्तीय संदेश सेवा

यू.एस. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूनचिन ने यह भी कहा कि वाशिंगटन ने ब्रुसेल्स स्थित SWIFT वित्तीय संदेश सेवा (SWIFT financial messaging service) को बताया था कि इसके द्वारा उन सभी वित्तीय संस्थानों को अलग करने की उम्मीद की गयी थी जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ब्लैकलिस्ट करने की योजना बनायी जा रही है।

शर्तें:

लेकिन, छूट की शर्त के रूप में, भारतीय तेल कंपनियां अपने आयात में महत्वपूर्ण कटौती करेंगी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कहा है कि वह केवल अस्थायी छूट जारी कर रहा है और शर्त यह है कि जिन देशों को यह छूट मिल रहा है वे ईरान से अपनी खरीददारी कम करते रहेंगे।

नोट्स

अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध

चीन और
पाकिस्तान
बस सर्विस पीओके
से होते हुए

(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

सन्दर्भ:

काशगर (चीन) और लाहौर (पाकिस्तान) के बीच पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते से पाकिस्तान-चीन बस सेवा आरम्भ की गई है। भारत ने इसका सशक्त विरोध किया है।

CPEC के कार्य

- इस बस का प्रस्तावित मार्ग बहुचर्चित चीन पाकिस्तान इकनोमिक कॉरिडोर से होकर जाता है।
- लाहौर (पाकिस्तान) और काशगर (ताशकुरगन, चीन) बस सेवा के अंत बिंदु होंगे।
- लाहौर से प्रस्थान के दिन शनि-रवि-सोम-मंगलवार होंगे, जबकि मंगलवार-गुरुवार-शुक्रवार ताशकुरगन से प्रस्थान के दिन होंगे।
- यात्रा की लागत 13,000 पाकिस्तानी रुपया एक तरफ से और दोनों तरफ से 23,000 पाकिस्तानी रुपया है।
- पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम (पीटीडीसी) और शुजा एक्सप्रेस, बस सेवा के दो उद्यम भागीदार हैं।
- 5 स्टॉपओवर, 15 सीटों वाली बस, खंजरब, चीन में क्रॉसिंग और सेवा में वैध वीजा और आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। साथ ही दोनों तरफ से 36 घंटे का समय लगेगा।
- हुमायूं इकबाल शामी - चीन-पाकिस्तान आर्थिक मंच के अध्यक्ष।

भारत से कोई सहमति नहीं:

इस बस का प्रस्तावित मार्ग बहुचर्चित चीन पाकिस्तान इकनोमिक कॉरिडोर से होकर जाता है। लाहौर (पाकिस्तान) और काशगर (ताशकुरगन, चीन) बस सेवा के अंत बिंदु होंगे।

लाहौर से प्रस्थान के दिन शनि-रवि-सोम-मंगलवार होंगे, जबकि मंगलवार-गुरुवार-शुक्रवार ताशकुरगन से प्रस्थान के दिन होंगे।



नोट्स

अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2018
और आसियान शिखर सम्मेलन 2018

UPSC के दृष्टिकोण से: UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019

नवम्बर 2018 में क्या हुआ था?



प्रधानमंत्री की सिंगापुर की यात्रा

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी सिंगापुर यात्रा का समापन किया तथा 33वें आसियान (Association of

Southeast Asian Nations: ASEAN) सम्मेलन, 13 वें ईस्ट एशिया सम्मेलन तथा व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी समझौता (RCEP) के साथ ही आसियान-भारत सम्मेलन में भागीदारी की।

आसियान सम्मेलन, नवंबर 2018

► आसियान सम्मेलन अर्ध-वार्षिक (वर्ष में दो बार होता है) बैठक है।

► यह 33 वें आसियान सम्मेलन था।

30th	28-29 April 2017	Philippines	Pasay
31st	10-14 November 2017	Philippines	Pasay
32nd	27-28 April 2018	Singapore	Singapore
33rd	11-15 November 2018	Singapore	Singapore
34th	April/May 2019	Thailand	TBA
35th	October/November 2019	Thailand	TBA

33 आसियान सम्मेलन



Theme: Resilient And Innovative

आसियान के बारे में

- एसोसिएशन ऑफ़ साउथईस्ट एशियन नेशंस अथवा आसियान की स्थापना 1967 में आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई।
- इसके सदस्य इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस हैं।

भारत-आसियान

- 33 वें आसियान सम्मेलन के दौरान, भारत-आसियान सम्मेलन भी आयोजित किया गया था।
- रणनीतिक साझेदार के रूप में, भारत और आसियान के व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं।
- 2017-18 में भारत और आसियान के बीच 81 अरब डॉलर का व्यापार हुआ जोकि भारत के कुल व्यापार का 10% है। आसियान देशों का निर्यात भारत के कुल निर्यात का 11% है।
- भारत और आसियान की आबादी 1.9 बिलियन है, जो दुनिया की आबादी का एक चौथाई हिस्सा है। इसके साथ ही दोनों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पादन 5 ट्रिलियन डॉलर का है।
- 2017 में, भारत और आसियान ने अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों की 25वीं वर्षगांठ मनाई तथा इस उपलक्ष्य में भारत-आसियान स्मारक सम्मेलन 25 जनवरी, 2018 को आयोजित किया गया था।
- आसियान के साथ भारत के संबंध संस्कृति, वाणिज्य और संयोजकता (Culture, Commerce and Connectivity) द्वारा चिह्नित हैं।

13 वां ईस्ट एशिया सम्मेलन

- भारत ने 13 वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया।
- ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन (स्थापित: 2005) क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों का एक मंच है।
- ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों में 10 आसियान राष्ट्र (इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस) तथा 8 अन्य सदस्य- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं।

13th East Asia Summit #ASEAN2018



2nd Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Summit



- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी
- यह आसियान सदस्यों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम) और छह एशिया-प्रशांत राज्य (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, और न्यूजीलैंड) जैसे देशों के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते का विचार है।
- कुछ देशों को बाजार पहुंच के संदर्भ में मुक्त व्यापार समझौते के तहत एकजुट होना चाहिए और बाजार के संदर्भ में सभी सीमाओं को कम करना चाहिए।
- RCEP के तहत कोई भी देश अपने उत्पाद को किसी अन्य देश में न्यूनतम टैरिफ में बेच सकता है।
- RCEP एक क्रांतिकारी विचार है और जब यह सफल होगा, तब सम्बंधित देशों की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक भाव होगा जो आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा।

तीसरी चतुर्पक्षीय (काड) बैठक (अनौपचारिक समूह)

- यह चार लोकतंत्रों का समूह है- भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान।
- यह उन सदस्यों का चतुर्पक्षीय समूह है जोकि एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र तथा नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को सुनिश्चित करने तथा इसे समर्थन देने का साझा उद्देश्य रखते हैं।

- संयोजकता, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्षा 'क्लाड' देशों की तीसरी बैठक में बातचीत के केंद्रबिंदु थे।
- अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में "नियम-आधारित व्यवस्था" पर जोर दिया, जोकि भारतीय बयान में अनुपस्थित था।
- श्रीलंका और मालदीव पर एक गंभीर चर्चा हुई। ये दोनों भारत के निकटस्थ पड़ोसी और चीन के विस्तारवाद से प्रभावित हैं।

ट्रम्प अनुपस्थित क्यों थे?

- अमेरिकी राष्ट्रपति की एशियाई राष्ट्रों के साथ असम्बद्धता, उनके विश्व युद्ध के एक समारोह के लिए की गयी फ्रांस यात्रा के कुछ दिन बाद ही देखी गयी। वहां भी वे नाटो सहयोगियों से अलग-थलग दिखाई दिए।
- सिंगापुर में होने वाले आसियान तथा पूर्वी एशियाई देशों के संगठनों के सम्मेलन में अनुपस्थित रहने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा पापुआ न्यू गिनी में होने वाले एशिया पैसिफिक इकनोमिक कोऑपरेशन (APEC) फोरम की बैठक में भी प्रतिभाग नहीं करेंगे।

संदेह

- ट्रम्प ने 2017 में आसियान और APEC दोनों बैठकों में भाग लिया था। ऐसे में इस वर्ष दूर रहने के उनके निर्णय ने चीन से निपटने की क्षेत्रीय रणनीति के सन्दर्भ में वाशिंगटन की प्रतिबद्धता के बारे में प्रश्न उठाए हैं।
- सिंगापुर में ट्रम्प का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराष्ट्रपति माइक पेन्स ने बैठक में बताया कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता "दृढ़ और स्थायी" है।

नोट्स

अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध

भारत पर भूटान चुनाव का प्रभाव



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से

मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2: अंतराष्ट्रीय संबंध- भारत के हित में विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति के प्रभाव

भूटान

- भूटान दक्षिण एशिया में एक स्थलरुद्ध (लैंडलाक) देश है।
- चीन के साथ कम संपर्क।
- भारत से अधिक जुड़ाव।
- भूटान एक संवैधानिक राजशाही है (राजा के पास शक्ति है, लेकिन संविधान तक ही सीमित है।)
- सरकार एक संसदीय लोकतंत्र है; राज्य का मुखिया भूटान का राजा है, जिसे "ड्रैगन किंग" के नाम से जाना जाता है।
- भूटान संयुक्त राष्ट्र, सार्क, बिस्मटेक और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है।
- संवैधानिक राजतंत्र
- एक संवैधानिक राजशाही ऐसी राजशाही होती है जिस में राजा की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं।
- जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक वर्तमान में सत्तारूढ़ डुक ग्याल्पो या भूटान साम्राज्य के "ड्रैगन किंग" है।



भूटान में चुनाव

संसद - ची त्सोग के दो सदन हैं

- नेशनल काउंसिल (Gyelyong Tshogde) ऊपरी सदन।
- नेशनल असेंबली (Tshogdu) निम्न सदन, दोनों पांच साल की अवधि के साथ।

भूटान संसद के बारे में

- नेशनल काउंसिल में 25 सदस्य हैं जिनमें से 20 चुने जाते हैं जबकि पांच राजा द्वारा मनोनीत होते हैं। उम्मीदवार निर्दलीय रूप में परिषद चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में नहीं।
- हालाँकि नेशनल असेंबली में सदस्य पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ते हैं। इसमें 47 सदस्य होते हैं।

भूटान के दल

- तोबो के नेतृत्व में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भारत को "हमारे निकटतम पड़ोसी और मित्र" के रूप में वर्णित किया और कहा कि वे नई नई दिल्ली (प्रो इंडिया पार्टी) के साथ और जुड़ाव सुनिश्चित करेंगे।
- डॉ पेमा ग्यामशो के डुक फुएनसमशोग्पा (डीपीटी) का अपने मैनिफेस्टो में कहना है कि यह आर्थिक संबंधों को गहरा कर और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाकर उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

► हालांकि, कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं कि डीपीटी की "संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता" का दृष्टिकोण अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय हितों को संदर्भित करता है।

भूटान 2018 चुनाव विजेता

► केंद्र-वामपंथी डीएनटी, जो भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत और विविधता प्रदान करने हेतु प्रयासरत है, ने भूटानी संसद के निचले सदन 47 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 30 सीटें जीती हैं।

डीएनटी के दृष्टिकोण में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ाने के लिए भूटान की संस्कृति को बढ़ावा देना, और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल था। भूटान में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कमी से निपटने के लिए महिलाओं को बाल देखभाल और मातृत्व लाभ भी पेश करने की योजना थी। हालांकि, घोषणापत्र में विदेशी नीति के मुद्दों का कोई उल्लेख नहीं था।

भूटान के नये प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के नव निर्वाचित प्रधान मंत्री लोटयेशेरिंग (डुक न्यामप्रशोम्पा पार्टी के अध्यक्ष) को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी।



भारत के लिए चुनाव परिणाम का महत्व

► भारत के लिए, भूटानी चुनावों का विशेष महत्व है, क्योंकि नई दिल्ली के थिम्फू के साथ बहुत करीबी संबंध हैं (खासकर चीन की भागीदारी और डोक्कलम स्टैंडऑफ के संदर्भ में)।
► भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 79 दिनों के डोक्कलम गतिरोध को ध्यान में रखते हुए, भूटान के प्रधानमंत्री का झुकाव महत्वपूर्ण है।

भारत से भूटान की आशा

► सारी अटकलों को समाप्त करते हुए, भावी प्रधानमंत्री लोटेटी शेरिंग, ने एक मीडिया साक्षात्कार में कहा "हमारे [डीएनटी] विचार विदेश नीति पर बहुत स्पष्ट हैं और हम मानते हैं कि यह हर पांच साल में नहीं बदले जा सकते।"
► हमारे राजा (जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक) का विदेशी नीति के मामलों पर मार्गदर्शक बल होगा ... और भारत पर, हम मानते हैं कि भूटान-भारत संबंध गैर-विचारणीय है।"

भूटान- भारत तनाव

भूटानी अर्थव्यवस्था के लिए जलविद्युत परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं और आत्मनिर्भरता के लिए भूटान की योजनाओं के केंद्र में हैं।

जुलाई 2017 तक, भूटान के तीन प्रमुख चल रही परियोजनाओं के लिए भारत का कर्ज:

मांगदेछो, पुनातसंगछू 1 और 2 पर लगभग 12,300 करोड़ रुपये हैं जो देश के कुल ऋण का 77% है, और इसके सकल घरेलू उत्पाद का 87% है।

जबकि पिछले दो सालों में 720 MW मांगदेछो परियोजना की लागत लगभग दुगुनी हो गई है। इसी प्रकार पुनातसंगछू 1 और 2, जोकि प्रत्येक 1200 MW की हैं, की लागत तीन गुनी हो गई है और ये अपने निर्धारित समय से 5 वर्ष पीछे हैं।

नोट्स

अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध

भारत कोसोवो विवाद



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से

मुख्य प्रश्नपत्र 2:

अंतराष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते

हाल ही में क्या हुआ?

► भारत ने AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कोसोवो की मुक्केबाज डोनजेता सादिकु को वीजा देने से इनकार कर दिया।

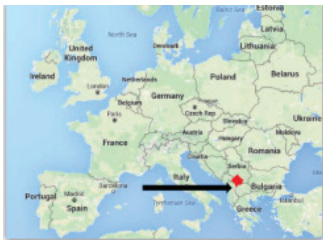
► इसके बाद ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया (ओसीए) के अध्यक्ष ने खेल मंत्री और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लिखा वीजा का रद्द हो जाना अंतराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए भारत की योग्यता पर संदेह प्रकट करता है।

► इसके उपरांत, एआईबीए ने धमकी दी कि वह 2021 एआईबीए पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए मेजबान के रूप में भारत पर पुनर्विचार करेगा।



कोसोवो का इतिहास

- एक समय में, कोसोवो सर्बियाई साम्राज्य का केंद्र था। 1398 में ओटोमैन से हार के बाद सर्बिया ने इसे खो दिया था।
- सदियों बाद, 1912 में, सर्बिया ने कोसोवो पर नियंत्रण कर लिया और 1946 में, कोसोवो युगोस्लाव संघ का हिस्सा बन गया।
- 1960 के दशक के दौरान, कोसोवो ने बहुसंख्यक-ईसाई संघ में सदियों के तुर्क शासन के बाद बहुमत-मुस्लिम प्रांत होने के नाते अपनी स्वायत्तता पर जोर देना शुरू किया।
- युगोस्लाव संघ ने 1980 के दशक में इस स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया, जिससे कोसोवो को 'डी फैक्टो सेल्फ गवर्नमेन्ट' का अधिकार मिला।
- 1998-99 से कोसोवो में कटुतापूर्ण और घातक युद्ध छिड़ गया जहाँ हजारों लोगों की मृत्यु हुई। यह युद्ध बड़े पैमाने पर सर्व और अल्बानी नृजातीय समूह के लोगों के बीच लड़ा गया था।
- इस संघर्ष में बड़े पैमाने पर हत्याएँ और बदले की भावना से हिंसक घटनाएँ की गयीं।
- अंत में नाटो ने युगोस्लाविया के खिलाफ हस्तक्षेप किया, और युद्ध को समाप्त करने के लिए 1999 में कुमानोवो समझौता किया गया।

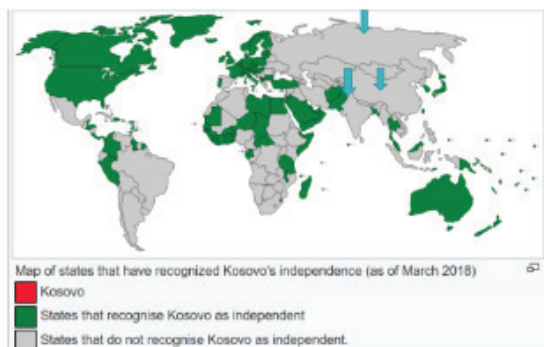


कोसोवो

- 2008 में, कोसोवो ने सर्बिया से अपनी आजादी की घोषणा की, जिसे सर्बियाई सरकार ने संक्षेप में खारिज कर दिया था।
- जबकि सर्बिया कोसोवो की निर्वाचित सरकार द्वारा क्षेत्र के प्रशासन को मान्यता देती है, लेकिन यह इस पर अपने स्वयं के स्वायत्त प्रांत कोसोवो और मेटोहिजा के रूप में दावा करती है।

कोसोवो की अंतरराष्ट्रीय मान्यता

1 नवंबर 2018 तक, कोसोवो गणराज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में 116 राजनयिक मान्यताएं मिली हैं।



गहरे हरे भाग के राज्य- वे देश जो कोसोवो को स्वतंत्र मानते हैं। ब्रिक्स देश कोसोवो का एक स्वतंत्र देश के रूप में समर्थन नहीं करते हैं।

सिद्धांतों का पालन करना

- भारत के लिए, यह मुद्दा सिर्फ एक छोटे यूरोपीय राष्ट्र कोसोवो से कहीं अधिक है।
- यह एक लंबे और कड़े सिद्धांत के बारे में है कि भारत संप्रभुता को प्रिय मानता है और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है।
- 2008 में सर्बिया से खुद को स्वतंत्र घोषित करने के बावजूद भारत द्वारा कोसोवो को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक के रूप में, भारत की विदेश नीति इन सिद्धांतों का पालन करती है: अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और अपने मुद्दों में हस्तक्षेप न करने की अपेक्षा; क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान; आपसी गैर आक्रामकता; और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।

भारत के लिए जटिलताएँ

- उत्तर में एक संघर्षग्रस्त कश्मीर, जहाँ 'आज़ादी' का रोना नियमित रूप से सुनाई देता है, और कुछ कुछ समय में खालिस्तान संघर्ष।
- भारत इस सिद्धांत पर बल देने के लिए अनिच्छुक है कि एक संप्रभु राष्ट्र के भीतर के क्षेत्र इच्छा से अलग हो सकते हैं।
- भारत को डर है कि ऐसा करने से उसे दोमुंहा आचरण करने वाला समझा जायेगा अर्थात् यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि आप किसी और देश में खुद को स्वतंत्र कर देने के अधिकार को मान्यता देते हैं तो कश्मीर/खालिस्तान के मसलों में क्यों नहीं?

विवाद से बचने के लिए भारत क्या कर सकता था?

- भारत के पास लंबे समय से चलने वाले विदेशी नीति सिद्धांतों को पीछे छोड़ने का पर्याप्त कारण नहीं है जिसे यह अन्य देशों के साथ अपनी बातचीत का आधार बनाता है।
- भारत को भविष्य की सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी छोड़ देने की आवश्यकता नहीं थी।
- हमें (चीन की तरह) बॉक्सर को उसके पासपोर्ट में एक पेपर के टुकड़े पर स्टेपल वीजा दे देना चाहिए था।

नोट्स

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

पाकिस्तान - आसिया बीबी मामला



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

आसिया बीबी मामला क्या है?

आसिया बीबी पाकिस्तान की एक ईसाई नागरिक है जिसको पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने 2009 के ईशनिंदा मामले से बरी कर दिया है। उसे बरी किये जाने के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान में अनेक चरमपंथी समूहों ने उसे सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड देने की मांग की है और विद्रोही रुख अपना लिया है।

बरी किये जाने के निर्णय की प्रस्तावना

आसिया बीबी (असली नाम- आसिया नौरीन) 47 साल की एक ईसाई महिला है जो पाकिस्तान में खेतों में काम करती है। आसिया का कहना है कि उसके इलाके की तीन मुसलमान महिलाओं ने कथित रूप से एक बर्तन से पानी पीने से इंकार कर दिया क्योंकि वह बर्तन ईसाईयों द्वारा प्रयोग किया जाता था। इससे आसिया और उन तीन औरतों के बीच मौखिक विवाद होने लगा। उन तीन औरतों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आसिया बीबी द्वारा पैगम्बर मोहम्मद का उपहास उड़ाया गया। यह मौखिक विवाद स्थानीय इलाके में फैल गया, स्थानीय लोगों ने आसिया के घर में हंगामा किया और उसे धमकाया। आखिरकार, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और 2010 में एक निचली अदालत ने उसे पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 295-C के अंतर्गत मौत की सजा सुनाई।

पाकिस्तान में, ईशनिंदा के मामले में, मृत्यु की सजा अनिवार्य है। 2014 में लाहौर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के मृत्युदंड के फैसले को बरकरार रखा।

इसी दौरान

कई ईसाई संगठनों और समूहों ने इस निर्णय को तर्कहीन बताया और पाकिस्तानी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की। पोप फ्रांसिस ने भी पाकिस्तानी सरकार के हस्तक्षेप का अनुरोध किया। 2011 में पंजाब के गवर्नर, सलमान तासीर ने भी इस फैसले को तर्कहीन बताया। उन्होंने आसिया का समर्थन किया और ईशनिंदा कानून पर अदालत को पुनः विचार करने को कहा। उनके आवाज़ उठाने का परिणाम यह हुआ कि उनके अपने गार्ड मुमताज़ कादरी ने उनकी हत्या कर दी। मुमताज़ कादरी को 2016 में दोषी ठहराया गया और मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन, उसे कई चरमपंथियों और धार्मिक चरमपंथियों द्वारा एक शहीद के रूप में सम्मानित किया गया। इस्लामाबाद में उसके लिए बनी मज़ार पर लाखों लोग जा चुके हैं।

आसिया बीबी के समर्थन में आवाज़ उठाने पर 2011 में

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, शाहबाज भट्टी की भी हत्या कर दी गई।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

काफी लम्बे समय के बाद, उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों: न्यायमूर्ति असिफ सईद खोसा और न्यायमूर्ति मजहर आलम ने 31 अक्टूबर 2018 को आसिया को ईशनिंदा के आरोप से बरी कर दिया। न्यायमूर्ति खोसा ने न्याय के दौरान पवित्र कुरान की कुछ आयतें पढ़ीं और कहा "सहिष्णुता इस्लाम के मूल सिद्धांतों में से एक है। आप (धार्मिक चरमपंथी) मुझे भी मार सकते हैं, मैं आपके लिए एक आसान लक्ष्य हूँ।"

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद

जमात-उद-दावा (आतंकवादी हाफिज़ सईद के नेतृत्व में) और जमात-उल्लेमा-ए-इस्लाम सहित पाकिस्तान के अनेक चरमपंथियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को गलत बताया और विरोध करना शुरू कर दिया। इससे पाकिस्तान में अराजकता और संघर्ष की शुरुआत हो गयी। इन चरमपंथियों द्वारा अपने समर्थकों से न्यायमूर्ति खोसा और न्यायमूर्ति आलम की हत्या करने और आसिया बीबी को सार्वजनिक रूप से सजा-ए-मौत देने की अपील की है।

पाकिस्तान सरकार की कायरता: आसिया बीबी के रिहा होने पर उनके पाकिस्तान छोड़ के चले जाने की पहले से ही उम्मीद थी। उसके पति असिफ मसीह और उनकी दो बेटियों ने पहले से ही लंदन में शरण ले रखी है और वे आसिया के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 नवम्बर 2018 को, पाकिस्तान की सरकार और तहरीक-ए-लब्बाइक नामक इस्लामी राजनीतिक दल, जिसने आसिया बीबी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, ने समझौता किया कि आसिया बीबी पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकतीं। इस समझौते के अनुसार, आसिया बीबी को एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) पर रखने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो किसी भी व्यक्ति को देश छोड़ने से प्रतिबंधित करती है।

नोट्स

अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध

सॉफ्ट स्टेट क्या है?



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

'सॉफ्ट स्टेट' क्या है? भारत के लिए एक छद्म नाम?

यूपीएससी प्रासंगिकता - GS प्रश्नपत्र -2

सॉफ्ट स्टेट क्या है?

दक्षिण एशियाई देशों की तुलना यूरोप से करते हुए गुनार मर्डल ने अपनी पुस्तक 'एशियाई ड्रामा' में यह शब्द ईजाद किया था। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि दक्षिण एशियाई देश सॉफ्ट स्टेट की नीति का पालन करते हैं। सॉफ्ट स्टेट की नीति 'सामाजिक विचलन' की ओर एक उदार दृष्टिकोण का दावा करती है। सामाजिक विचलन का उदाहरण बलात्कार, हत्या, अपराध, विरूपण आदि हो सकता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि ये कर्म या गतिविधियां सामाजिक मानदंडों के साथ अभिसरण में नहीं हैं। सॉफ्ट स्टेट से आशय है, इस तरह की सरकार जो बलात्कार, अपराध और अन्य सामाजिक विचलन पर कठिन निर्णय नहीं लेती है, जबकि कभी-कभी वे बहुत अनिवार्य हो जाते हैं। सॉफ्ट स्टेट की नीति कानून के शासन को लागू करने में राज्य की क्षमता को कमजोर करती है। कठिन निर्णय ना लेने से अपराध दर, हिंसा, भ्रष्टाचार इत्यादि बढ़ जाता है। हर देश में कानून की आवश्यकता है और संस्थाएं उन नियमों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। 'कानून का शासन' हमेशा 'व्यक्ति के/वैयक्तिक शासन' पर प्रबल होना चाहिए।

भारत का परिप्रेक्ष्य:

भारत में, स्वतंत्रता अवधि के बाद से इस नीति का पालन किया जा रहा है। आजादी के बाद, और विशेष रूप से 1990 के बाद ज्यादातर सरकारें अन्य दलों के साथ गठबंधन में

आई। गठबंधन में, सरकार कभी-कभी दूसरी पार्टी को खुश करने के लिए एक उदार दृष्टिकोण का दावा करती है, जो सामाजिक विचलन का कारण बन सकती है, और अंततः वह देश एक सॉफ्ट स्टेट बन जाता है। कई अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के अनुसार 10 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की वजह से भारत धीरे-धीरे सॉफ्ट स्टेट में बदल रहा है। मर्डल ने कहा कि प्रभावी सरकारें कानूनों और नियमों के सख्त प्रवर्तन का पालन करती हैं।

आंतरिक मुद्दे: अंग्रेजों ने उन नियमों और कानूनों की शुरुआत कर क्रियान्वयन किया जो औपनिवेशिक युग के दौरान उनके निहित हितों के अनुकूल थे। लेकिन, स्वतंत्रता के बाद भी, यह देखा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में सरकार नियमों और कानूनों को लागू करने में सक्षम नहीं है। कुछ आधार पर, लोग स्वयं 'नियम' स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, वास्तव में, वे मौजूदा 'सामाजिक मानदंड' पर ही चला चाहते हैं। कुछ उदाहरण जातिवाद, दहेज, मादा भ्रूण हत्या, या यहां तक कि वर्तमान सबरीमाला भी हो सकते हैं।

बाहरी मुद्दे: भारत के समक्ष आतंकवाद एक महत्वपूर्ण समस्या है और इस सन्दर्भ में भारत द्वारा कुछ कठोर कार्यवाहियां की जानी आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, नक्सलवाद भारत में एक विकराल समस्या बन गया है। भारत में लोगों का एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो नक्सलवाद के साथ सहानुभूति व्यक्त करता है।

इससे पहले के समय में:

इससे पूर्व 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने कुछ कठोर निर्णय लिए थे। पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाने के उपरांत, प्रधानमंत्री ने कठोर रुख अपनाया तथा बांग्लादेश के निर्माण में सहायता की; 1975 में सिक्किम का भारत में विलय सुनिश्चित किया तथा पंजाब के अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन का दमन किया।

अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध

अमेरिका जन्मसिद्ध अधिकार नागरिकता मुद्दा



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

ट्रम्प द्वारा अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह 'राष्ट्रपति कार्यकारी आदेश' द्वारा जन्मजात अमेरिकी नागरिकता के अधिकार को समाप्त कर देंगे। यह नागरिकता उन बच्चों को दी जाती है जिनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यक्षेत्र में होता है। उदाहरण - अगर एक गैर-अमेरिकी महिला गर्भवती है और वह किसी भी उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका जाती है और वहां बच्चे का जन्म होता है तो वह महिला उस नवजात शिशु की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है। ट्रम्प नागरिकता के इस प्रावधान को समाप्त करना चाहते हैं।

प्रावधान के लिए प्रस्तावना:

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

- यह कानून 14वें संविधान संशोधन पर आधारित है जिसकी पुष्टि राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के कार्यकाल में 9 जुलाई 1968 को की गयी।
- इस संशोधन का उद्देश्य मुख्य रूप से उन अश्वेत अमेरिकियों को नागरिकता देना या आश्रय देना था जो दासों के बच्चे थे। इसके साथ ही इसका लक्ष्य उन दासों को भी नागरिकता प्रदान करना था जिन्हें अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद मुक्त कराया गया था।
- इसके अनुसार, "संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके अधीन क्षेत्रों में जन्म लेने वाले अथवा देशीयकृत सभी व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका के तथा उस राज्य के नागरिक होंगे जहाँ वे निवास करते हैं। कोई भी राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण अथवा प्रवर्तन नहीं करेगा जोकि संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को प्राप्त उन्मुक्तियों अथवा विशेषाधिकारों में कमी करता हो।"

यूपीएससी प्रासंगिकता - GS प्रश्नपत्र -2

Jus Soli और Jus Sanguinis:

संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता हर उस व्यक्ति को स्वचालित रूप से मिलती है जो अमेरिका में और उसके अधिकार क्षेत्र में जन्म लेता है। (इसे jus soli कहा जाता है।)

जन्मजात नागरिकता, अमेरिकी नागरिकों के उन बच्चों पर भी लागू होती है जो अमेरिका के अलावा दुनिया में कहीं और जन्म लेते हैं। (इसे jus sanguinis कहा जाता है।)

Jus soli एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ भूमि का कानून होता है। अनेक देश jus soli प्रणाली का पालन करते हैं और आमतौर पर इसे जन्मजात नागरिकता के नाम से जाना जाता है।

उन देशों के नाम जो Jus Soli का पालन करते हैं:

- अर्जेंटीना
- बारबडोस
- ब्राजील
- कनाडा
- जमैका
- मेक्सिको
- पाकिस्तान
- पेरू
- रोमानिया
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- उरुग्वे

Jus Sanguinis: भारतीय राष्ट्रीयता कानून बड़े पैमाने में jus soli के विपरीत jus sanguinis (रक्त के आधार पर नागरिकता) का पालन करता है। इसके अंतर्गत बच्चे पैदा होते ही नागरिक बन जाते हैं यदि उनके माता पिता के पास राष्ट्र की नागरिकता या नृजातीय, सांस्कृतिक या अन्य मूलों की राष्ट्रीय पहचान हो।

Jus Soli और Jus Sanguinis का मिश्रण:

अमेरिका, कनाडा, इजराइल, ग्रीस, रिपब्लिक ऑफ़ आयरलैंड और जर्मनी।

भारत का नियम- भारत में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता प्रदान करने के लिए बच्चे के माता पिता में कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से- प्रारंभिक परीक्षा

सेशेल्स का ब्लू बॉण्ड

सेशेल्स गणराज्य ने 29 अक्टूबर 2018 को दुनिया का पहला 'सॉवरेन ब्लू बॉण्ड' लॉन्च किया। यह एक वित्तीय उपकरण है जिसको संधारणीय समुद्री और मत्स्य पालन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सेशेल्स के बारे में:

- सेशेल्स कई द्वीपों से बना एक द्वीपसमूह है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का एक भाग है।
- यूके से स्वतंत्रता 19 जून 1976 को मिली।
- राजधानी- विक्टोरिया
- नृजातीयता - क्रियोल्स (93.2%)
- मुद्रा- सेशेलोइस रुपया (एससीआर)
- राष्ट्रपति- डैनी फौरे

इस बॉण्ड ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से 15 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। यह बॉण्ड समुद्री संसाधनों के संधारणीय उपयोग के वित्तपोषण के लिए पूंजी बाजारों का उपयोग करने की देशों की क्षमता को दर्शाता है। ब्लू बॉण्ड जारी करने के साथ, सेशेल्स इस नए तरह के वित्त पोषण उपकरण की खोज करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है।

पर्यटन उद्योग में तेज़ी

2011 में प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी प्रिंसेस केट के इस द्वीपीय राष्ट्र के दौरे के बाद, यहाँ के पर्यटन उद्योग में तीव्र वृद्धि हो रही है। अब सरकार ने समुद्री जीवन एवं उद्योगों के संरक्षित करने तथा उसमें वृद्धि करने के द्वारा इस तीव्रता को बनाये रखने के लिए कुछ योजनाएँ प्रस्तावित की हैं।

ब्लू बांड में निवेश करने वाली कम्पनियाँ:

विश्व बैंक ने ब्लू बॉण्ड के विकास में सहायता की है और सेशेल्स की निम्नलिखित तीन निवेशकों तक पहुंचने में मदद की है:

- कल्वर्ट इम्पैक्ट कैपिटल (Calvert Impact Capital)
- नुवीन (Nuveen)
- प्रूडेंशियल फिनेंशियल इंक जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। (U.S. Headquartered Prudential Financial Inc.)

ब्लू बॉण्ड के बारे में मुख्य बिंदु:

ब्लू बॉण्ड एक ऐसी पहल का हिस्सा है जो स्थानीय समुदायों और व्यवसायों को सशक्त बनाने हेतु संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक

और निजी निवेश को जोड़ती है।

► बॉन्ड से प्राप्त आय का उपयोग समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार, प्राथमिक मत्स्य उद्योगों के बेहतर शासन और सेशेल्स की ब्लू इकॉनमी के विकास के लिए किया जाएगा।

► बॉन्ड से प्राप्त आय से विश्व बैंक के दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर मत्स्योद्योग प्रशासन और साझा विकास कार्यक्रम में भी योगदान किया जायेगा। यह संस्था इस क्षेत्र के देशों को अपने मत्स्योद्योगों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने और अपने मत्स्यपालन क्षेत्रों से आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए समर्थन प्रदान करती है।

ब्लू बॉन्ड का निर्माण:

► सेशेल्स ब्लू बॉन्ड को आंशिक रूप से विश्व बैंक (आईबीआर डी) से 5 मिलियन अमरीकी डालर की गारंटी प्राप्त है। इसके साथ ही इसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने पांच मिलियन डॉलर का रियायती ऋण देकर समर्थन दिया है, जोकि आंशिक रूप से बॉन्ड के लिए ब्याज भुगतान को कवर करेगा।

► ब्लू बॉन्ड को संरचित करने के लिए विश्व बैंक की टीम ने निवेशकों के साथ मिलकर काम किया। इस टीम में ट्रेजरी, कानूनी, पर्यावरण और वित्त समूहों के विशेषज्ञ शामिल थे।

सेशेल्स के साथ भारत की चिंताएं:

सेशेल्स 'एजम्पशन द्वीप' के कारण भारत के लिए चिंता का विषय बन चुका है। भारतीय नौसेना सेशेल्स पर एक ध्वनि निगरानी प्रणाली स्थापित करना चाहती है। लेकिन सेशेल्स की सरकार ने प्रस्ताव से इनकार कर दिया क्योंकि वे अपनी जमीन पर संघर्षों का सामना कर रहे थे। वास्तव में सेशेल्स के लोग भारत और चीन के बीच हो रहे झगड़े में नहीं फसना चाहते।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

ब्रेक्सिट समझौता क्या है?



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से: GS 2 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचारों में क्यों:

► ब्रेक्सिट वोट के 2 से अधिक वर्षों के बावजूद, यूरोपीय संघ छोड़ने के मुद्दे पर, ब्रिटेन एक मत नहीं हो सका है।

ब्रेक्सिट के बारे में

► ब्रेक्सिट शब्द यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से बाहर आने को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक जनमत संग्रह में, ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट के पक्ष में (बहुत कम अंतर से) मतदान किया। परिणामस्वरूप इसके बाहर निकलने की शर्तों पर बातचीत करने के लिए वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संसद के बीच वार्ताएं चल रही हैं।

ब्रेक्सिट का संवैधानिक प्रावधान:

लिस्बन संधि (अनुच्छेद 50) यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को इससे बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करती है। किसी भी देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए, यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता-वार्ता करनी पड़ती है। यह वार्ता यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच समझौता करवाएगी।

ब्रेक्सिट की मांग क्यों?

► आर्थिक कारण- मुख्य विवाद यह था कि आर्थिक रूप से, ब्रिटेन जो लाभ प्राप्त करता है उससे अधिक खो देता है। चीजों में से एक यह है कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता की कमजोरी है।

► आप्रवासन मुद्दे: ब्रिटेन में कानूनी प्रवासियों में से आधे यूरोपीय संघ से आते हैं। ऐसे में वहां यह भावना है कि उनके कारण ब्रिटेन में जन्मे श्रमिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्थानीय लोगों में व्याप्त इस डर को इस तथ्य से और बल मिला है कि 1997 के बाद से कुल सृजित नौकरियों के तीन चौथाई हिस्से पर यूरोपीय संघ के आप्रवासियों ने कब्जा किया है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ द्वारा अपने सदस्यों से अधिक शरणार्थियों को स्थान देने की प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाती है। ब्रिटेन इसके पक्ष में नहीं है। यह ऐसे समय में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब मध्य पूर्व और अफ्रीका में जारी संघर्षों के कारण यूरोप में शरणार्थियों का आगमन अभूतपूर्व रूप से उच्च है।

► संप्रभुता का मुद्दा: यूरोपीय संघ कई मायनों में एक परिवर्तनीय विचार है। इसके विभिन्न परिणामों में से एक राष्ट्रीय सम्प्रभुता को कमजोर करना है। इसके अतिरिक्त EU द्वारा एक अधिक संकुचित संघ बनाने के विचार पर बल दिया जा रहा है जोकि यूरोपीय संसद को निर्णय-निर्माण के सम्बन्ध में अधिक शक्तियां प्रदान करेगा। इससे ब्रिटिश संसद की प्राधिकारिता और भी सीमित होगी।

ब्रेक्सिट की प्रक्रिया:

सबसे पहले, थेरेसा मे के मंत्रिमंडल से पारित किया गया। इसके उपरांत EU द्वारा अनुमोदित किया गया। अंततः इसे UK के हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित होने की आवश्यकता होगी।

इस समझौते में निम्नलिखित तीन मुद्दे सर्वाधिक प्रभावी हैं:

- यूके और यूरोपीय संघ के बीच वित्तीय समझौता
- ब्रिटेन और ईयू नागरिकों के अधिकार (जो एक-दूसरे के क्षेत्रों में रहते हैं)
- यूके- आयरलैंड सीमा के मुद्दे

आयरिश प्रश्न:

आयरलैंड ब्रिटेन के पश्चिम में एक द्वीप है और इसमें विशिष्ट जनसांख्यिकीय विशेषताओं के साथ दो प्रमुख क्षेत्र हैं (उत्तर और दक्षिण)।

"प्रोटेस्टेंट बहुमत उत्तरी आयरलैंड" (एक यूके क्षेत्र) और "कैथोलिक

बहुमत आयरिश गणराज्य" (दक्षिण में एक स्वतंत्र देश), के भीतर और उनके बीच गंभीर नृजातीय तनाव है।

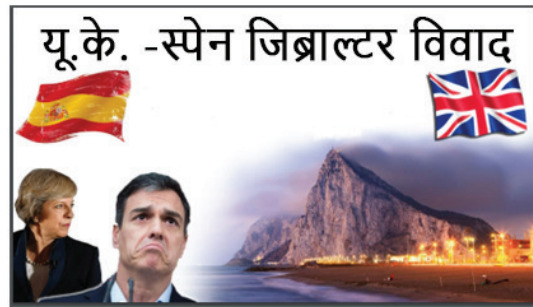


चूंकि यू.के. यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की योजना बना रहा है, इसलिए आयरिश प्रश्न सभी संबंधित सरकारों को परेशान कर रहा है क्योंकि वहां स्पष्ट भय है कि हिंसा का एक नया युग शुरू हो सकता है।

PRELIMS बिट्स: यूरोपीय संघ के बारे में:

- यूरोपीय संघ (ईयू):
- 28 राज्यों का राजनीतिक और आर्थिक संघ
- 4,475,757 वर्ग किमी (1,728,099 वर्ग मील) का क्षेत्रफल
- अनुमानित जनसंख्या- 513 मिलियन। इसे सभी सदस्य देशों में लागू कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार के रूप में विकसित किया गया है। ये कानून केवल उन मामलों में लागू होंगे, जिनके सम्बन्ध में सदस्य राज्यों ने सहमति व्यक्त की है।

अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से: प्रारंभिक परीक्षा 2019

जिब्राल्टर

- जिब्राल्टर आइबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र है।
- यह स्पेन का हिस्सा नहीं है।
- ब्रिटेन का उपनिवेश
- भूभाग के अधिकांश भाग में रॉक ऑफ जिब्राल्टर है। इसके नीचे एक घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है जहाँ 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से जिब्राल्टरियन हैं।



14 समुद्रपारीय क्षेत्र जो ब्रिटेन के पास है।

- एंगुइला
- बरमूडा
- ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र (बीएटी) - एसएसआई की बीएटी के संबंध में कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि यहाँ अंटार्कटिक संधि को प्राथमिकता दी जाती है।
- ब्रिटेन और भारतीय समुद्री क्षेत्र।
- ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स।
- कैमैन द्वीप.
- फॉकलैंड आइलैंड्स

जिब्राल्टर - यूरोपीय संघ के भीतर अपनी स्थिति के कारण

एसएसआई की पहुँच से बाहर।

- मोंटेसेराट
- पिटकेरेन द्वीप, हेंडरसन, दुसी और ओनो द्वीपसमूह
- सेंट हेलेना, असेंशन और ट्रिस्टन दा कुन्हा।
- सर्वोच्च आधार क्षेत्र (एसबीए) - एसबीए के संबंध में एसएसआई की जिम्मेदारी प्रशासक को सलाह के प्रावधान तक ही सीमित है।
- दक्षिण जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड्स।

रॉक ऑफ जिब्राल्टर



आइबेरियन प्रायद्वीप

यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित, आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत एंडोरा, पुर्तगाल और स्पेन देश और जिब्राल्टर का ब्रिटिश उपनिवेश है।

जिब्राल्टर ब्रिटिश क्यों है?

यह ब्रिटिश साम्राज्य के समय के उन 14 क्षेत्रों में से एक है जिन पर अभी भी ब्रिटेन का स्वामित्व है।

स्पेन ने 1704 में जिब्राल्टर को एंग्लो-डच सैन्य हमले में खो दिया और आधिकारिक तौर पर 1713 में इस पर लंदन का स्वामित्व हो गया।

स्पेन तब से इस पर पुनः अधिकार करना चाहता है।

लेकिन दो हालिया जनमत संग्रहों- 1968 और 2002 में - जिब्राल्टर के लोगों ने स्पेन के बजाय ब्रिटिश शासन के अधीन रहना चुना। ब्रिटेन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए लोग ब्रिटेन के साथ रुके। जिब्राल्टर की महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति - भूमध्यसागरीय प्रवेश द्वार के रूप में - उन कारणों में से एक है जिसके कारण ब्रिटेन इस पर अधिकार चाहता है।

यह ब्रेक्सिट के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?

ब्रेक्सिट: ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना जिब्राल्टर में रहने वाले लोग ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए उन्हें EU जनमत संग्रह में भी वोट देना पड़ता है।

उन्होंने EU में रहने के पक्ष में (96% के बहुमत से) मत दिया किन्तु उन्हें भी शेष UK के साथ अलग होना पड़ेगा।

ब्रेक्सिट और जिब्राल्टर

चूंकि यू.के. यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की योजना बना रहा है, इसलिए आयरिश प्रश्न सभी संबंधित सरकारों को परेशान कर रहा है क्योंकि वहां स्पष्ट भय है कि हिंसा का एक नया युग शुरू हो सकता है।



- स्पेन के लिए यह चौंकाने वाला था कि लोग ब्रिटेन छोड़ना नहीं चाहते हैं।
- स्पेन ने यह मांग की है कि, जिब्राल्टर के निर्णय में स्पेन का मत होगा।

स्पेन के लिए विजय?

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सेन्चेज़ ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि

थेरेसा मे के ब्रेक्सिट समझौते को EU के शेष 27 नेताओं द्वारा सहमति दिए जाने के उपरांत, जिब्राल्टर पर भविष्य में होने वाली वार्ताओं के सम्बन्ध में स्पेन को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा: "यह जिब्राल्टर पर यूनाइटेड किंगडम के साथ वार्ता में स्पेन की स्थिति को सुदृढ़ करता है, जोकि अब तक नहीं थी।"

स्पेन ने ब्रिटेन की स्थिति का लाभ उठाकर जिब्राल्टर पर अपनी सर्वोच्च प्राधिकारिता आरोपित की है।

थेरेसा मे पर दबाव

- जिब्राल्टर के भविष्य पर स्पेन की मांगों को स्वीकारने को लेकर थेरेसा मे पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया है।
- एक बार यूके ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया, तो यूरोपीय संघ के साथ जिब्राल्टर का राजनीतिक, कानूनी और यहां तक कि भौगोलिक संबंध स्पेन के माध्यम से जाएगा।

नोट्स

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

मास्को- प्रारूप बैठक



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

मास्को प्रारूप और तालिबान का संपूर्ण विश्लेषण अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत हो रहा है और यह भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों को कैसे प्रभावित करेगा? मास्को प्रारूप इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

UPSC परिप्रेक्ष्य
GS प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा II- भारत और उस के पड़ोसी; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

समाचारों में क्यों?

- दो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक रूस में होने वाली अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर वार्ता (बैठक) में भाग लेंगे।
- मास्को प्रारूप" के रूप में प्रसिद्ध इस वार्ता में तालिबान के "उच्च स्तरीय" प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ 12 देशों के प्रतिनिधियों के साथ अफगानिस्तान की "उच्च शांति परिषद" का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा।
- यह पहली बार है जब दोहा में स्थित तालिबान प्रतिनिधियों के साथ मेज पर एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद होगा। अमेरिका और पाकिस्तान भी अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे।

रूसी संघ

- अफगानिस्तान भारत के पश्चिमी ओर है।
- अफगानिस्तान विशिष्ट रूप से उन देशों द्वारा स्थलरुद्ध है जो प्राकृतिक संसाधनों के अच्छे स्रोत हैं।
- अगर भारत तुर्कमेनिस्तान से तेल चाहता है, तो उसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरना होगा, क्योंकि पाइपलाइन इसी मार्ग से होकर जायेगा।

अफगानिस्तान

- कई महान साम्राज्यों ने (जैसे ब्रिटेन, यूएसएसआर) ने अफगानिस्तान को विभिन्न उद्देश्यों और इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण सदैव आकर्षक पाया है।
- अफगानिस्तान को दिया गया विशेष नाम: साम्राज्यों का कब्रिस्तान।
- अफगानिस्तान भूराजनैतिक प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण है।
- अफगानिस्तान में हर साम्राज्य असफल रहा।
- कई सम्राटों ने अफगानिस्तान में अपनी शक्ति स्थापित करने की कोशिश की।
- कई सम्राटों ने अफगानिस्तान में अपनी शक्ति स्थापित करने की कोशिश की।
- जब यूएसएसआर ने पाकिस्तान पर आक्रमण शुरू किया, तो अफगानिस्तान ने सोचा था कि उनका नंबर अगला है।

अफगानिस्तान पर आक्रमण

- यूएसएसआर- सोवियत-अफगान युद्ध 9 वर्षों से अधिक समय तक चला (दिसंबर 1979 से फरवरी 1989 तक)
- इस युद्ध में USSR की पराजय हुई।
- अफगानिस्तान यूएसएसआर के लिए एक कब्रिस्तान था।

- दस वर्षों तक यूएसएसआर ने खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन असफल रहा।
- यूएसएसआर के पास अफगानिस्तान के साथ भूमि सीमाएं हैं।

तालिबान

- 2001 के अंत में 11 सितंबर के हमले के बाद अफगानिस्तान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हमला किया।
- यह संघर्ष अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है।
- इसका सार्वजनिक उद्देश्य अल-कायदा को खत्म करना और तालिबान को सत्ता से हटाकर उसे अफगानिस्तान में एक सुरक्षित आधार ना मिलने देना था।
- जब यूएसएसआर अफगानिस्तान आया, तो अमेरिका ने तालिबान की मदद की।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न आतंकवादी समूह के लिए धन उपलब्ध कराया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वित्तीय रूप से तालिबान जैसे समूहों का समर्थन किया। वे यूएसएसआर के साथ लड़े और तालिबान का नेतृत्व किया।

2001 से 2018 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में बम फेंके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

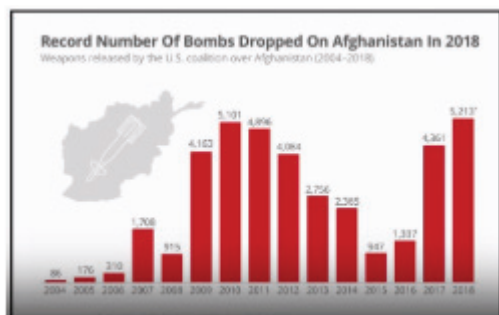
2018 - अफगानिस्तान को कौन नियंत्रित करता है



गहरे रंग का हिस्सा तालिबान के गंभीर प्रभाव को दर्शाता है। तालिबान की वृद्धि अन्य आस-पास के देशों के लिए अच्छी नहीं है।

अगला कदम क्या?

संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं



संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं पिछले 2 वर्षों में गंभीर बमबारी। तालिबान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इसका प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

मॉस्को फॉर्मेट 2018

- मॉस्को फॉर्मेट- अफगानिस्तान में तालिबान के मुद्दे पर रूस द्वारा आरम्भ की गई दूसरी बैठक।

- 12 प्रतिभागियों - चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, कज़ाखस्तान और तुर्कमेनिस्तान, रूस और यू.एस. + तालिबान के प्रतिनिधि।

भारत और तालिबान

- भारत ने हाल ही में तालिबान प्रतिनिधियों को शामिल करने वाली "मॉस्को फॉर्मेट" बहुपक्षीय बैठक में दो पूर्व राजनयिकों को "गैर-आधिकारिक" प्रतिभागियों के रूप में भेजा।
- पहली बार तालिबान प्रतिनिधिमंडल के साथ मंच साझा करने वाले भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि उल्लेखनीय हैं।
- भारत ने इस मास्को बैठक में अनौपचारिक रूप से भाग लिया ताकि आने वाले समय पर अगर तालिबान का दमन किया जाता है तो भारत अपना रुख बदल दे।

भारत के प्रतिनिधि:

अमर सिन्हा और टीसीए राघवन भारतीय प्रतिनिधि थे। श्री सिन्हा काबुल (2013-2016) के राजदूत थे। श्री राघवन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से निपटने वाले विदेशी मामलों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है और इस्लामाबाद के उच्चायुक्त (2013-2015) थे। ये वर्तमान में, दिल्ली में स्थित सरकार-संचालित इंडियन कौंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसी डब्ल्यूए) थिंक टैंक के महानिदेशक हैं।

भारत की पारंपरिक स्थिति क्या थी?

- भारत उन देशों में से एक था जिन्होंने 1996-2001 के तालिबान शासन को मान्यता देने से इनकार कर भारत द्वारा तालिबान की वृद्धि को चिंता के साथ देखा गया है। इसका अनुमान है कि इसे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई द्वारा संचालित किया जा रहा था।
- हम तालिबान को अनदेखा नहीं कर सकते हैं।

रूस का ग्रेट गेम?

- विशेष रूप से मध्य एशिया और अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में खुद को फिर से स्थापित करने की रूस की महत्वाकांक्षा।
- तालिबान को भी सम्मेलन से फायदा हुआ: पहली बार इसके प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा आयोजित मंच में भाग लिया।

नोट्स

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध



FCTC

डब्ल्यू. एच. ओ. का
तम्बाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क
कन्वेंशन

(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से: प्रारंभिक परीक्षा के लिए WHO
और WHO -FCTC से संबंधित तथ्य

सन्दर्भ:

WHO का तम्बाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, भारतीय
मंत्रिमंडल ने प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है:

मंत्रिमंडल ने तम्बाकू उत्पादों में गैरकानूनी व्यापार को खत्म
करने के लिए WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल
(WHO FCTC) के तहत प्रोटोकॉल में प्रवेश करने के लिए भारत
को मंजूरी दे दी है। भारत ने कहा है कि वो इस प्रोटोकॉल का
हिस्सा बनेगा।

WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन)

- ▶ संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी।
- ▶ सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित।
- ▶ 7 अप्रैल 1948 को स्थापित।
- ▶ मुख्यालय- स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में

इस संधि के बारे में

- ▶ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (FCTC) दुनिया की
पहली आधुनिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है।
- ▶ यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के तहत पहली संधि
भी है।
- ▶ संधि फरवरी 2005 में लागू हुई थी। 192 WHO सदस्य राज्यों
में से 168 ने हस्ताक्षर किए थे।

अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां:

FCTC तम्बाकू महामारी का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय
स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया प्रदान करता है और तम्बाकू के
उपयोग को संबोधित करने वाली सरकारों के लिए विशिष्ट कदम
निर्धारित करता है, जिनमें निम्न शामिल हैं:

- ▶ तम्बाकू की खपत को कम करने के लिए कर और मूल्य
उपायों को अपनाना। (तम्बाकू, जिसकी बड़े स्तर पर खपत होती
है, पर कर आरोपित करना। इससे उसकी खपत में कमी
आएगी।)
- ▶ तम्बाकू विज्ञापन, पदोन्नति, और प्रायोजन पर प्रतिबंध
- ▶ कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान को धूम्रपान मुक्त बनाना
- ▶ तम्बाकू पैकेजों पर प्रमुख स्वास्थ्य चेतावनियां डालना
- ▶ तम्बाकू उत्पादों में अवैध व्यापार का मुकाबला करना

WHO FCTC के अनुच्छेद 15 में निहित तम्बाकू आपूर्ति में कमी
की प्रमुख रणनीतियों में से एक में अवैध व्यापार और तम्बाकू
उत्पादों के सभी रूपों को खत्म करने की परिकल्पना की गयी
है, जिसमें तस्करी, अवैध विनिर्माण शामिल हैं।

उपाय :

पक्षकारों द्वारा सप्लाई चेन कंट्रोल उपाय अपनाये जाने चाहिए।
इनमें तम्बाकू पदार्थों के निर्माण एवं निर्माण की मशीनरी की
लाइसेंसिंग, रिकॉर्ड रखना, उत्पादन में संलग्न लोगों द्वारा
समुचित परिश्रम से कार्य करना इत्यादि शामिल है।

▶ प्रोटोकॉल में अपराधों, जल्दी और जल्द उत्पादों के निस्तारण
जैसे प्रवर्तन उपायों की सूची दी गयी है।

▶ यह सूचना साझा करने, गोपनीयता बनाये रखने, प्रशिक्षण,
तकनीकी सहायता और वैज्ञानिक एवं तकनीकी मामलों में
सहयोग को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की
मांग करता है।

नोट्स

एक साथ 31 सैटेलाइट लॉन्च

भारत की पहली
हाइपर स्पेक्ट्रल
इमेजिंग सैटेलाइट



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से : GS 3 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचारों में क्यों?

- इसरो ने 29 नवंबर को श्रीहरिकोटा से भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट (HySIS) और 30 सह-यात्री उपग्रहों को लेकर जाने वाले रॉकेट पीएस-एलवी-सी 43 लॉन्च किया।
- HySIS के सह-यात्रियों में आठ अलग-अलग देशों के एक माइक्रो और 29 नैनो उपग्रह शामिल हैं।

HySIS के बारे में:

- HySIS हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्षमता वाला इसरो का पहला पूर्ण-पैमाने पर काम करने वाला उपग्रह है।
- इस उपग्रह को एक ध्रुवीय तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है।
- इसरो ने अप्रैल 2008 में हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। इसके अंतर्गत आईएमएस -1 (इंडियन मिनी सैटेलाइट -1) नामक एक छोटे से 83-किलोग्राम के प्रदर्शन माइक्रोसैटेलाइट को कार्टोसैट -2 ए के साथ सह-यात्री के रूप में लॉन्च किया गया था।
- अक्टूबर 2008 में, इसने चंद्रयान -1 पर एक HySI या हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर लगाया। इसका प्रयोग खनिजों के लिए चंद्रमा की सतह को स्कैन करने के लिए किया गया।

HySIS का महत्व

- HySIS का प्राथमिक लक्ष्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दृश्यमान, निर-इन्फ्रारेड और शॉर्टवेव इन्फ्रारेड क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है।
- हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह जमीन के 630 किमी ऊपर से 55 वर्णक्रमीय या कलर बैंड में देख जा सकता है।
- Hypex' इमेजिंग अंतरिक्ष से किसी दृश्य के प्रत्येक पिक्सेल के लिए स्पेक्ट्रम को पढ़कर पृथ्वी पर वस्तुओं, सामग्री या प्रक्रियाओं की अलग पहचान की अनुमति देती है।
- यह एक संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को चिह्नित करने और पृष्ठभूमि से अलग करने में अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। इससे सीमापारीय गति अथवा अन्य प्रच्छन्न गतियों की पहचान में सहायता मिलेगी।
- इसका उपयोग वायुमंडलीय गतिविधि और जलवायु परिवर्तन की निगरानी से लेकर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, कृषि, वानिकी, जल प्रबंधन, तटीय पैटर्न के अध्ययन, तेल और खनिजों की

तलाश तथा सैन्य निगरानी तक सभी तरह की गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

प्रीलिम्स बिट्स: पीएसएलवी बनाम जीएसएलवी

- पीएसएलवी (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन) के बारे में: पीएसएलवी का उपयोग लो अर्थ ऑर्बिट में विभिन्न उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से "पृथ्वी-अवलोकन" या "रिमोट-सेंसिंग" उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- उनकी सूर्य-तुल्यकालिक प्रकृति के कारण, इन कक्षाओं को "लो अर्थ ऑर्बिट (LEO)" के रूप में भी जाना जाता है। यह उपग्रह के धरती पर किसी एक स्थान पर बार-बार आने के दौरान ऑन-बोर्ड कैमरे को सूर्य के प्रकाश की स्थिति के तहत धरती की छवियों को लेने में सक्षम बनाता है। साथ ही इससे उपग्रह का उपयोग धरती के संसाधनों के पर्यवेक्षण के लिए भी किया जा सकता है।
- रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में लॉन्च करने के अलावा, पीएसएलवी का उपयोग अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) तक लगभग 1400 किलो तक के निचले लिफ्ट-ऑफ द्रव्यमान के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए भी किया जाता है।
- पीएसएलवी चार चरणों वाला प्रक्षेपण वाहन है। इसके पहले और तीसरे चरण में सॉलिड राकेट मोटर तथा दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड राकेट इंजन का प्रयोग होता है।
- पीएसएलवी दुनिया के सबसे विश्वसनीय लॉन्च वाहनों में से एक है। यह बीस वर्षों से अधिक समय से सेवा में रहा है और चंद्रयान -1, मंगल ऑर्बिटर मिशन, स्पेस कैप्सूल रिकवरी प्रयोग, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (आईआरएन एसएस) आदि जैसे ऐतिहासिक मिशनों के लिए विभिन्न उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। पीएसएलवी विभिन्न संगठनों के बीच एक प्रेक्षपण सेवा प्रदाता के रूप में पसंदीदा है और 19 देशों के लिए 40 से अधिक उपग्रहों का शुभारंभ किया है।

जीएसएलवी (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन) के बारे में:

- जीएसएलवी के प्राथमिक पेलोड INSAT क्लास (लगभग 2,500 किलो द्रव्यमान) के संचार उपग्रह हैं जो भूगर्भीय कक्षाओं (लगभग 36000 किमी) से संचालित होते हैं और इसलिए जीएसएलवी द्वारा भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षाओं में रखे जाते हैं।
- अपनी भू-तुल्यकालिक स्थिति के कारण इन कक्षाओं में स्थित उपग्रह पृथ्वी पर किसी निश्चित स्थान से देखने पर एक ही अवस्थिति पर स्थायी रूप से ठहरे हुए नज़र आते हैं। इसके कारण ट्रैकिंग ग्राउंड एंटेना की आवश्यकता नहीं होती और ये संचार अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होते हैं।
- इसरो द्वारा जीएसएलवी के दो संस्करण विकसित किए जा रहे हैं। जीएसएलवी मार्क -2 के पहले संस्करण में GTO के लिए 2,500 किलोग्राम तक लिफ्ट-ऑफ द्रव्यमान के उपग्रहों को लॉन्च करने और LEO के लिए 5,000 किलोग्राम लिफ्ट-ऑफ द्रव्यमान के उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता है। दूसरा जीएसएलवी एमके -3 एक ठोस चरण रॉकेट मोटर का उपयोग करने वाला त्रिचरणीय जिसमें पहले स्टेज में सॉलिड राकेट मोटर दूसरे स्टेज में तरल ईंधन और तीसरे स्टेज (इसे क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहा जाता है) में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है।

विज्ञान और तकनीक

इसरो और नासा ने ब्लैक होल की खोज की



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से:

प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी एवं बायो-टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जागरूकता।

ब्लैकहोल की खोज करने में भारत के एस्ट्रोसैट ने सहायता की है।

2018 नवम्बर

ISRO के एस्ट्रोसैट और NASA के चंद्रा एक्स-रे वेधशाला द्वारा एक ब्लैक होल देखा गया।

भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह, एस्ट्रोसैट ने 4U 1630-47 नामक बाइनरी स्टार सिस्टम में एक ब्लैक होल देखा जोकि अधिकतम संभव गति से घूम रहा है।

नासा के चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने उच्च स्पिन दर की पुष्टि की है। ब्लैक होल एक विदेशी लेकिन अतिसाधारण खगोलीय वस्तु है। यह तब उत्पन्न होता जब एक बड़े तारे की मृत्यु हो जाती है और अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ एक छोटे से स्थान पर सिमट जाता है और प्रकाश में फंस आता है।

घूमने वाला ब्लैकहोल (SPINNING BLACKHOLE)

ब्लैक होल दुर्लभ होते हैं, इन्हें मुश्किल से देखा जा सकता है और ये तेज़ी से नहीं घूमते हैं।

इस विशिष्ट ब्लैक होल को मॉन्स्टर ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यह एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमा के बहुत करीब घूम रहा है।

वैज्ञानिकों के पास ब्लैक होल को मापने के लिए सिर्फ दो ही तरीके होते हैं- या तो उनका द्रव्यमान या उनकी चक्रण दर (spin rate)। हालाँकि अभी भी यह ब्लैक होल को मापने का सही तरीका नहीं है। और, स्पिन रेट 0 (न्यूनतम) और 1 (अधिकतम) के बीच कहीं भी हो सकती है।

यह ब्लैक होल 0.9 की गति से घूम रहा था जो अधिकतम गति है। यह अब तक दर्ज की गई उच्चतम गतियों में से एक है। NASA और ISRO ने एक ऐसे ब्लैक होल की खोज की है जो इतनी तेज़ गति से घूमता है कि वो अंतरिक्ष को भी घुमा (स्पिन) सकता है।

ब्लैक होल का रहस्य

आइंस्टीन के सिद्धांत से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यदि एक ब्लैक होल इतनी तेज़ गति से घूमता है, तो वह अंतरिक्ष को भी घुमाने में सक्षम है।

वास्तव में, यदि ब्लैक होल के आस-पास की स्थितियों के सही

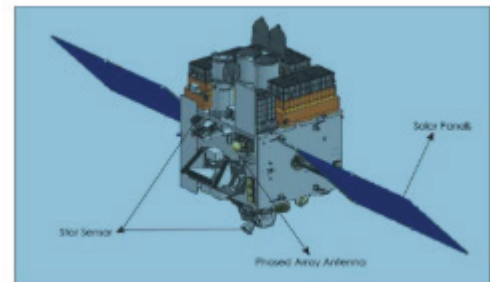
होने की कल्पना की जाये तो ब्लैक होल में प्रवेश करने वाले गैसीय तत्वों तथा उच्च तापमान के साथ मिलकर उच्च चक्रण दर, आकाशगंगाओं के निर्माण को समझने की कुंजी हो सकती है। एक ब्लैक होल, तारे से छोटा होता है, लेकिन ये बहुत सघन और भारी होते हैं तथा इसमें प्रकाश को भी खींचा जा सकता है। शोधकर्ताओं के एक दल ने, जिसका अध्ययन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा, विशेष रूप से कहा है कि यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करती है और सामान्य रूप से इस बारे में अधिक प्रकाश डालती है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे होता है।

खोज का महत्त्व

► एस्ट्रोसैट द्वारा खोजे गए ब्लैक होल सहित, केवल पांच ब्लैक होल ऐसे हैं जोकि सटीक रूप से मापी गयी उच्च चक्रण दरों पर घूमते हैं।

► यदि चक्रण दरों को ध्यान में न लिया जाए, तो यह ब्लैक होल मिल्की वे आकाशगंगा में देखे गये 20 ब्लैक होल्स में से है।

5. तीन आईडेंटिकल लार्ज एरिया ज़ेनन प्रपोज़नल काउंटर



चंद्र एक्स-रे वेधशाला

► चंद्र एक्स-रे वेधशाला (सीएक्सओ), जिसे पहले एडवांस्ड एक्स-रे के नाम से जाना जाता था

एस्ट्रोसैट-चंद्रा अध्ययन

► ब्लैक होल के अध्ययन के लिए एस्ट्रोसैट और चंद्रा उपग्रहों का उपयोग भारत और अमेरिका का पहला सहयोग है। इससे भविष्य में होने वाले ऐसे सहयोगों के लिए रास्ते खुलने चाहिए।

► भारत के पहले समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान उपग्रह एस्ट्रोसैट में SXT तथा लार्ज एरिया एक्स-रे प्रपोज़नल काउंटर (LAXPC) स्थापित किये गये हैं। इन उपकरणों ने ब्लैक होल की चक्रण दर (स्पिन रेट) के मापन में मुख्य भूमिका निभाई जोकि हमारे समकालिक चंद्रा सैटेलाइट के आँकड़ों से प्राप्त परिणामों से संगत थी।

► भविष्य में यह ISRO (भारत) को लाभ देगा।

► यह भारत के लिए एक अवसर है।

► NASA, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ काम नहीं करेगा।

एस्ट्रोसैट के बारे में अधिक जानकारी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 2015 में एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण किया। एस्ट्रोसैट का जीवनकाल 5 साल

है जोकि 2020 तक है।

1. UV इमेजिंग टेलीस्कॉप
2. स्कैनिंग स्काई मॉनिटर
3. कैडमियम-जिंक-टेलुराइड इमेजर
4. सॉफ्ट एक्स-रे टेलीस्कॉप, और

(AXAF) के नाम से जाना जाता था, एक फ्लैगशिप-क्लास अंतरिक्ष वेधशाला है। NASA द्वारा 23 जुलाई 1999 को STS-93 पर इसका प्रक्षेपण किया गया। हबल स्पेस टेलीस्कॉप, कॉम्प्टन गामा रे वेधशाला (1991-2000) और स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कॉप के साथ चंद्रा भी महान वेधशालाओं में से एक है। इस टेलिस्कोप का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय-अमेरिकी खगोलशास्त्री सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है।

नोट्स

विज्ञान और तकनीक

आईएनएस अरिहंत



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

INS अरिहंत के साथ अब भारत परमाणु ट्राई वाला राष्ट्र बन गया

UPSC के दृष्टिकोण से- GS पेपर 1, मुख्य परीक्षा, भारत की प्रतिरक्षा

वर्तमान में इस पर चर्चा क्यों?

भारत की पहली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने 6 नवंबर, 2018 को अपना पहला प्रतिबंध पेट्रोल पूरा कर लिया है। इसका अर्थ है कि पनडुब्बी पूरी तरह से परिचालित है और यदि तैनात है, तो भारत के प्रतिद्वंद्वियों को लक्षित कर सकती है।

INS अरिहंत (दुश्मनों का विध्वंसक):

- निर्माता: शिप बिल्डिंग सेंटर (एसबीसी), विशाखापटनम, भारत
- लांच: 26 जुलाई 2009 (विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस पर)
- उपार्जित: 13 दिसंबर, 2014
- कमीशन: अगस्त 2016
- स्थिति: सेवा में
- विस्थापन: सतह: 6,000 टन

भारत ने पूर्ण परमाणु प्रतिरोध की घोषणा की

परमाणु प्रतिरोध (Nuclear Deterrence): यह एक ऐसा सैन्य सिद्धांत है जिसके अनुसार यह संभावना कि एक देश बदले की कार्यवाही के रूप में अपने पास उपलब्ध परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा, दुश्मन देश को आक्रमण करने से रोकेगी। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई देश परमाणु हथियारों वाले देश पर हमला करता है, तो जिस देश को परमाणु हमले का सामना करना पड़ता है वह बदले में परमाणु हमला कर सकता है और युद्ध को रोक और पलट सकता है।

प्रतिरोध संतुलन

यह शीत युद्ध-काल की एक परंपरा है जिसके अनुसार परमाणु-सशस्त्र पनडुब्बियों को जल में तैनात किया जाता था, ताकि वे हमले की स्थिति में पलटवार कर सकें।

2013 में चीन द्वारा अफ्रीका के पूर्वी तट पर तथाकथित 'एंटी-पाइरेसी मिशन' के लिए परमाणु पनडुब्बी की तैनाती के बाद से, नई दिल्ली में यह दृढ़ विश्वास है कि 'परमाणु त्रिभुज' (लगभग 30 वर्षों से विचाराधीन) पर त्वरित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए।

यह भारत को उन कुछ देशों की लीग में रखता है जो एसएस-बीएन को डिजाइन, निर्माण और संचालित कर सकते हैं।

प्रतिरोध पर भारत का मत:

- भारत ने घोषणा की है कि इसके परमाणु सिद्धांत में वर्णित, परमाणु त्रिभुज परिचालित है। परमाणु त्रिभुज -वायु, भूमि और समुद्र, कहीं से भी परमाणु हथियारों के संचालन की क्षमता।
- यह घोषणा स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत द्वारा अपनी पहली प्रतिरोध गश्त आयोजित करने के उपरांत की गयी थी।
- इसका अर्थ यह है कि अब अरिहंत परमाणु युद्धसामग्री युक्त बैलिस्टिक मिसाइल से सुसज्जित होकर गहरे समुद्र में निगरानी कर रहा है।
- अरिहंत अपनी श्रृंखला की दूसरी पनडुब्बी है। यह समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है जिसके उपरांत इसे सेवा में शामिल किया जायेगा।

INS अरिहंत का विकास:

- INS अरिहंत, एक सामरिक परिसंपत्ति है। यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (एटीवी) कार्यक्रम के तहत दो दशकों से अधिक समय में विकसित हुई है।
- INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी तीन और पनडुब्बियां निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
- INS अरिहंत विकास परियोजना को आधिकारिक तौर पर 1998 में स्वीकार किया गया था और पनडुब्बी को 2009 में लांच किया गया।
- 2013 में पनडुब्बी के परमाणु रिएक्टर क्रिटिकल हो गए और इसे तीन साल बाद कमीशन किया गया।
- यह सीधे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के तहत आता है।
- परमाणु हथियारों के सन्दर्भ में भारत की 'नो-फर्स्ट-यूज (NFU)' की स्थिति देखते हुए, SSBN जवाबी हमले के लिए सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है।
- चूंकि वे परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित होते हैं, अतः इन पनडुब्बियों को बिना डिटेक्ट होने के खतरे के, पानी के भीतर अनिश्चित काल तक रखा जा सकता है। अन्य दो प्लेटफॉर्म: भूमि-आधारित और एयर-लॉन्च का पता लगाना बहुत आसान है।

चीन की क्षमता:

चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) में चार जिन-क्लास SSBN (बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां) और नौ SSN (परमाणु संचालित पनडुब्बियां) होने का अनुमान है। यह अनुमान भी लगाया गया है कि इसके पास 40 से अधिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का बेड़ा है।

नोट्स:

- भारत की तरह, चीन भी अपने परमाणु सिद्धांत में 'नो फर्स्ट स्ट्राइक' का पालन करता है। यह मानता है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की समुद्री क्षमता इसकी भूमि आधारित सड़क और रेल से लांच हो जाने वाली सामरिक मिसाइलों को पूरकता प्रदान करती है।
- पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अज़ीज़ ने अपनी 'पहले उपयोग की नीति' का बचाव किया। अज़ीज़ ने कहा कि पाकिस्तान का पहले उपयोग का सिद्धांत प्रकृति में पूरी तरह से प्रतिरोधक है। उन्होंने समझाया कि 2001 के भारतीय संसद हमले के बाद यह प्रभावी हुआ और तर्क दिया कि यदि पाकिस्तान के पास 'नो फर्स्ट यूज' नीति होती, तो दोनों देशों के बीच एक बड़ा युद्ध होता।
- सागरिका कोड नाम K-15 or B-05 से भी जाना जाता है। यह एक परमाणु पनडुब्बी है जिसने 750 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। 25 नवंबर, 2015 को, अरिहंत से एक डमी या हथियार-रहित सागरिका मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
- भारत में 14 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, जिनमें से आधा दर्जन में अब विभिन्न प्रकार के अपग्रेड्स किये जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास रूस से 10 साल के पट्टे पर प्राप्त INS चक्र SSN है, और अब अरिहंत भी है। इसके साथ ही अरिहंत क्लास की दो और पनडुब्बियों पर काम चल रहा है।

- लेकिन लंबी दूरी की पनडुब्बी-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBM) पर भारत की प्रगति एक रहस्य है, जिसके सम्बन्ध में आधिकारिक तौर पर पर बहुत कम या नगण्य जानकारी दी गई है। सागरिका मिसाइल का एक अन्य संस्करण, जो अरिहंत पर तैनात है, की रेंज अनुमानित रूप से लगभग 750 किलोमीटर है। चीनी जिन-क्लास की SSBN पर तैनात JL-2 मिसाइलों की सीमा, 4,000 मील (6,400 किमी से अधिक) से अधिक होने के अनुमान हैं।

विज्ञान और तकनीक

कैसे पड़ी मंगल के चंद्रमा पर आड़ी-तिरछी नालियां?

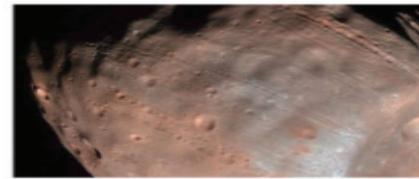


(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

चन्द्रमा के गड्ढे

UPSC दृष्टिकोण: प्रीलिम्स और GS प्रश्नपत्र 3 (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी खंड में)

एक नये अध्ययन से इस विचार को बल मिला है कि मंगल ग्रह के चन्द्रमा फोबोस की सतह पर आड़े-तिरछे गड्ढे, लुढ़कते हुए पथरों द्वारा बनाए गए थे।



उपरोक्त चित्र पर गड्ढों और निशानों के विशिष्ट पैटर्न प्रदर्शित हैं।

- प्लैनेटरी एंड स्पेस साइंस में प्रकाशित शोध।
- ये गड्ढे फोबोस की अनोखी विशेषता हैं। इनकी उत्पत्ति पिछले 40 वर्षों से वैज्ञानिकों के मध्य विवाद का विषय है।
- फोबोस के गड्ढे, जो चंद्रमा की अधिकांश सतह में दिखाई दे रहे हैं, पहली बार 1970 में नासा के मैरिनर और वाइकिंग मिशन में देखे गए थे।
- पिछले कुछ वर्षों में, इनके निर्माण के सम्बन्ध में बहुत से स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर बड़े संघातों के कारण मलबे से निकट स्थित चन्द्रमा पर गड्ढों का निर्माण हुआ है।

वहीं अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह का

गुरुत्वाकर्षण धीरे-धीरे फोबोस को अलग कर रहा है, और ये गड्ढे संरचनात्मक विफलता के लक्षण हैं।

► फोबोस के छोटे आकार और अपेक्षाकृत कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण, फोबोस में स्टिकनी (क्रैटर (बड़ा छेद) होता है) पत्थर लुढ़कते रहते हैं। जबकि अन्य बड़े पिंडों में ये लगभग एक किलोमीटर के बाद रुक जाते हैं।

► यहाँ तक कि कुछ बोल्लर्स (बहुत बड़ी चट्टानें) लुढ़कते हुए लघु आकार के चन्द्रमा के चारों ओर घूमने लग जाते हैं। इस स्टिकनी से बड़े पत्थर या बड़े चट्टान बाहर निकलते हैं। चट्टानों में गति होती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वे कुछ समय के बाद रुक जाती हैं। चूंकि फोबोस में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है इसलिए चट्टानें बहुत दूर नहीं जा पातीं। इसीलिए फोबोस में गड्ढे नज़र आते हैं।

नोट्स

विज्ञान और तकनीक



मानव शरीर में एंटीऑक्सिडेंट्स की भूमिका

(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

एंटीऑक्सीडेंट क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट, गैर-संचारी रोगों को कैसे पराजित कर सकते हैं।

ऑक्सीकरण: जब एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है तो उस परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट उस परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। ऑक्सीकरण को निष्क्रिय करना।

विटामिन ई, सी, ए और कैरोटीनोइड यथा बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, सेलेनियम और लाइकोपीन आदि आहार में प्राथमिक एंटीऑक्सीडेंट के उदाहरण हैं।

एंटीऑक्सीडेंट्स:



एंटीऑक्सीडेंट क्या हैं, और वे कैसे काम करते हैं?

- ब्रह्मांड में सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं।
 - परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के साथ बने होते हैं। इनमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं।
 - परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं।
 - अणु परमाणुओं से मिलते हैं
- मानव शरीर में कई परमाणु मौजूद हैं। परमाणुओं में परिवर्तन (इलेक्ट्रॉन का दान) सीधे प्रोटीन और अणुओं को बदल देगा।

मानव और अन्य जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा अपनी संरचना और कार्य को बनाए रखते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सामूहिक रूप से चयापचय के रूप में जाना जाता है।

- एक अणु को स्थिर होने के लिए, इसमें सही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि अणु इलेक्ट्रॉन को तब खो देते हैं, जब उन्हें नहीं खोना चाहिए तो वे फ्री रेडिकल में बदल सकते हैं।
- फ्री रेडिकल कोशिकाओं में अस्थिर, विद्युत् रूप से चार्ज किए गए अणु हैं, जो अन्य अणुओं (जैसे डीएनए) के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- वे चेन रिएक्शन प्रारम्भ कर सकते हैं और अन्य अणुओं को फ्री रेडिकल में परिवर्तित कर सकते हैं।
- एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। इसके बाद अतिरिक्त फ्री रेडिकल्स को स्थिर अणुओं में परिवर्तित किया जाता है।
- इससे फ्री रेडिकल्स के नकारात्मक प्रभाव में कमी आयी है।

एंटीऑक्सिडेंट्स और फ्री रेडिकल्स दोनों महत्वपूर्ण हैं

- फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बैक्टीरिया को मारते हैं और वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- फ्री रेडिकल हमारी प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और बैक्टीरिया को मार देते हैं।
- यदि फ्री रेडिकल बड़ी मात्रा में हैं तो वे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे।

नोट्स

नासा का

केप्लर टेलीस्कोप रिटायर



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से

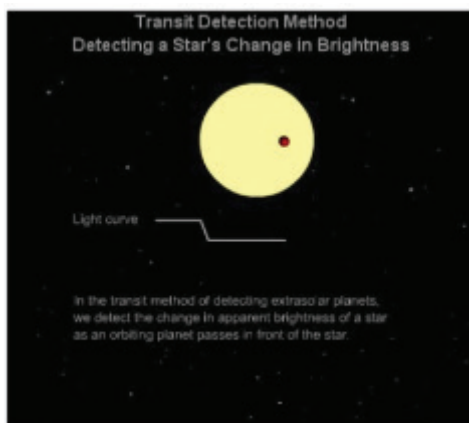
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण (2019 अथवा 2020)

नासा ने केप्लर स्पेस टेलीस्कोप को सेवामुक्त किया:

- ▶ नासा ने 2009 में केप्लर स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया था। यह नासा का पहला प्लेनेट-हंटिंग मिशन (ग्रहों की खोज करने वाला मिशन) था।
- ▶ इसका नाम जर्मन गणितज्ञ और खगोलविद जोहान्स केप्लर के नाम पर रखा गया था।
- ▶ अपने नौ साल के जीवन के दौरान, केप्लर ने 530,506 तारों को देखा और 2,662 ग्रहों का पता लगाया।

केप्लर स्पेस टेलीस्कोप:

- ▶ नासा ने 2009 में केप्लर स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया था। यह नासा का पहला प्लेनेट-हंटिंग मिशन (ग्रहों की खोज करने वाला मिशन) था।
- ▶ इसका नाम जर्मन गणितज्ञ और खगोलविद जोहान्स केप्लर के नाम पर रखा गया था।
- ▶ अपने नौ साल के जीवन के दौरान, केप्लर ने 530,506 तारों को देखा और 2,662 ग्रहों का पता लगाया।



ट्रांजिट डिटेक्शन विधि:

- ▶ यदि किसी तारे के पास एक ग्रह है, तो वह तारा उस ग्रह की कक्षा में होगा।
- ▶ केप्लर का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि जब भी ग्रह तारे के सामने आता है, तो यह केप्लर के लिए तारे के प्रकाश में कितनी कटौती करता है।
- ▶ इससे हम देख सकते हैं कि वह कौन सा ग्रह है।

गोल्लिऑक्स जोन के अनुसार तारे और ग्रह के बीच की दूरी एकदम सही होनी चाहिए।

एक्जोप्लेनेट

एक्जोप्लेनेट, एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा नहीं करता तथा एक अलग तारे, स्टेलर रेमनेन्ट या ब्राउन ड्वार्फ के चारों ओर घूमता है। इसे एक्स्ट्रासोलर ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सूर्य के समान किसी तारे की परिक्रमा करने वाला ऐसा ग्रह सर्वप्रथम 1995 में देखा गया था। वर्तमान में लगभग 3,600 एक्जोप्लेनेट देखे जा चुके हैं। इनमें पृथ्वी के आकार के चट्टानी-ग्रहों से लेकर बृहस्पति जैसे गैस के बड़े ग्रह शामिल हैं।

केप्लर के बाद, अगला क्या?

एक्जोप्लेनेट, एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा नहीं करता तथा एक अलग तारे, स्टेलर रेमनेन्ट या ब्राउन ड्वार्फ के चारों ओर घूमता है। इसे एक्स्ट्रासोलर ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सूर्य के समान किसी तारे की परिक्रमा करने वाला ऐसा ग्रह सर्वप्रथम 1995 में देखा गया था। वर्तमान में लगभग 3,600 एक्जोप्लेनेट देखे जा चुके हैं। इनमें पृथ्वी के आकार के चट्टानी-ग्रहों से लेकर बृहस्पति जैसे गैस के बड़े ग्रह शामिल हैं।

ट्रांजिटिंग एक्जोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) नासा के एक्सप्लोरर प्रोग्राम के लिए एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। इसे केप्लर मिशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से 400 गुना बड़े क्षेत्र में पारगमन विधि (transit method) का उपयोग करके एक्जोप्लेनेट की खोज के लिए डिज़ाइन किया गया है। जहाँ केप्लर के प्रेक्षण पर 640 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे, वहीं TESS की लागत केवल 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर (साथ ही प्रेक्षण के लिए 87 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है।

नोट्स

इसरो का जीसैट-29 सैटेलाइट लॉन्च



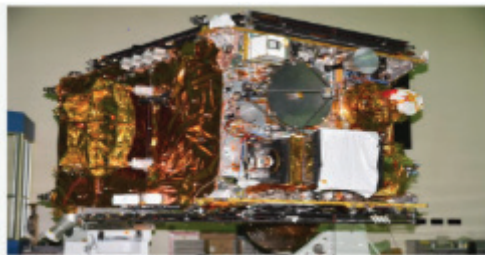
(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

समाचारों में क्या है?

14 नवंबर, 2018 को, इसरो ने श्रीहरिकोटा (आंध्रप्रदेश) में सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने संचार उपग्रह GSAT-29 का अपनी दूसरी विकास उड़ान GSLV-Mk III D2 (लॉन्च वाहन) पर प्रक्षेपण किया।

GSAT-29 की विशेषताएँ

14 नवंबर, 2018 को, इसरो ने श्रीहरिकोटा (आंध्रप्रदेश) में सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने संचार उपग्रह GSAT-29 का अपनी दूसरी विकास उड़ान GSLV-Mk III D2 (लॉन्च वाहन) पर प्रक्षेपण किया।



- ▶ लिफ्ट-ऑफ पर 3,423 किलोग्राम वजन के साथ, GSAT-29 भारत से प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी उपग्रह है।
- ▶ 10 वर्षों के मिशन काल (जीवन काल) के साथ, यह इसरो द्वारा निर्मित 33 वां संचार उपग्रह है।
- ▶ इसरो के मुताबिक, "GSAT-29 एक मल्टी-बीम, मल्टीबैंड संचार उपग्रह है।"
- ▶ इंटरनेट, टेलीफ़ोनिक संचार के माध्यम से संचार।
- ▶ इसके पेलोड को मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पहाड़ी और भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ▶ इससे दुर्गम क्षेत्रों के बीच संपर्क में सुधार होगा।
- ▶ हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग में सहायता के लिए इसमें एक जियो हाई-रेज़ॉल्यूशन कैमरा भी है।
- ▶ पहली बार, एक ऑप्टिकल संचार पेलोड का उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाएगा। उच्च श्रृंखला उपग्रहों का संयोजन (GSAT-19, GSAT-29, GSAT-11 और GSAT-20) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक उच्च गति इंटरनेट प्रदान करेगा।

GSLV MK III की विशेषताएँ

GSLV और PSLV के बीच क्या अंतर है?
PSLV (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन) और GSLV

(भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन) इसरो द्वारा विकसित उपग्रह-प्रक्षेपण वाहन (रॉकेट) हैं।

PSLV

PSLV मुख्य रूप से लगभग 1750 किलोग्राम तक लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान के साथ "पृथ्वी अवलोकन" या "रिमोट सेंसिंग" उपग्रहों को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

▶ PSLV एक चार चरणों वाला प्रक्षेपण वाहन है जिसमें पहले और तीसरे चरण में सॉलिड रॉकेट मोटर्स और दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है।

▶ PSLV द्वारा प्रक्षेपित किए गए कुछ उल्लेखनीय पेलोडों में भारत की पहला चंद्रमा सम्बन्धी जांच यान चंद्रयान -1, भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन- मंगल ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान) और भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला-एस्ट्रोसेट शामिल हैं।

▶ GSLV मुख्य रूप से उच्च-दीर्घवृत्तीय (आमतौर पर 250 x 36000 किलोमीटर) भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में संचार-उपग्रहों को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

▶ GSLV, MK III - यह इसरो द्वारा विकसित तीन चरणीय हैवी-लिफ्ट प्रक्षेपण वाहन है।

▶ इस वाहन में दो ठोस स्ट्रैप-ऑन, एक कोर लिक्विड बूस्टर और एक क्रायोजनिक उच्च चरण उपस्थित है।

नोट्स

राजनीति

सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद, सीबीआई के लिए सुधार

सीबीआई के बारे में:

- ▶ सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है।
- ▶ इसे संधानम समिति की अनुशंसा के बाद गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा 1963 में स्थापित किया गया था।
- ▶ इस एजेंसी की उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई जिसे 1946 में भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय सरकारी पुलिस फ़ोर्स के रूप में स्थापित किया गया।
- ▶ भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में सीबीआई का नियंत्रण सीवीसी के पास रहता है जबकि अन्य मामलों में इसका नियंत्रण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास है।
- ▶ मुख्यालय- नई दिल्ली। सिद्धांत - उद्योग, निष्पक्षता, ईमानदारी

एजेंसी की कठिनाईयां:

राजनीतिक दबाव:

- ▶ चूँकि दस प्रतिशत से कम मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और जाँचों के राजनीतिकरण के आरोप में कुछ सच्चाई भी है;
- ▶ इसलिए हाई प्रोफाइल जाँचों में विश्वसनीय टीम की आवश्यकता होती है जोकि बाहरी दबावों के सामने ना झुके।

केस समाप्त होने में देरी:

- ▶ कई मामलों में अभी भी गतिरोध की स्थिति है। जांच में ऐसे विलम्बों के कारण एजेंसी की विश्वसनीयता में कमी आ जाती है।

रोजगार के माध्यम के रूप में अलोकप्रिय:

- ▶ सीबीआई में काम करना आज युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि इस एजेंसी में नौकरी पाना एक कठिन कार्य है।

राज्य के साथ समन्वय की अनिवार्यता:

- ▶ सीबीआई, सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के अनुसार कार्य करती है अतः यह पुलिस की तरह मानी जाती है। चूँकि पुलिस संविधान की राज्य सूची में है, इसलिए यह राज्य का मामला भी बन जाती है और एजेंसी को राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।
- ▶ ऐसी स्थितियों में, प्रत्येक मामले में राज्य की प्राधिकारिता या उससे अनुमति लेने का मुद्दा सामने आता है। कई बार राज्य से अनुमति मिलने में देर हो जाती है जिससे जांच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सीबीआई की स्वायत्तता पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय:

- ▶ विनीत नारायण के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को स्वायत्त बनाने का सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि सीबीआई के निदेशक
- ▶ उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त - समिति के अध्यक्ष तथा गृह सचिव एवं डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के सचिव इसके सदस्यों के रूप में।
- ▶ पूर्व में, उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सीबीआई को 'केज़्ड पैरेंट विद मेनी मास्टर्स' या 'पिंजड़े में बंद तोते' के नाम से सम्बोधित किया था।

सरकार की पहलें:

- ▶ सरकार ने सीबीआई को प्रभावी अभियोजन के लिए एक अलग न्यायालय, सीबीआई न्यायालय, की सुविधा प्रदान की है।
- ▶ 2017 में 3 साल की अवधि के लिए डीएसपी के पद की भर्ती के लिए यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के परामर्श से छूट दी गई है।
- ▶ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी और आईआईएम बैंगलोर से प्रशिक्षण के जरिए सीबीआई अधिकारियों के लिए उन्नत सर्टिफाइड कोर्स बनाये गये हैं जिससे जांच कौशल, फॉरेंसिक डेटा संग्रह, साक्ष्य का संग्रह इत्यादि में सुधार किया जा सकेगा।
- ▶ सीबीआई में प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गयी हैं।

राजनीति

सीबीआई बनाम राज्य



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

सामान्य सहमति की वापसी

आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने हाल ही में सीबीआई को अपने संबंधित राज्यों में मामलों की जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। अभी के लिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीबीआई नए मामलों की जांच नहीं कर पाएगी।

इसके पीछे का कारण क्या है?

- ▶ दोनों राज्य सरकारों ने कहा कि वे एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के मध्य हुई झपड़ों तथा इससे सामने आयी आंतरिक कलह की पृष्ठभूमि के कारण सीबीआई में अपना विश्वास खो चुके हैं।

- उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र विपक्षी दलों को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए सीबीआई का उपयोग कर रहा है।
 - हालांकि, केंद्र का तर्क है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी राज्य के लिए कोई संप्रभुता नहीं है।
- केंद्र ने राज्यों पर आरोप लगाया है कि राज्यों का आरोप किसी एक विशिष्ट केस से नहीं, बल्कि जाँच में अन्य बातों के बाहर निकल आने के सामान्य भय से प्रेरित है।

सामान्य सहमति क्या है?

- कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं। सीबीआई, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित है, जो कि राज्य में जाँच प्रक्रिया को करने के लिए राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है। सीबीआई को किसी भी राज्य में जाँच के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है।
- केस की अवस्था के आधार पर दो प्रकार की सहमति होती है: विशिष्ट सहमति और सामान्य सहमति (सीबीआई किसी पर भी केस फाइल कर सकती है)
 - केंद्र सरकार, अधिसूचना के माध्यम से सीबीआई से आयकर उल्लंघन, राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र, जासूसी इत्यादि मामलों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जाँच करने के लिए कह सकती है।
- नोट्स:
- चूंकि कानून और व्यवस्था राज्यों से संबंधित है, इसलिए सभी राज्य आम तौर पर सीबीआई को इन जांचों के लिए सामान्य सहमति देते हैं।
 - 'सामान्य सहमति' आम तौर पर सीबीआई को संबंधित राज्य में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी जाँच बिना किसी अवरोध के करने के लिए दी जाती है।
 - उदाहरण के लिए, यदि सीबीआई मुंबई में पश्चिमी रेलवे क्लर्क के खिलाफ रिश्वत के आरोप की जांच करना चाहती है, तो उसे सहमति के लिए आवेदन करना होगा।

सीबीआई इन दो राज्यों में किसी मामले की जाँच नहीं कर सकती?

- हालांकि, सीबीआई के पास अभी भी सामान्य सहमति प्राप्त पुराने पंजीकृत मामलों की जाँच करने का अधिकार होगा।
- साथ ही, देश में कहीं भी पंजीकृत मामलों, जिनमें आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रहे रहे लोगों की सहभागिता होगी, में भी सीबीआई का न्यायक्षेत्र इन राज्यों तक विस्तृत हो जायेगा।
- इसका मतलब यह है कि जब तक राज्य सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं देगी, तब तक सीबीआई अधिकारी उस राज्य पर प्रवेश करने करने पर एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों को खो देंगे।
- इसके अंतर्गत उन्हें हर मामले और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर हो रही हर जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है।
- पिछले कुछ वर्षों में, कई राज्यों ने सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सहित सामान्य सहमति वापस ले ली है, जो की हाल में उठाये गए एक कदम का उदाहरण है।

सीबीआई दो राज्यों में एक मामले की पूछताछ नहीं कर सकता है?

- अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत दोनों राज्यों से सामान्य सहमति वापस ले ली गई है।
- अधिनियम की धारा 6 दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्य को राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य के किसी भी क्षेत्र में शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोकती है।

- हालांकि, सीबीआई के पास अभी भी सामान्य सहमति प्राप्त पुराने पंजीकृत मामलों की जाँच करने का अधिकार होगा।
- साथ ही, देश में कहीं भी पंजीकृत मामलों, जिनमें आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रहे रहे लोगों की सहभागिता होगी, में भी सीबीआई का न्यायक्षेत्र इन राज्यों तक विस्तृत हो जायेगा।
- इस पर अस्पष्टता है कि एजेंसी, दोनों राज्यों से जुड़े पुराने मामलों में बिना राज्य की सहमति के खोजबीन कर सकती है या नहीं।

नए मामलों में क्या होता है?

- सहमति वापस लेने से, सीबीआई को केवल आंध्र और बंगाल के अधिकार क्षेत्र में मामला दर्ज करने से रोक दिया जाएगा।
- सीबीआई अभी भी दिल्ली में मामला दर्ज कर सकती है और दोनों राज्यों के अंदर लोगों की जांच जारी रख सकती है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि मामला उस राज्य में पंजीकृत नहीं है, तो एजेंसी 'सामान्य सहमति' वापस ले लेने वाले राज्य में किसी की भी जाँच कर सकती है।
- यह निर्णय छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मामले के संबंध में दिया गया है, जो स्वयं केसेज के आधार पर सहमति देता है

मुख्य बातें:

- इस प्रकार, यदि एक राज्य सरकार का मानना है कि सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों या सदस्यों को केंद्र के आदेश पर सीबीआई द्वारा निशाना बनाया जा सकता है और सामान्य सहमति वापस लेने से उनको बचाया जा सकता है तो यह एक गलत धारणा होगी।
- सीबीआई अभी भी दिल्ली में ऐसे मामले दर्ज कर सकती है, जिन में अपराध का कुछ हिस्सा दिल्ली राज्य से संबंधित हो और अभी भी मंत्रियों तथा विधायकों को गिरफ्तार कर मुकदमा चला सकती है।

नोट्स

प्राइवेट मेंबर बिल क्या है?



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से: मुख्य परीक्षा GS प्रश्नपत्र 2

भारतीय संसद में निजी सदस्य विधेयक क्या है?

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के पुनः उभरने पर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा है कि वह राम मंदिर पर एक निजी सदस्य विधेयक लाएंगे।

भारत का लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र है। इसके तीन स्तम्भ हैं:

विधायिका: कानून बनाने वाला निकाय

कार्यपालिका: कानून का क्रियान्वयन

न्यायपालिका: कानून उचित संरचना में है या नहीं।

उदाहरण

यदि हमें परिवहन से सम्बंधित कोई कानून बनाना है तो इसकी विषयवस्तु परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्मित की जाती है जिसे कैबिनेट मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मंत्री, संसद का हिस्सा होते हैं। वे संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित करते हैं। यदि कोई विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो वो एक अधिनियम का रूप ले लेता है।

दो लोग ऐसा कर सकते हैं:

ऐसा कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, उसे एक निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है। संसद की प्रमुख भूमिका विचार-विमर्श करना और कानून बनाना है। मंत्री और निजी सदस्य, दोनों कानून बनाने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं।

निजी सदस्य विधेयक उन सांसदों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं। इनका उद्देश्य सरकार का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करना है जो कि निजी सदस्य के अनुसार, महत्वपूर्ण हैं। साथ ही इसका उद्देश्य मौजूदा विधायी ढांचे में व्याप्त अंतरालों को सम्बंधित करना है।

सांसदों को स्थानीय लोगों की सहायता हेतु कानून बनाने की स्वतंत्रता दी गयी है, जिसे निजी सदस्य विधेयक कहते हैं।

राज्य सभा और लोकसभा

► एक निजी सदस्य के विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल) की स्वीकृति राज्यसभा के सभापति द्वारा तय की जाती है।

► लोकसभा के मामले में, यह स्वीकृति अध्यक्ष देता है। इसकी प्रक्रिया दोनों सदनों के लिए लगभग समान है।

विधेयक को प्रस्तावित करने से पहले निजी सदस्य को एक महीने पूर्व नोटिस देनी होती है ताकि उसे सूचीबद्ध किया जा सके। सदन का सचिवालय सूचीबद्ध होने से पहले संवैधानिक प्रावधानों और कानून से सम्बंधित नियमों के अनुपालन के लिए इसकी जांच करता है।

राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय

ये लोकसभा और राज्य सभा को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। सचिवालय नज़र रखते हैं कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष यह तय

नहीं। इसके बाद राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष यह तय करते हैं कि बिल को अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।

राज्यसभा में निजी सदस्य विधेयक

► राज्य सभा में बिलों की चर्चा के अनुक्रम का निर्णय करने के लिए मतदान किया जाता है। यदि मतदान में कोई विधेयक सफल होता है, तो उसे सदन में विचाराधीन विधेयक पर चर्चा समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

► पिछले तीन वर्षों में, राज्यसभा में 165 निजी सदस्य विधेयकों की शुरुआत की गयी; जिनमें से 18 पर चर्चा हुई।

► एक ऐसा निजी सदस्य विधेयक जिसे प्रस्तावित कर दिया गया है परन्तु राज्य सभा में उस पर चर्चा नहीं की गई है, सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर समाप्त हो जाता है।

► चर्चा के समापन पर, विधेयक प्रस्तावित करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है, या वह इसे पारित करवाने के लिए आगे बढ़ सकता है।

► बाद के मामले में, विधेयक पर वोट लिया जाता है, और यदि निजी सदस्य को सदन का समर्थन मिलता है, तो यह पारित हो जाता है।

► 1977 में, राज्यसभा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के लिए एक निजी सदस्य का विधेयक पारित किया।

नोट

► 1997 तक, निजी सदस्य एक सप्ताह में तीन बिल पेश कर सकते थे। इससे वो बिल इकट्ठे होते गए और उन्हें पेश तो किया गया पर उन पर चर्चा नहीं की गई। इसके कारण तत्कालीन सभापति के आर नारायणन ने कार्यभार कम करने के लिए निजी सदस्यों के विधेयकों की अधिकतम संख्या 3 प्रति सत्र निश्चित कर दी।

► जहाँ सरकारी बिलों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और चर्चा की जा सकती है, वहीं निजी सदस्यों के विधेयक केवल शुक्रवार को ही पेश किए जा सकते हैं और उनपर चर्चा केवल शुक्रवार को ही जा सकती है।

► राज्यसभा में पिछले तीन सालों में केवल 20 दिन ही इन विधेयकों पर एक ऐसा निजी सदस्य विधेयक जिसे प्रस्तावित कर दिया गया है परन्तु राज्य सभा में उस पर चर्चा नहीं की गई है, सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर समाप्त हो जाता है। चर्चा की गयी या इन्हें प्रस्तावित किया गया।

► निजी सदस्य के बिलों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया।

► निर्धारित शुक्रवार को, निजी सदस्य विधेयक की शुरुआत के लिए एक प्रस्ताव रखता है, जिसका आमतौर पर विरोध नहीं होता है।

► पेश किए जाने वाले निजी सदस्य के बिलों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही चर्चा के लिए लिया जाता है।

नोट्स

महाराष्ट्र में चुनावी सुधार



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

महाराष्ट्र में चुनाव सुधार

यह किस बारे में है:

MSEC (महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यदि चुनाव में NOTA को अधिकतम वोट मिले, तो पुनः चुनाव आयोजित कराये जायेंगे। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने भी नोटा को 'काल्पनिक उम्मीदवार' घोषित कर दिया है।

राज्य आयोग द्वारा निर्णय:

यह किस बारे में है:

केंद्रीय चुनाव आयोग की संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करने की ज़िम्मेदारी है। राज्य चुनाव आयोग, राज्यों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में भूमिका निभाता है;

- मुख्य रूप से नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों में। राज्यों के स्थानीय निकाय चुनावों में अब NOTA इस भूमिका को निभाएगा। MSEC (महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग) ने NOTA को 'काल्पनिक उम्मीदवार' का हक दिया है।
- यह निर्णय राज्य के भीतर सभी नगरपालिका परिषदों एवं ग्राम पंचायतों के चुनावों तथा उपचुनावों पर लागू होगा।

NOTA, धारा 49 (O) और फॉर्म 17A:

- ईवीएम में नोटा शुरू करने का निर्णय 27 सितंबर, 2013 को आया, जब 'पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज' (एक एनजी-ओ) ने चुनाव में नकारात्मक मतदान की मौजूदा प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
- चुनाव आचरण नियम 1961 की धारा 49 (ओ) के तहत, एक मतदाता एक विशिष्ट फॉर्म 17 'ए' पर अपना चुनावी क्रमांक डाल सकता है और नकारात्मक वोट डाल सकता है। तब पीठासीन अधिकारी फॉर्म में टिप्पणी करके इसे मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित करवाएगा। धोखाधड़ी या मत का दुरुपयोग रोकने के लिए यह किया गया था।
- लेकिन फॉर्म 17 'ए' के साथ शंकाएँ थी: पहली कि यह मतदाता की पहचान प्रकट करेगा जोकि चुनावी नैतिकता के विरुद्ध है और साथ ही मतदाता के जीवन को खतरे में डाल सकता है।
- दूसरी यह कि अधिकारी फॉर्म 17(A) में मतदाता के रिमार्क के आधार पर नकारे जाने का कारण जान जायेंगे।
- NOTA के आधिकारिक प्रतीक चिह्न की रचना सितम्बर, 2015 में अहमदाबाद स्थित नेशनल स्कूल ऑफ़ डिज़ाइन द्वारा की गयी।

निर्णय का महत्व:

- चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में नोटा अभी भी मान्य है लेकिन मतदाताओं के लिए एक तरह से 'अप्रभावी' विकल्प है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में यदि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत के विरुद्ध भी मत मिलते हैं, तो भी वह उस क्षेत्र में विजेता घोषित किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 100 मतदाता हैं अगर 95 लोग भी नोटा के लिए वोट देते हैं और शेष 5 वोट किसी अन्य उम्मीदवार को, तब भी 95 खिलाफ मतों के बावजूद उम्मीदवार को ही विजेता घोषित किया जाएगा।
- अब यह कम से कम महाराष्ट्र के स्थानीय क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में सुधार करेगा।
- राजनीतिक दलों को अच्छे, मेहनती और मेधावी उम्मीदवारों को पेश करना होगा।
- ज्यादातर आबादी अभी भी मानती है कि नोटा इसकी निष्क्रियता के कारण किसी भी तरह चुनावी विकल्प नहीं है और उन्हें उन उम्मीदवारों के लिए वोट देना पड़ता है, जिन्हें मतदाता समर्थन देना ही नहीं चाहते। लेकिन अब महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में उन मतदाताओं के पास अपनी पसंद को प्रदर्शित करने का एक शानदार मौका है।
- यह राज्य में सत्ता और अधिकारी-वर्ग के विकेंद्रीकरण को भी मजबूत कर सकता है, जैसे कि 73 वें और 74 वें संविधान संशोधनों को क्रमशः पंचायती राज और नगर पालिकाओं में शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए किया गया था।

एमएसईसी(MSEC) द्वारा अन्य पहलें:

- महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के नामांकन और हलफनामे को पूर्णतः डिजिटल तरीके से दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है, पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए।
- उम्मीदवारों की जानकारी का तत्काल मतदाताओं तक प्रसारित की जा सकती है।
- यह देश का पहला राज्य निर्वाचन-आयोग निकाय है, जिसने लेखापरीक्षित खातों की जानकारी जमा करने में विफलता के बाद 250 से अधिक राज्याधीन राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी है।
- एमएसईसी पहला राज्य निर्वाचन-आयोग निकाय है, जिसने चुनाव संबंधी व्यय खातों का खुलासा नहीं करने के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया।

नोट्स

करतार कोरिडोर पर कैबिनेट की मंजूरी



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

यह किस बारे में है?:

कैबिनेट ने पाकिस्तान के करतारपुर साहिब जाने की इच्छा रखने वाले तीर्थयात्रियों के आवागमन को सुचारू करने के लिए एक गलियारे के विकास को मंजूरी दे दी।

पृष्ठभूमि:

गुरुद्वारा दरबार करतारपुर साहिब:

- ▶ पाकिस्तान के पंजाब के नोरावल जिले में करतारपुर में एक गुरुद्वारा है।
- ▶ लाहौर से 120 किमी दूर स्थित, लेकिन भारतीय सीमा से केवल 3-4 किलोमीटर दूर।
- ▶ रावी नदी के तट पर 1522 ईस्वी में स्थापित।
- ▶ सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक देव द्वारा सिख समुदाय को एकत्रित किया गया और गुरुद्वारा का निर्माण किया।
- ▶ गुरु नानक देव ने अपनी मृत्यु (1539 में) तक जीवन के अंतिम 18 वर्ष इस गुरुद्वारे में बिताए।
- ▶ चूंकि, गुरु नानक देव की यहाँ मृत्यु हुई थी, अतः यह स्थान दुनिया भर के और भारत के सिखों के लिए अत्यंत पवित्र है।

करतारपुर कॉरिडोर क्या है?:

- ▶ सिख समुदाय, विशेष रूप से भारतीयों, ने सरकार से आग्रह किया था कि वह इस जगह पर आवागमन आसान करे।
- ▶ 1999 में पहली बार आग्रह, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिल्ली-लाहौर बस यात्रा के दौरान किया गया था। (जिसे आधिकारिक तौर पर सदा-ए-सरहद के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्घाटन 19 फरवरी, 1999 को हुआ था)। उस बस यात्रा में, करतारपुर भी एक बस स्टॉप था।
- ▶ अनुरोध के बाद, साल 2000 ईस्वी के बाद पाकिस्तान सरकार ने भारतीय सिखों को बिना किसी वीजा की आवश्यकता के गुरुद्वारा जाने की इजाजत दी। गलियारा शुरू होता है - डेरा बाबा नानक गांव, गुरुदासपुर, पंजाब, भारत।
- ▶ समाप्ति - गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, पाकिस्तान।
- ▶ लंबाई - 4 किमी, दोनों देशों की तरफ 2-2 किमी।

कमर बाजवा - नवजोत सिद्द वार्तालाप:

क्रिकेटर से सांसद बने नवजोत सिंह सिद्द पाकिस्तान के निर्वाचित प्रधान मंत्री इमरान खान की शपथ ग्रहण समारोह में गए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर बाजवा ने एक मुलाकात में उन्हें बताया कि पाकिस्तान शीघ्र ही गलियारे के निर्माण की अनुमति देगा। लेकिन यह सिर्फ एक अनौपचारिक प्रस्ताव था।

पृष्ठभूमि:

धार्मिक मंदिरों के दौरे पर प्रोटोकॉल 1974 - प्रोटोकॉल दोनों देशों के तीर्थयात्रियों के लिए है। दोनों देशों में पूजा स्थलों की एक सूची है। सूचीबद्ध पूजा स्थलों के लिए भारत सहित अन्य देशों को वीजा की आवश्यकता है। लेकिन पाकिस्तान ने वीजा आवश्यकता से करतारपुर गुरुद्वारा को छूट दी है। इसलिए, इस वजह से करतारपुर कॉरिडोर के लिए एक अलग संधि की आवश्यकता होगी क्योंकि इसे प्रोटोकॉल 1974 से छूट दी गई है।

नोट्स

अभिशासन और सामाजिक मुद्दे

गुजरात प्रवासित पलायन



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से- GS प्रश्नपत्र 2

संकट का प्रारंभ:

गुजरात में एक प्रवासी श्रमिक द्वारा एक नाबालिग लड़की के बलात्कार ने लोगों को गुस्से से भर दिया। बलात्कारी बिहार का मूल निवासी था जो गुजरात काम करने के लिए आया था। इस अपराध से उग्र लोगों ने बिहार के लोगों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया

इस समस्या के लिए प्रस्तावना:

- गुजरात एक बेहद औद्योगिकीकृत राज्य है और वहाँ अकुशल मजदूरों की बहुत मांग है। शेष भारत से लोग नौकरी की तलाश में गुजरात आते हैं, हालाँकि उनमें से अधिकतर लोगों में उचित कौशल नहीं होता। इस प्रकार भारत के विभिन्न भागों से सस्ते श्रमिक गुजरात पहुँचते हैं।
- चूँकि गुजरात में शेष भारत से आये हुए मजदूर सस्ते में मिल जाते हैं, अतः गुजरात के मूल निवासियों को राज्य में नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस स्थिति को संबोधित करने के लिए, गुजरात सरकार ने निर्णय लिया है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 80 प्रतिशत रोजगार गुजरात के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होगा।
- नाबालिग लड़की के बलात्कार के कारण भीड़ ने कई बार प्रवासी श्रमिकों पर हमले किये।

देश के भीतर आंतरिक प्रवासन के प्रभाव:

- अलग-अलग राज्यों की असमान वृद्धि की समस्या पहले से ही व्याप्त है और यदि सम्बंधित सरकारों ने राज्य के लोगों को नौकरी प्रदान करने की समुचित व्यवस्था नहीं की तो विभिन्न राज्यों से प्रवासन के कारण यह समस्या व्याप्त रहेगी।
- विवाह और रोजगार, संकट की इस आग में ईंधन का काम करते हैं।
- बेहतर नौकरियों की तलाश में, गाँव से शहरों की ओर प्रवासन के कारण निवास के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती तथा इसके कारण झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है।
- और इस तरह शहरी क्षेत्रों में भीड़ शहर के संसाधनों में भारी कमी ला रही है, जिससे लोगों के बीच दरार पैदा हो रही है।
- मतदान में समस्या- दूसरे राज्यों में रहने के कारण, प्रवासी कई बार अपने मूल राज्य में चल रहे चुनावों में मतदान कर नहीं जा पाते।

यह गुजरात को कैसे प्रभावित करता है:

- गुजरात ने औद्योगीकरण तथा उद्योग और सेवा क्षेत्र के माध्यम से आर्थिक विकास का मॉडल अपनाया है। इन क्षेत्रों के लिए, अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिक इस आवश्यकता को पूरा करते हैं।

► छोटे और मध्यम उद्योग देश के बाकी हिस्सों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सस्ते श्रम पर निर्भर थे। अब, उन उद्योगों को आवश्यक मात्रा में सस्ते श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं जिसके कारण उत्पादित वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

► प्रवासी श्रमिकों के अपने मूल राज्यों में लौटने की वजह से निर्माण के कई कामों में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है।

श्रम कानून की कमी

► अधिकांश प्रवासी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से आते हैं। गुजरात और अन्य राज्यों में, उचित दस्तावेजों की कमी के कारण, नियोजता श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं।

► प्रवासी श्रमिकों को उचित मजदूरी भी नहीं मिल रही है। उन्हें केवल न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है जो केवल उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जीवन स्तर और सामाजिक स्थिति को सुधारने में सहायक नहीं है। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिक बहुत जोखिम वाले स्थानों पर भी काम करते हैं। पूर्व में, इन समस्याओं को संबोधित करने वाले दो कानून थे:

- अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

नोट

- वर्तमान में भारत में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी 16% है।
- जीडीपी में 10% की वृद्धि ने नौकरियों में केवल 1% की वृद्धि दर्ज की है।
- श्रमिकों की निम्न मजदूरी के कारण राष्ट्र के उत्तरी राज्य अत्यधिक प्रभावित होते हैं।

नोट्स

भारत में आंतरिक प्रवासन



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

आंतरिक प्रवासन को संचालित करने वाले कारक क्या हैं?

आंतरिक प्रवासन पुश और पुल कारकों द्वारा संचालित किया जा सकता है।

- ▶ भारत में, हाल के दशकों में, कृषि संकट (पुश फैक्टर) और शहरी क्षेत्रों में बेहतर तनख्वाह वाली नौकरियों में वृद्धि (पुल फैक्टर) आंतरिक प्रवासन के चालक रहे हैं।
- ▶ उदाहरण: Uber eats - शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में देखा जा सकता है।
- ▶ साथ में, कृषि में बेरोजगारी या अल्परोजगार की समस्या, प्राकृतिक आपदाओं, और आगत/निर्गत (input/output) बाजार की खामियों ने भी इसमें योगदान दिया है।
- ▶ आंकड़ों से पता लगता है कि रोजगार की तलाश क्षेत्रों के बीच प्रवासन का बिना किसी संशय के मुख्य कारण है।
- ▶ अधिकांश प्रवासन, बेरोजगारी के कारण होता है। बेहतर शिक्षा और मानक जीवन स्तर की तलाश भी एक कारक है।

प्रवासन से जुड़े लाभ क्या हैं?

- ▶ आंतरिक प्रवासन के कारण परिवारों के जीवनस्तर में वृद्धि हुई है। खासकर उच्च कौशल, सामाजिक संबंधों और संपत्ति वाले लोगों के लिए।
- ▶ निचली जातियों और जनजातियों से संबंधित प्रवासियों ने भी ग्रामीण इलाकों में अपने घरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त आय कमाई है।
- ▶ घर पर पीछे छूटे पारिवारिक सदस्यों की ऋण योग्यता में सुधार हुआ है, जिससे वे अब 'लोन' आसानी से ले सकते हैं।

आंतरिक प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं क्या हैं?

- ▶ अनौपचारिक विकास - एक प्रवासी की कौशल हीनता, श्रम बाजार में प्रवेश करने में एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करती है।
- ▶ 'शहरी अनौपचारिक' अर्थव्यवस्था को भारत जैसे देशों में गलत तरीके से एक क्षणिक घटना के तौर पर समझा गया है, जबकि यह वर्षों से फैलता ही गया है और अधिकतम शहरी रोजगार के लिए जिम्मेवार है।
- ▶ नौकरियां - शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में अधिकतर नौकरियां अपर्याप्त भुगतान करती हैं और स्व-नियोजित श्रमिकों को शामिल करती हैं जो मजदूरी युक्त श्रम खोजने में असमर्थता के कारण छोटे उत्पादन में संलग्न हो जाते हैं।
- ▶ विभिन्न प्रकार के भेदभाव, जो कि प्रवासियों को बेहतर भुगतान करने वाली नौकरियों के लिए सातक होने की

अनुमति नहीं देते हैं।

- ▶ प्रवासी श्रमिक, गैर-प्रवासी श्रमिकों की तुलना में महज दो-तिहाई ही कमाते हैं।

जीवन यापन की लागत

- ▶ इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रवास की एक बड़ी लागत लगानी पड़ती है, जिसमें 'सर्च या खोज-लागत' और धोखाधड़ी का खतरा शामिल है।
- ▶ अक्सर इन लागतों में वृद्धि होती है क्योंकि ये राज्य द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रणाली के बाहर हैं।
- ▶ अक्सर उधार लेने से उन्हें ऋण का भुगतान करने के लिए अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

रोजगार को प्रभावित करने वाले कारक

- ▶ एक अध्ययन के मुताबिक, 20% से कम शहरी प्रवासियों पर ही पूर्वनियोजित (Prearranged) नौकरियाँ थी और लगभग दो तिहाई लोग शहर में प्रवेश के एक हफ्ते के भीतर नौकरी खोजने में कामयाब रहे।
- ▶ शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ, शहरों में एक पूर्वनियोजित नौकरी के साथ प्रवास की संभावना में वृद्धि हुई है।
- ▶ प्रवास से पूर्व ही, सोशल नेटवर्क के साथ रोजगार उपलब्धता संबंधी जानकारी की प्राप्ति ने बेरोजगारी के समय को स्पष्ट रूप से कम किया है।
- ▶ सोशल नेटवर्क्स ने न केवल मूल जगह पर ही प्रवासियों को रोजगार के अवसरों पर जानकारी दी है, बल्कि विश्वास उपलब्ध कराने के कारण एक सोशल कैपिटल के तौर पर भी काम किया है।
- ▶ जहाँ एक ओर प्रवासी अपने मूल के आधार पर आपस में बात करते हैं, वहीं जब वे रोजगार पाने के लिए शहरी पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं, तो ये संबंध टूटने लगते हैं।

नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता

- ▶ भारत में नीतिगत हस्तक्षेपों के बड़े हिस्से का उद्देश्य प्रवासियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और गरीबी कम करना है।
- ▶ हालांकि, सीधे क्षेत्रों पर लक्षित और केंद्रित हस्तक्षेपों की कमी है।
- ▶ इसलिए, एक राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य एक तरफ डिस्टेंस इंड्यूस्ड प्रवासन (समस्या से प्रभावित प्रवास) को कम करना होना चाहिए, तो दूसरी ओर कार्य-स्थिति, रोजगार-शर्तों एवं आधारभूत आवश्यकताओं के सुधार पर होना चाहिए।

MoHUPA (आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय) द्वारा प्रवासन सेटअप पर कार्यकारी समूह की सिफारिशें:

- ▶ पीडीएस को अंतरराज्यीय संचालन प्रदान करके गंतव्य राज्य में प्रवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ उठाने के लिए सक्षम किया जाना चाहिए।
- ▶ राज्यों को, काम और रोजगार में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए मूलनिवास की आवश्यकता को सक्रिय रूप से खत्म करने के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ▶ राज्यों को शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रवासी बच्चों को शामिल करने के लिए भी कहा जाना चाहिए।
- ▶ अनौपचारिक धन-विप्रेषण (Remittances) से बचने के लिए पोस्ट ऑफिस के विशाल नेटवर्क का धन हस्तांतरण लागत में कमी लाकर प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।
- ▶ प्रवासियों का बैंक से सिर्फ आरबीआई की 'केवाईसी' मानदंडों के आधार पर खाता खुलवाने के लिए कहा जाना चाहिए तथा अनावश्यक दस्तावेजों को मांगने पर जोर नहीं देना चाहिए।
- ▶ 'कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस फंड' जिसका बेहद कम प्रयोग हुआ है, का उपयोग किराए पर आवास, कामकाजी महिलाओं के छात्रावास आदि प्रवासी सुविधाओं में करना चाहिए।

क्या आवश्यकताएं हैं?

'अस्तित्व के लिए प्रवासियों' और 'रोजगार के लिए प्रवासियों' के बीच के नीतियों के उद्देश्य में अंतर करने की आवश्यकता है।

- मौसमी प्रवासियों के लिए एकसूत्रीय स्थिर नीति के बजाय लंबे समय तक सतत गतिशील नीति की जरूरत है।
- स्थानीय निकाय और गैर सरकारी संगठन, जो स्थानीय क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन लाते हैं।
- कौशल विकास के तरीकों पर जोर दिया जाए, ताकि वे आसानी से श्रम बाजार में प्रवेश कर सकें।
- व्यक्तिगत और घरेलू प्रवासियों के बीच भी अंतर करना चाहिए, क्योंकि घरेलू प्रवासन को व्यक्तिगत प्रवासन से कहीं ज्यादा आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल जैसे बुनियादी ढांचे तक पहुंच की आवश्यकता होती है।

- कौशल विकास को बाजार आधारित नीतियों जैसे माइक्रोफाइनेंस पहलों द्वारा सहायता दी जानी चाहिए, जो कि आय की मौसमिकता से निपटने में मदद करते हैं।
- इसे पुश फैक्टर्स पर विचार करना चाहिए, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होते हैं और प्रवासियों की विभिन्नताओं को भी समझना चाहिए।
- प्रवासियों द्वारा धन-प्रेषण तेजी से ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा बन रहे हैं।
- अतः नीतियों को, धन प्रेषण को सुगम बनाने और उसके प्रभावी उपयोग हेतु, भारत के उभरते वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय अवसरचना को मजबूत बनाने पर जोर देना चाहिए।

अभिशासन और सामाजिक मुद्दे

भारतीय मुसलमानों की आर्थिक स्थिति



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

भारतीय मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति; नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट

वर्तमान में यह मामला क्या है?

- NSSO (नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस) के अनुसार NSSO श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भारत में मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत नहीं दिखते हैं।
- NSSO की रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं?
- NSSO के 68वें दौर (2011-12) की रिपोर्ट में भारत के प्रमुख धार्मिक समुदायों में शिक्षा स्तर और रोजगार बाजार संकेतकों के अनुमान प्रदान किये गए हैं। मुस्लिमों की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम है।
- शहरी क्षेत्रों में, स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करने वाले मुस्लिम पुरुषों की संख्या बहुत कम (15 प्रति 1000) है। महिलाओं की हालत और भी बदतर है।
- हिंदू, ईसाई और सिख समेत अन्य समुदायों की तुलना में यह संख्या चार गुनी कम है।
- मुस्लिमों में पुरुष स्नातकों की संख्या 71 प्रति 1000 है, जो अन्य समुदायों में स्नातकों (प्रति 1000) की आधे से भी कम है।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पढ़ने वालों की संख्या क्रमशः 162 और 90 व्यक्ति प्रति 1000 है। यह भी सभी समुदायों में सबसे कम है।
- मुस्लिमों में औसत प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (आय के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है) केवल रु.32.66 प्रति दिन है, जो सभी धार्मिक समूहों में सबसे कम है।

- विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मुस्लिमों को गरीबी के दुष्चक्र का सामना करना पड़ रहा है।
- स्कूल शिक्षा के निम्न स्तर या निरक्षरता।
- कम उपस्थिति दर और शैक्षणिक योग्यता।
- कम खपत व्यय और खराब रोजगार बाजार संकेतक।

वर्तमान में यह मामला क्या है?

- केंद्रीय और राज्य सरकारें भारतीय मुस्लिमों को गरीबी के इस दुष्चक्र से बचाने में मदद करने के लिए ठोस कदम उठा सकती हैं।
- इनकी स्थिति में सुधार करने का एक तरीका उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना है।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्कूल जाने वाले छात्र स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंचेंगे।
- व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए।
- उनके कौशल में सुधार होगा जो उनके लिए बेहतर रोजगार लाएगा। इस प्रकार उनकी रोजगार बाजार तक पहुंच में वृद्धि होगी और बेहतर आय मिलेगी।
- जब उनकी आय बेहतर होगी है तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगा इसलिए वे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
- आर्थिक स्थितियों में और सुधार।

नोट्स

चिंताएं

पोलियो और इसके उन्मूलन



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

पोलियो टीका प्रदूषण और पोलियो के प्रकार, क्या अभी भी भारत में पोलियो मौजूद है?

मुद्दा

- ▶ जब ओरल पोलियो टीका (ओपीवी) बच्चों को दिया जाता है, तो ओपीवी में लाइव पोलियो वायरस होते हैं और इसे लेने वाले बच्चों के शरीर से यह वायरस मलत्याग में निकल जाता है। इसके कारण सरकार और नियामक प्राधिकरण चिंतित हैं कि यदि टाइप 2 वायरस सीवेज या जल प्रणाली में चला जायेगा तो पोलियो फैल सकता है।
- ▶ हैदराबाद, दिल्ली, बिहार और गुजरात में इस प्रकार का टाइप 2 परिवर्तन देखा गया था।
- ▶ खुले में शौच वाले स्थानों में सबसे अधिक प्रवण।

इस संबंध में भारत की स्थिति

- ▶ मार्च 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया था।
- ▶ देश में टाइप 2 पोलियो वायरस का अंतिम मामला 1999 में सामने आया था।
- ▶ वाइल्ड p1 और p3 उपभेदों को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया।

पोलियो क्या है?

- ▶ यह एक बेहद संक्रामक विषाणु जनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है।
- ▶ WHO के अनुसार, यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलमार्ग-मौखिक मार्ग के ज़रिये प्रसारित होता है।
- ▶ यह तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, अंगों में अचानक पक्षाघात और अचानक मांसपेशी की कमजोरी और दर्द का कारण बनता है।

उपभेद

- ▶ पोलियो वायरस के 3 उपभेद हैं: P1, P2 और P3
- ▶ 1999 में P 2 को वैश्विक स्तर पर समाप्त कर दिया गया था।
- ▶ भारत को 2014 में सफलतापूर्वक वाइल्ड p1 और p3 उपभेदों को समाप्त कर लेने में सफलता प्राप्त करने पर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था।
- ▶ एक वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस (वीडीपीवी) क्या है?
- ▶ वायरस का स्रोत खुद वैक्सीन ही है। जब बच्चे को टीका (ओपीवी) दिया जाता है तो इसकी बूंदों में लाइव पोलियो वायरस होता है। इस प्रकार टीके के माध्यम से वायरस फैलता है जिसका इंटेस्टाइन में दोहराव होता है। यह रक्त

प्रवाह में प्रवेश कर बच्चे में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को जन्म देता है।

- ▶ बच्चा मलत्याग द्वारा वायरस को बाहर निकाल देगा।
- ▶ मल के माध्यम से उत्सर्जित वायरस मूल वायरस नहीं होता है, अपितु आनुवांशिक रूप से परिवर्तित वैक्सीन वायरस होता है।
- ▶ बच्चा 6 से 8 सप्ताह की अवधि में वैक्सीन वायरस को उत्सर्जित करता है।
- ▶ खुले शौच वाले क्षेत्रों में, यह उत्सर्जित वैक्सीन वायरस समुदाय में तेजी से फैल सकता है और कम प्रतिरक्षा वाले बच्चों को संक्रमित कर सकता है।

वैक्सीन-एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलिओमाइलाइटिस (वीएपीपी)

- ▶ वीएपीपी तब होता है जब वायरस हाल ही में टीकाकरण वाले बच्चे के शरीर में विषाक्त हो जाता है और पोलियो का कारण बनता है।
- ▶ वीएपीपी मामलों की आवृत्ति अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न होती है।
- ▶ उच्च आय वाले देशों द्वारा निष्क्रिय पोलियो टीका (आईपीवी) का उपयोग किया जा रहा है। यह बच्चों में टीकाकरण के लिए मृत वायरस का उपयोग करता है।
- ▶ वीएपीपी का बोझ आमतौर पर कम आय वाले देशों में केंद्रित है जो अभी भी ओपीवी का उपयोग कर रहे हैं।
- ▶ कम आय वाले देश आईपीवी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि भारत यह एक मध्यम आय देश है।

आईपीवी बनाम ओपीवी

- ▶ इंजेक्शन के माध्यम से दिए गए आईपीवी में निष्क्रिय वायरस होता है, जिसे ओपीवी से सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें लाइव वायरस होता है।
- ▶ आईपीवी की तुलना में ओपीवी को प्रशासित करना आसान है और ओपीवी की प्रति खुराक लागत भी आईपीवी की तुलना में कम है। हालांकि, ओपीवी ने दो महत्वपूर्ण संकेतकों पर खराब प्रदर्शन किया: सुरक्षा और प्रभावकारिता।

भारत में ओपीवी के साथ संबद्ध चुनौतियां

- ▶ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1982 में ओपीवी का उपयोग करने वाले सभी देशों से वीएपीपी की आवृत्ति की निगरानी के लिए "निगरानी की निरंतर और प्रभावी प्रणाली" को शामिल करने का आग्रह किया है लेकिन भारत ने इसका पालन नहीं किया है।
- ▶ कई सदस्य देश वीएपीपी के किसी भी जोखिम से बचने के लिए स्वाभाविक रूप से ओपीवी के बजाय आईपीवी का चयन करते हैं। भारत में, बच्चों के टीकाकरण के लिए ओपीवी का उपयोग बंद करके वीएपीपी के मामलों से बचा जा सकता है।
- ▶ यह जानने के बावजूद कि मौखिक टीकों के कारण पोलियो होने की बड़ी सम्भावना है, भारत ने ओपीवी का उपयोग जारी रखा है।
- ▶ जहाँ उच्च आय वाले देशों ने आईपीवी को प्राथमिकता दी है, वहीं भारत और अन्य कम आय वाले देशों ने ओपीवी पर भरोसा रखा है।

भारत ने केवल 2006 में आईपीवी को लाइसेंस दिया है लेकिन इसे नियमित टीकाकरण में प्रयोग नहीं किया।

उपाय

- ▶ भारत में, बच्चों को टीकाकरण के लिए ओपीवी का उपयोग बंद होने के बाद वीएपीपी मामलों से बचा जा सकता है।

- ▶ वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस के उन्मूलन के उपरांत, वीडिपीवी और वीएपीपी से छुटकारा पाने के लिए आईपीवी आवश्यक है।
- ▶ भारत में निगरानी की एक सतत और प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता है।

अभिशासन और सामाजिक मुद्दे

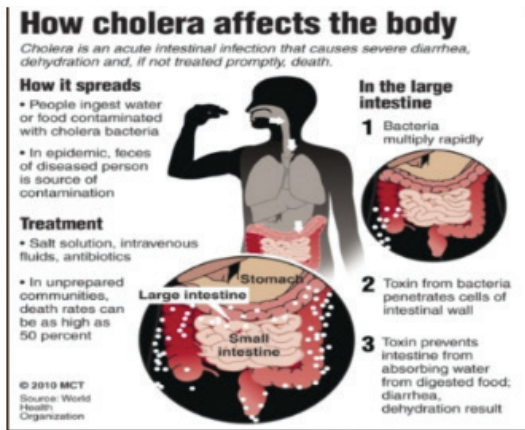


(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

GS प्रश्नपत्र 3: आतंकवाद

नाइजीरिया में हैज़ा का प्रकोप

नाइजीरिया में आतंकवाद के कारण हैज़ा का प्रकोप



कारण

हैज़ा का कारण वी कोलरा नामक बैक्टीरिया से संक्रमण होता है।



- ▶ उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण कि लोग अपने घर से विस्थापित हो गए हैं।
- ▶ पर्याप्त जल हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है।
- ▶ उचित स्वच्छता प्रदान नहीं की जाती है।
- ▶ दोनों समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है।

- ▶ हैज़ा का रोग बड़ी मात्रा में फैल रहा है।
 - ▶ जब दूषित भोजन या जल
 - ▶ का उपभोग किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे वह संक्रमित करता है।
- जब पानी या भोजन में यह बैक्टीरिया होता है और यदि मनुष्य इसका उपभोग करते हैं, और यह मानव आंत तक पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं।



यह बीमारी मूल रूप से अफ्रीका के उत्तर पूर्व क्षेत्र में फैल रही है। (उपरोक्त अरिख का पीला हिस्सा)

संघर्ष के बारे में

बोको हरम: इस्लामी राज्यों की स्थापना के लिए मोहम्मद यूसुफ द्वारा 2002 में स्थापित किया गया। नाइजीरिया के आतंकवादी इस्लामवादी समूह बोको हरम - नाइजीरिया का इस्लामी आतंकवादी समूह बोको हरम - जिसने अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश में बमबारी, हत्या और अपहरण की घटनाओं के माध्यम से अराजकता का माहौल बना दिया है - सरकार को उखाड़ फेंकने और इस्लामी राज्य बनाने के लिए लड़ रहा है। 2009 में बोको हरम विद्रोह शुरू हुआ, जब जिहादी विद्रोही समूह बोको हरम ने नाइजीरिया सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भ किया।

नाइजीरिया के मुस्लिम और ईसाई समुदायों के बीच लम्बे समय से जारी धार्मिक हिंसा से सम्बंधित मुद्दों के संदर्भ में यह विद्रोह हुआ। दोनों समुदायों के बीच संघर्ष जारी है। इसके कारण बोको हरम की स्थापना हुई।

स्थिति और खराब हो गई है

पूर्वोत्तर नाइजीरिया में संदिग्ध हैज़ा के मामलों में वृद्धि हुई है, जहां बोको हरम हिंसा ने हजारों लोगों को भीड़ वाले शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर किया है

- ▶ इसके द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट सामग्री में वी कोलरा बैक्टीरिया होता है जिसे मानव मलत्याग के माध्यम से पर्यावरण में स्थानांतरित किया जाता है।
- ▶ इस वजह से कई लोग मर गए हैं।

▶ खूनी संघर्ष से 1.8 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, जिसमें 27,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। मोहम्मद यूसुफ ने 2002 में बोर्नो के उत्तर-पूर्वी राज्य की राजधानी मैदुगुडी में एक संप्रदाय की स्थापना की जो बोको हरम के नाम से जाना गया। बोको हरम का जन्मस्थान मैदुगुडी में लगभग 243 000 विस्थापित लोग भीड़ भरे शिविरों में रह रहे हैं। इन शिविरों में अपर्याप्त स्वच्छताओं के कारण हैज़ा के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।

मानवतावादी समूह ने कहा कि तेजी से फैले हुए हैज़ा के प्रकोप से 10 000 लोग प्रभावित हुए हैं और एडमवा, बोर्नो और योबे के पूर्वोत्तर राज्यों में 175 लोगों की मौत हो गई है। भीड़ शिविरों में पर्याप्त पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना मुश्किल बनाती है। बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा होने के कारण स्थितियां और भी खराब हो गई है।

अगर तत्काल प्रभाव से शिविरों को हटाने तथा स्वास्थ्य और

स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि प्रदान नहीं की गयी, तो नाइजीरिया 2019 में एक और हैज़ा प्रकोप की ओर बढ़ रहा है।

नाइजीरियाई सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण है।

समाधान:

दोनों समुदायों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए तथा नाइजीरियाई लोगों की मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समूह को साथ आना चाहिए।

अभिशासन और सामाजिक मुद्दे

उम्र बढ़ने का मुकाबला

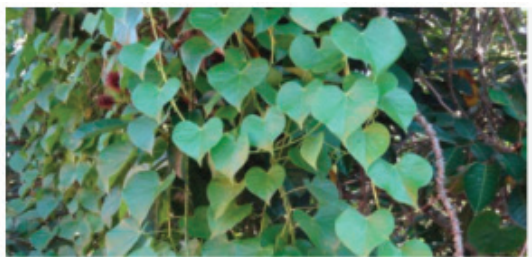


(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)



उम्र बढ़ने का मुकाबला

निबंध और जीएस प्रश्नपत्र 3 के लिए महत्वपूर्ण है बढ़ती उम्र का सामना करने के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि की खोज एक भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने उम्र बढ़ने से निपटने के लिए शोध में बड़ी सफलता प्राप्त करने का दावा किया है। जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हुए एक अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया है कि गिलोय (हार्ट लीव्ड मूनसीड)-जोकि एक प्रकार की झाड़ी है- का उपभोग करने से फलमक्खी (ड्रोसोफिला मेलानोगस्टर) की उम्र में वृद्धि हुई है।



गिलोय



► ड्रोसोफिला मेलानोगस्टर (मक्खी)

उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और दीर्घायु को समझने के लिए मक्खियां सबसे बड़े पैमाने पर अध्ययन किए गए पशु मॉडल में से एक हैं। अध्ययन में दावा किया गया है कि मक्खियों का जीवनकाल, जो 29 से 30 दिनों से अधिक नहीं है, 30 दिनों तक सांद्र गिलॉय पाउडर खिलाए जाने से 85 दिनों तक बढ़ गया है।

► इसे नीदरलैंड स्थित वॉल्टर कुल्वर, (स्वास्थ्य देखभाल पर एक प्रतिष्ठित पत्रिका) में प्रकाशित किया गया है।

► गिलॉय पाउडर के कारण मक्खियों के जीवनकाल में वृद्धि को इसके उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

एंटीऑक्सीडेंट क्या हैं? ये कैसे कार्य करते हैं?

- ब्रह्मांड में सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं।
- परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के साथ बने होते हैं। इनमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं।
- परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं।
- अणु परमाणुओं से मिलते हैं
- अणु स्वयं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक रसायन निर्मुक्त किया जाता है जो शरीर के चयापचय के लिए आवश्यक होता है।

गिलोय पाउडर

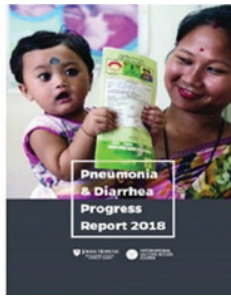
► गिलॉय पाउडर को पेपर में गुडुची चूर्ण के रूप में उल्लिखित किया गया है और इसे दीर्घायु लाने वाली जड़ी बूटी के रूप में माना जाता है।

► "हालांकि डी मेलानोगस्टर की जीवितता को बढ़ाने के लिए गुडुची चूर्ण की कार्रवाई के सटीक तंत्र का पता नहीं लगाया जा सका, किन्तु इसने गुडुची चूर्ण के रसायन प्रभाव की अवधारणा को मान्यता दी है।

► "रसायन, आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है और औषधीय तैयारी के एक समूह के साथ सम्बंधित है, जो प्रतिरक्षा को बढ़ाती है और असमय उम्र बढ़ने जैसी कई बीमारियों के कारण को रोकता है।

नोट्स

निमोनिया और डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट 2018



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

भारत में निमोनिया के कारण बाल मृत्यु
UPSC के दृष्टिकोण से- GS प्रश्नपत्र 3

मुद्दा क्या है?:

हाल ही में, निमोनिया और दस्त की प्रगति रिपोर्ट भारत में प्रकाशित की गई है और इसमें, बच्चों के मौत के सभी कारक प्रकाशित किए गए हैं।

निमोनिया क्या है?:

- फेफड़ों के वायु कोषों में होता है
- बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा और अन्य संक्रामक एजेंट, जैसे कि कवक, निमोनिया के कारण बन सकते हैं।
- किसी भी उम्र में हो सकता है। फेफड़े की बीमारियों से प्रभावित लोग इसके प्रति अधिक सुभेद्य हो सकते हैं, खासतौर पर जिनको जुखाम और खांसी रहती है।
- एक सामान्य निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है जैसे लेजिओनेला न्यूमोफिला, माइकोप्लाज्मोनिया और क्लेम्यो-डोफिला निमोनिया।
- वायरल निमोनिया इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होता है। यह गंभीर और कभी-कभी घातक भी हो सकता है। यह वायरस फेफड़ों पर हमला करता है और कई गुना बढ़ जाता है। माइकोप्लाज्मा बीमारी के सबसे छोटे मुक्त जीवित एजेंट हैं। उन्हें वर्गीकृत नहीं किया जाता है कि वे बैक्टीरिया हैं या नहीं। माइकोप्लाज्मा से आमतौर पर हल्का निमोनिया का होता है लेकिन कुछ लक्षण लम्बे समय तक रहते हैं तो यह गंभीर हो सकता है।

निमोनिया और दस्त की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई:

- भारत में निमोनिया से 1,58,176 बच्चों की मौत हुई है। भारत में बच्चों में निमोनिया का बोझ विश्व में सर्वाधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत एक संकटग्रस्त राष्ट्र है जहाँ बच्चे इस बीमारी के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य हैं।
- वैश्विक स्तर पर, 2016 में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में हर चार मौतों में से लगभग एक निमोनिया और डायरिया के कारण हुई।
- रिपोर्ट यह विश्लेषण करती है कि देश निमोनिया और डायरिया के खिलाफ सुरक्षा, रोकथाम और उपचार में मदद के लिए कितने प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जैसे- स्तनपान, टीकाकरण, देखभाल तक पहुँच, एंटीबायोटिक्स का उपयोग, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्युशंस (ओआरएस) और ज़िंक सप्लीमेंट- प्रदान कर रहे हैं।
- ये उपाय इन बीमारियों के कारण मृत्यु को रोकने में मदद के लिए साबित हुए हैं। साथ ही ये 2030 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1,000 जीवित जन्मों तक करने के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं।
- आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1,000 जीवित जन्मों तक करने के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं।

भारत में प्रगति:

भारत में मिश्रित प्रगति देखी गयी है - 2016 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ डायरिया और निमोनिया के कारण पांच वर्ष की आयु से कम के बच्चों की मृत्यु, अन्य देशों की तुलना में अधिक है। 2017 में, न्यूमोकोकल कॉजुगेट वैक्सीन का उपयोग प्रारम्भ किया गया, लेकिन यह केवल 6 राज्यों तक ही सीमित था।

अभिशासन और सामाजिक मुद्दे

मराठा आरक्षण प्रस्ताव



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)
मराठा आरक्षण विधेयक

यह किस बारे में है?:

महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में एक नव निर्मित स्वतंत्र श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दे दी है।

मराठा समुदाय:

- महाराष्ट्र 1 मई 1960 को राज्य बना था। बॉम्बे राज्य को दो राज्यों में विभाजित किया गया था: महाराष्ट्र और गुजरात, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा।
- 1960 से, राज्य में 18 मुख्य मंत्री थे, इनमें से 18 में से 11 मराठा समुदाय से थे, जो इंगित करता है कि समुदाय काफी राजनीतिक रूप से सक्रिय है।
- राज्य की एक तिहाई आबादी मराठा समुदाय से है और ऐतिहासिक रूप से उन्हें 'योद्धा वर्ग' के रूप में पहचाना जाता है।
- इस समुदाय का भूमि की बड़ी मात्रा पर स्वामित्व है। इस के अधिकांश सदस्य अपने रोजगार के लिए कृषि श्रम पर भरोसा करते हैं, जोकि राज्य की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग:

महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है।

कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक;

► 37% मराठी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे।

लगभग 62% मराठा जनसंख्या लघु या सीमान्त भूमि धारण करती है।

► 70% मराठा जनसंख्या कच्चे घर (मिट्टी के घरों) में रह रही है

► राज्य के अन्य समुदायों की तुलना में मराठा समुदाय के लोगों में शैक्षिक पिछड़ापन भी अधिक मात्रा में है।

क्या यह निर्णय उचित है?:

► उपलब्ध आंकड़ों के साथ साम्य नहीं-जैसे हरियाणा में जाट समुदाय और गुजरात में पटेल सामाजिक-आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग में आते हैं, वैसे ही स्थिति में महाराष्ट्र में मराठा भी हैं।

► ऐसा कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है कि मराठों को अन्य राज्यों की तरह किसी भी सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।

► हालाँकि उनके उत्थान के कारणों के रूप में रोजगार के अवसरों की कमी और उनकी खराब कृषि आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन दो मुद्दों को नीति कार्रवाई द्वारा हल किया जा सकता है।

आरक्षण योजना:

► समुदाय द्वारा राज्य में 16% आरक्षण के लिए मांग की जा रही है, लेकिन सरकार मांग से सहमत नहीं है।

► मंत्रिमंडल ने इस मामले को खत्म करने और आरक्षण की मात्रा को नियत करने के लिए एक समिति गठित की है।

वर्तमान आरक्षण स्लैब:

अनुसूचित जाति - 13%, अनुसूचित जनजाति - 7%, अन्य

पिछड़ा वर्ग - 19%, विशेष पिछड़े वर्ग-4%

शेष आरक्षण राज्य की घुमन्तु जनजातियों के लिए है

आरक्षण की चुनौतियां:

► श्रेणी - आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मराठा क्रांति मोर्चा ने ओबीसी श्रेणी के तहत कोटा के लिए मांग की और इससे ओबीसी वर्ग ने अनुमान लगाया कि नए कोटे से ओबीसी के मौजूदा समूह में मराठे भी शामिल होंगे। इससे ओबीसी समुदाय के भीतर संघर्ष हो सकता है।

► हिस्सेदारी- महाराष्ट्र राज्य में ओबीसी अपने आरक्षण के हिस्से को वर्तमान के 19% से 27% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एक चरवाहा समुदाय, डुंगा समुदाय ने मांग की कि वे ओबीसी से एसटी श्रेणी में जाना चाहते हैं। मुसलमानों ने भी 5% आरक्षण की मांग की है।

► कुल आरक्षण हिस्सेदारी - चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की

सीमा को पहले से ही 50% (इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992) सीमित कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य पहले ही 50% से अधिक आरक्षण प्रदान कर रहा है। ऐसे में, अब 16% अधिक आरक्षण संचयी रूप से 68% आरक्षण कर देगा जो लगभग तमिलनाडु (69% आरक्षण) के बराबर है।

सरकारी स्पष्टीकरण:

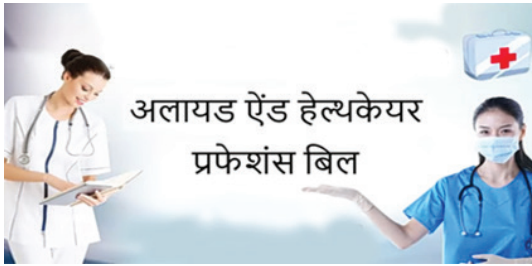
► महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह किसी भी वर्ग के मौजूदा आरक्षित वर्गों को प्रभावित नहीं करेगा, चाहे वह अन्य पिछड़ा वर्ग या कोई अन्य वर्ग हो

► सरकारी की योजना एक नया अलग कोटा पेश करनी की है और यह कोटा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में जाना जाएगा।

► महाराष्ट्र सरकार का तीसरा तर्क यह है कि भारत के संविधान में कोटा पर कोई सीमा नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

► राज्य यह भी कहता है कि संविधान असाधारण मामलों और अपवादों के तहत कोटे के लिए प्रावधान प्रदान करता है, उदाहरण के लिए - तमिलनाडु में 69% आरक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी लंबित है।

नोट्स



अलायड ऐंड हेल्थकेयर प्रफेशनल बिल

(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC दृष्टिकोण : GS 2 - स्वास्थ्य और संबंधित मुद्दों

समाचार में क्यों?

INS अरिहंत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अलायड और हेल्थकेयर पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के विनियमन और मानकीकरण के लिए अलायड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

यह केंद्रीय और संबंधित राज्य अलायड और हेल्थकेयर परिषदों की स्थापना; अलायड और हेल्थकेयर श्रेणी में 53 व्यवसायों सहित 15 प्रमुख पेशेवर श्रेणियों का प्रावधान करता है।

► यह विधेयक एक केन्द्रीय परिषद और राज्य परिषदों के गठन, ढांचे, संविधान, संरचना और कार्यों का प्रावधान करता है। इसके कार्यों में नीतियों और मानकों को तैयार करना, पेशेवर आचरण का विनियमन करना, लाइव रजिस्ट्रारों का निर्माण और रखरखाव, सामान्य प्रवेश और निकास परीक्षा के लिए प्रावधान करना आदि शामिल हैं।

► केंद्रीय परिषद में 47 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से विविध भूमिकाओं और कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 पदेन सदस्य होंगे तथा शेष 33 अपदेन सदस्य होंगे जो मुख्य रूप से 15 पेशेवर श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

► राज्य परिषदों को भी केंद्रीय परिषद के समान संरचित करने की परिकल्पना की गयी है। इनमें 7 पदेन सदस्य और 21 अपदेन सदस्य होंगे। अध्यक्ष को अपदेन सदस्यों में से चुना जायेगा।

► केंद्रीय और राज्य परिषदों के तहत व्यावसायिक सलाहकार निकाय स्वतंत्र रूप से मुद्दों की जांच करेंगे और विशिष्ट मान्यता प्राप्त श्रेणियों से संबंधित सिफारिशें प्रदान करेंगे। किसी भी कवर किए गए व्यवसायों के लिए किसी अन्य मौजूदा कानून पर विधेयक का अधिव्यापी प्रभाव भी होगा।

► राज्य परिषद अलायड और हेल्थकेयर संस्थानों की मान्यता लेगी।

► कदाचार की जांच के लिए विधेयक में जुर्माना का प्रावधान विधेयक में शामिल किया गया है।

► यह विधेयक केन्द्रीय और राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार भी देता है।

► केंद्र सरकार को नियम बनाने और अनुसूची जोड़ने या संशोधित करने के लिए परिषद को निर्देश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है।

इस कानून की आवश्यकता है:

अलायड और हेल्थकेयर पेशेवर (A&HP) स्वास्थ्य मानव संसाधन नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण तत्व निर्मित करते हैं।

नाटकीय रूप से गुणवत्ता संचालित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार कर सकते हैं।

लाभार्थियों की संख्या:

► यह अनुमान लगाया गया है कि अलायड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल बिल, 2018 देश में लगभग 8-9 लाख अलायड और हेल्थकेयर संबंधित पेशेवरों और श्रमबल में सालाना शामिल होने और स्वास्थ्य प्रणाली में योगदान देने वाले कई अन्य स्नातक पेशेवरों को सीधे लाभान्वित करेगा। हालांकि, चूंकि इस विधेयक को बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि देश की समस्त जनसंख्या और स्वास्थ्य क्षेत्र को इस विधेयक से लाभान्वित किया जाएगा

प्रारंभिक परीक्षा बिट्स: अलायड और हेल्थकेयर पेशेवर कौन है?

► विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, "अलायड हेल्थ प्रोफेशनल वे कर्मचारी हैं जिनका स्वास्थ्य देखभाल की कला और विज्ञान के साथ विशिष्ट संबंध है और जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में स्वास्थ्य टीम के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे एक मान्यता प्राप्त या अधिकृत स्वास्थ्य या स्वास्थ्य देखभाल या अकादमिक संस्थान में पेशेवर योग्यता के विभिन्न स्तरों के साथ शिक्षित हैं।"

► अलायड और हेल्थकेयर पेशेवरों में चिकित्सकीय, नैदानिक, उपचारात्मक, निवारक और पुनर्वास संबंधी हस्तक्षेप में विशेषज्ञता के साथ स्वास्थ्य या संबंधित सेवाओं के वितरण से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं।

► वे एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने, संरक्षित करने, इलाज करने और / या प्रबंधित करने के लिए चिकित्सकों, नर्सों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों समेत अंतःविषयक स्वास्थ्य टीमों में काम करते हैं।

नोट्स

अर्थव्यवस्था

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'

भारत 77 वां स्थान पर रहा



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में भारत 77 वें स्थान पर

भारत ने पिछले वर्ष (2017) के 100 वें स्थान से जबरदस्त छलांग लगाते हुए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में 77वां स्थान प्राप्त किया है।

रैंकिंग की विशिष्टता:

वस्तुतः विश्व बैंक द्वारा दो शहरों, दिल्ली और मुंबई, में व्यापार करने के आधार पर मूल्यांकन कर देश को अंक दिए जाते हैं। हालाँकि इस सन्दर्भ में कई विशेषज्ञों का तर्क है कि ये दोनों शहर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते और केवल इन शहरों को दिए गए अंक पूरे देश के साथ न्याय नहीं कर रहे।

दस मापदंडों में भारत का स्कोर:

सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार 'निर्माण परमिट से निपटने (Dealing with Construction Permits)' में है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार (संघ और राज्य दोनों) और अधिकारी-तंत्र मिलकर सुधार की दिशा में कार्य कर रही है। हालाँकि कुछ तीव्रता आने के बावजूद संपत्ति पंजीकरण की स्थिति मंद रही है।

विश्व बैंक की अभिव्यक्ति:

► विश्व बैंक ने कुछ मानकों में सुधार के लिए भारत की प्रशंसा की।

- यह लगातार दूसरा वर्ष है जब भारत में सुधार हुआ है। यह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई और ब्रिक्स देश है।
- भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है जो इस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में किये गये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है

Parameters	2017	2018
Good Performances in		
Starting a business	156	137
Enforcing Contracts	164	163
Dealing with Construction Permits	181	52
Getting Credit	29	22
Getting Electricity Connection	29	24
Trading Across Borders	146	80
Bad Performances in		
Registering Property	154	166
Paying Taxes	119	121
Resolving Insolvency	103	108
Protecting Minority Investors	4	7

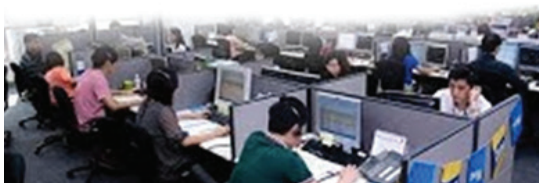
Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ranking	134	132	132	134	142	130	130	100	77

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण हेतु शून्य शुल्क।
- निर्माण परमिट प्राप्त करने की लागत कम कर दी गई है।
- बिजली पंजीकरण की लागत कम कर दी गई है तथा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रगति के फलस्वरूप, अब घरेलू क्षेत्र गैर-परंपरागत स्रोतों द्वारा बिजली की खपत के कुछ हिस्सों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। इससे विद्वत् का वो भाग जो घरेलू क्षेत्र को प्रदान किया जाता था, अब उद्योगों को उपलब्ध कराया जाता है।
- इसके साथ ही कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, इन्सॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड तथा GST जैसे प्रमुख सुधार किये गए हैं।
- 2016 में 'यूनाइटेड बिल्डिंग बाय-लॉ' को लागू किये जाने का इन दो वर्षों में अच्छा प्रभाव हुआ है जिसे वर्तमान परिदृश्य में देखा जा सकता है।
- मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, कंपनी अधिनियम तथा विकास नियंत्रण विनियम।

अर्थव्यवस्था

भारत के सेवा क्षेत्र में तेजी और और इसके निहितार्थ



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

यह किस बारे में है? :

सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के योगदान और देश के रोजगार वृद्धि के बीच असमानता मौजूद है। सेवा क्षेत्र और रोजगार वृद्धि मेल नहीं खाती है।

इस विचलन के कारण:

1990 के आर्थिक विकास के दौरान नई आर्थिक नीतियां लागू की गईं और भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था बन गई। सेवा क्षेत्र के निर्यात ने अर्थव्यवस्था में अच्छी भूमिका निभाई, जो 1996-97 की अवधि में सबसे अधिक था और सकल घरेलू उत्पाद के 50 प्रतिशत से अधिक था।

- 2013-14 के आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया कि चीन के पीछे भारत में दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र है। मूल्यांकन सीएजीआर (कंपाउंड वार्षिक विकास दर) पर आधारित था, जो 10.9% की चीनी दर से नीचे 9% था। यह अर्थव्यवस्था के पिछले 10 वर्षों (2001-2012) के विश्लेषण पर आधारित था।
- यह सेवाओं से प्राप्त सकल मूल्य से भी स्पष्ट था, इसलिए सेवाओं से वार्षिक जीवीए में 8.7% की वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2011-12 और 2016-17 के बीच कुल जीवीए में 58% की वृद्धि हुई। सेवाओं के निर्यात में वृद्धि से सेवाओं और संवृद्धि में भी बढ़ोतरी हुई है। सेवाओं के निर्यात में भारत प्रभावशाली बन गया है।
- विश्व के सेवा निर्यात खाते में भारत का हिस्सा 38% है। यह चीन, मेक्सिको, ब्राजील आदि से काफी अधिक है, और यूके, यूएसए के बहुत करीब है।

असंगठित क्षेत्र का योगदान:

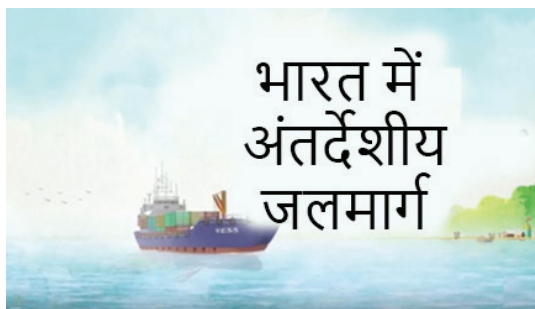
- उच्च उत्पादकता सेवाओं में विविधता - कुल सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं के सापेक्ष हिस्से में भारत की समयपूर्व वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।
- राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी में उल्लेख है कि नई और उच्च उत्पादक सेवाएं 2016-17 में कुल जीवीए का केवल 28.5% हैं।
- उच्च उत्पादकता सेवाएं हैं: परिवहन, संग्रहण, संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं इत्यादि।
- पारंपरिक सेवाएं - जीवीए के 11.1% के लिए उत्तरदायी हैं। पारंपरिक सेवाएं इस प्रकार हैं:
- व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट, खुदरा व्यापार इत्यादि। जबकि अन्य सेवाएं 6.9% के लिए उत्तरदायी हैं।
- असंगठित - बहुत कम आय - इस कम आय का कारण प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में उचित अवसरों की भारी कमी है, जो लोगों को तृतीयक या सेवा क्षेत्र पर अधिक विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। सेवा क्षेत्र में लोगों की अधिक उपलब्धता के कारण इसमें नियोजित लोगों की आय में भी कमी आयी है।

रोजगार के अवसर:

- कुल रोजगार क्षेत्र में कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा अपेक्षाकृत कम था, हालांकि असंगठित क्षेत्र की उपस्थिति सेवा क्षेत्र में अधिक है, लेकिन यह अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम नहीं है। या हम कह सकते हैं कि कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा अपेक्षाकृत कम था।
- बड़े स्तर पर विचलन - वित्त वर्ष 1999 - 2000 और 2004 - 05 के बीच तृतीयक क्षेत्र में रोजगार में केवल 22% की वृद्धि हुई, लेकिन नियमित मूल्य योगदान में जीडीपी में 44% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2009 - 10 में, तृतीयक क्षेत्रक रोजगार में केवल 25% के लिए जिम्मेदार था, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान 55% था। एनएसएसओ (नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस) के अनुसार सेवा रोजगार की हिस्सेदारी जीडीपी की ओर योगदान में वृद्धि की तुलना में काफी कम है।

नोट्स

अर्थव्यवस्था



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पुनरुद्धार

(UPSC के दृष्टिकोण से- GS प्रश्नपत्र-1)

इसके बारे में जानकारी

भारत माल-आवाजाही के लिए अपने अंतर्देशीय जल परिवहन को सशक्त कर रहा है। इसी सन्दर्भ में पेक्सिको के स्वामित्व वाले 16 कंटेनरों का शिपमेंट वाराणसी में नए बहु-मॉडल टर्मिनल तक पहुंचेगा।

जलमार्गों का पूर्वज्ञान:

- वाणिज्यिक भाड़ा, गलियारों के लिए योग्य और मितव्ययी।
- आधुनिक युग से पूर्व परिवहन के लिए नदियों और नहरों का उपयोग किया जाता था। हालांकि, सड़क और रेलवे के यात्रा और व्यापार में शामिल होने तथा इनके जलमार्गों की तुलना में तेज़ होने से जलमार्गों के उपयोग में कमी आयी है।
- गाद (सिल्ट) का जमाव
- IWA भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, 1986 में बनाया गया। इसका मुख्यालय नॉएडा में है। प्राधिकरण ने पांच जल मार्गों की खोज की है और इसमें निवेश के लिए सिफारिश की है।
- 1986 से 2014 तक, इन पांच जलमार्गों में केवल 1,456 करोड़ रुपये निवेश किए गए थे। अंतरराष्ट्रीय तुलना में वहीं चीन ने 2005-2010 से 1,09,000 करोड़ रुपये का निवेश किया और जर्मनी ने 2016 में अकेले 77,000 करोड़ रुपये का निवेश किया।
- 2016 में, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम पारित किया गया, जिसका लक्ष्य संभावित नदियों का विलय करना और देश के 106 जलमार्गों को मजबूत करना था, जिसमें पहले के 5 भी शामिल थे।

जलमार्गों की क्षमता:

- ▶ भारत के अंदर प्रभावी तौर से लगभग 14,500 किलोमीटर का नौकायन जलमार्ग है।
- ▶ लगभग 55 मिलियन टन वजन के कार्गो चलते हैं, लेकिन वे कई नदियों और क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।
- ▶ यह परिवहन केवल 3% योगदान देता है, शेष 97% परिवहन के अन्य साधनों द्वारा किया जाता है, अतः इसका बेहद कम उपयोग किया गया है, जबकि यह देश को और अधिक योगदान दे सकता है।

रास्तों में प्रतिरोध:

- ▶ समय समय पर निकर्षण, अर्थात् जलमार्गों में गाद जमा होना उचित नहीं है और यह अनियमित है।
- ▶ स्थाई और तैरने वाले पुलों की कमी
- ▶ नदियों का सूखना जो नदियों को उथला बना सकता है। निम्न ऊँचाई वाले पुल जो रास्तों में बाधाएं डाल सकते हैं।

उठाये गए कदम:

- जलमार्ग विकास परियोजना- परियोजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग -1 की नौहनियता में सुधार करना है। यह वाराणसी से हल्दिया तक 1380 किलोमीटर लंबा और 3 मीटर चौड़े रास्ते के तौर पर 2023 तक विकसित किया जायेगा।
- ▶ राष्ट्रीय जलमार्ग -1 के साथ मल्टीमॉडल टर्मिनल्स विकसित किए जाने हैं। पहला वाराणसी में, दूसरा साहेबजंग (झारखंड) में और तीसरा हल्दिया में।
- ▶ 359 करोड़ रुपये की लागत से फरक्का नौहन पथ जुलाई 2019 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- ▶ पुनरुद्धार के लिए धन इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष एवं केंद्रीय सड़क कोष विनियमित किया जा रहा है।
- ▶ सरकारी बॉन्ड जारी करके।
- ▶ दो 1233 टन फ्लाई ऐश से लदी नौकाओं का ध्वजारोहण किया गया। ये नौकाएँ 2085 किलोमीटर पर करके असम में स्थित आंतरिक बंदरगाह पांडु तक जाएंगी।

अर्थव्यवस्था



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

बैंकिंग क्षेत्र में असुरक्षित ऋण

हाल ही में क्या हुआ है?:

अर्थव्यवस्था में असुरक्षित ऋणों का हिस्सा बढ़ रहा है और बैंक अचानक जोखिमों के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे अंततः अर्थव्यवस्था को अचानक जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। यह अर्थव्यवस्था के क्रेडिट प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। असुरक्षित ऋण - ये केवल उधारकर्ता की ऋण योग्यता के आधार पर जारी और समर्थित होते हैं और इनमें संपार्श्विक पर विचार नहीं किया जाता है। संपार्श्विक का कोई समर्थन न होने का अर्थ है कि किसी भी संपार्श्विक के बिना ऋण असुरक्षित हो जाता है।

स्थिति:

- ▶ मार्च 2018 की क्रिसिल रिसर्च के अनुसार, भारतीय बैंकिंग उद्योग में बकाया असुरक्षित ऋण 5 लाख करोड़ रुपये है
- ▶ यह राशि खुदरा उधार का 26% है, जो तीन साल पहले केवल 21% थी। इसका अर्थ यह है कि भारतीय बैंकिंग उद्योग में असुरक्षित ऋण की मात्रा हर साल बढ़ रही है।
- ▶ यह एनपीए को और बढ़ा देगा।
- ▶ भारतीय बैंकों को 'परियोजना ऋण' के विलफुल डिफॉल्ट ने भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है और ये ऋण बड़े औद्योगिक समूहों को दिए गए थे। चूंकि वे असफल रहे, तो बैंक छोटे उधार देने लगे। बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि के वाहक के रूप में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खुदरा ऋण का उपयोग किया जाता है।

- ▶ इस कारण से, असुरक्षित क्रेडिट कार्ड ऋण और व्यक्तिगत ऋण बैंकिंग उद्योग में असुरक्षित ऋण के लिए सबसे तेजी से बढ़ते खंडों में योगदान देते हैं।
- ▶ असुरक्षित क्रेडिट ऋण और व्यक्तिगत ऋण की मात्रा सालाना 30-31% पर बढ़ रही है। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में ऋण, केवल 8-9% है।
- ▶ असुरक्षित खुदरा क्षेत्र उच्च दर पर बढ़ रहा है। इसलिए आरबी आई इस क्षेत्र पर ध्यान की जरूरत है।

चिंताएं:

- ▶ पिछले आर्थिक उछाल के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग का खुदरा ऋण के साथ कड़वा अनुभव रहा है।
- ▶ रिकवरी के लिए नगण्य संभावना - असुरक्षित ऋण के साथ सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह है कि किसी भी डिफॉल्ट स्थिति में, ऐसे ऋणों की वसूली के लिए नगण्य संभावनाएं प्रदान करते हैं। उनके पास क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई संपार्श्विक नहीं है अतः बैंक राशि रिकवर करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे।
- ▶ उपभोग की गति- पिछले कुछ वर्षों में, देश में निजी पूंजी व्यय कम हो रहा है। इसलिए, निजी खपत भारत के विकास की कुंजी रही है। निजी खपत बढ़ जाने पर अर्थव्यवस्था में कुल मांग बढ़ेगी। इसलिए, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद का उत्पादन बढ़ जाएगा।
- ▶ खुदरा ऋण में वृद्धि के साथ, बैंकों के लिए परिसम्पत्तियों पर प्रतिफलों में वृद्धि होती है। बैंकों में और अधिक ऋण वृद्धि हुई है और इसी कारण बैंक असुरक्षित ऋणों पर बल देने के लिए इच्छुक हैं।
- ▶ क्रेडिट मानकों को कम करना - बैंकिंग उद्योग में कई उधार-दाता हैं। वे सभी एक ही खुदरा क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण, ऋण मानकों के कम होने की सम्भावना है जो खराब मूल्य निर्धारण को जन्म देगा और बैंकिंग क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। उन सभी पर नज़र रखने के लिए उचित पर्यवेक्षण होना चाहिए।

आगे की राह

- ▶ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग डेटा और

एनालिटिक्स के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी को अपनाने और क्षमता निर्माण पर अधिक भरोसा कर सकते हैं।

- बैंक अप्रत्यक्ष रूप से खुदरा एक्सपोजर; सेक्युरिटाइजेशन या NBFC और लघु वित्त बैंकों के साथ असाइनमेंट डील, भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, इन अप्रत्यक्ष खुदरा एक्सपोजर्स को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी चुना जा सकता है।
- सेक्युरिटाइजेशन का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक कंपनी अपनी अलग-अलग वित्तीय संपत्तियों या ऋणों को एकत्रित कर एक समेकित वित्तीय उपकरण का निर्माण कर सकती है तथा इसे निवेशकों को जारी किया जा सकता है। कंपनी द्वारा इसका उपयोग पूँजी में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है और इस पूँजी का उपयोग बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

नोट्स

अर्थव्यवस्था



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

आरबीआई और सरकार के बीच मुद्दा क्या है

- सरकार RBI से 3.6 लाख करोड़ रुपये की आहरित करना चाहती है। हालाँकि RBI इसके लिए अनिच्छुक है क्योंकि राशि बहुत बड़ी है और अपने रिजर्व में कमी नहीं चाहता है।
- RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार
- हमारी कुल लागत हमारी कुल शुद्ध ब्याज आय का केवल 1/7 है।
- इसलिए हम एक बड़ी मात्रा में अधिशेष लाभ कमाते हैं, जो समस्त सार्वजनिक क्षेत्रों से भी अधिक है।
- "सरकार को अतिरिक्त लाभांश का भुगतान करने के लिए, आरबीआई को अतिरिक्त स्थायी रिजर्व बनाना होगा, अर्थात्, अधिक करेंसी छापनी होगी।

आरबीआई की संपत्ति और रिजर्व

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आरबीआई की कुल संपत्ति 36 लाख करोड़ रुपये (36,17,594 करोड़ रुपये) से अधिक है। यह निम्नलिखित में वितरित है:

- आरबीआई के कोष में रखे नोट, सिक्के और सोना।
- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ।
- सरकारी बांड, ट्रेजरी बिल और विशेष तेल बांड।
- केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए ऋण और अग्रिम।
- वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, नाबार्ड और अन्य के लिए ऋण और अग्रिम।

अधिशेष स्थानांतरण क्या है?

आरबीआई अपने रिजर्व से कमाता है। जैसा कि इस शब्द से पता चलता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अपने मुनाफे का एक हिस्सा केंद्र सरकार को स्थानांतरित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अधिशेष लाभ आवंटन) के अनुसार, आरबीआई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार को व्यय से अधिक आय स्थानांतरित करता है। आरबीआई ने अधिशेष हस्तांतरण के रूप में 50,000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करने का फैसला किया है। हालाँकि, सरकार चाहती है कि वह पूरे अधिशेष को वित्तीय वर्ष 2017-18 से सरकार को स्थानांतरित कर दे।

नोट्स

- वर्तमान में, वित्त वर्ष 18 में आरबीआई का भंडार 9.7 लाख करोड़ रुपये का है। (हम परिसंपत्तियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।)
- आरबीआई द्वारा प्रशासित 9.7 लाख करोड़ रुपये में से, केवल 2.55 लाख करोड़ रुपये आकस्मिक निधि का हिस्सा हैं, जिसे अप्रत्याशित नुकसान से बचाने के लिए आवंटित किया गया है।
- आरबीआई के बफर में मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन के रूप में 6.91 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। आकस्मिक निधि, संपत्ति विकास निधि, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता।

विवाद

आरबीआई लाभांश के रूप में सरकार को अधिशेष धन प्रदान करता है। अब प्रश्न यह है कि यह लाभांश कितना होना चाहिए। उषा थोराट समिति (2004) इस समिति ने कहा कि कुल भंडार कुल परिसंपत्तियों का लगभग 18% होना चाहिए। वर्तमान में यह 28% है। वाईएच मालेगाम की अध्यक्षता वाली एक और समिति ने कहा कि मौजूदा भंडार आवश्यक बफर से अधिक थे और इसलिए लाभांश से कोई स्थानान्तरण आवश्यक नहीं है। संपूर्ण अधिशेष सरकार को भेजा जाना चाहिए।

नोट्स

- CGRA कुल परिसंपत्ति का 21.81% था और आकस्मिक रिजर्व 8.44% था।
- संबंधित संख्या अब (2017-18) क्रमशः 19.11% और 6.41% है। RBI का मानना है कि बफर अब अपर्याप्त है।

फिलहाल, ऐसा लगता है कि भारतीय रिजर्व बैंक 3.6 लाख करोड़ रुपये की सरकार की मांग को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसे अंततः करना ही पड़ा, तो इसका अर्थ यह होगा कि आकस्मिक निधि को पूरी तरह से और सोने और मुद्रा परिसंपत्तियों को समाप्त करना पड़ेगा। अगर यह अपमानजनक लगता है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है। रघुराम राजन ने संक्षेप में कहा: "सरकार को अतिरिक्त लाभांश का भुगतान करने के लिए, आरबीआई को अतिरिक्त स्थायी रिजर्व बनाना होगा, अर्थात्, इसे अधिक करेंसी छापनी होगी।"

उपाय

इस सन्दर्भ में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों (आरबीआई और भारत सरकार) के प्रतिनिधियों को एक साथ आना चाहिए और प्रत्येक को एक-दूसरे के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वार्ता करना चाहिए।

अर्थव्यवस्था

आरबीआई अधिनियम की धारा 7



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

RBI अधिनियम की धारा 7

केंद्र सरकार द्वारा इस धारा का उपयोग:

केंद्र सरकार ने 1934 के आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करने की दिशा में कदम उठाए हैं। आरबीआई अधिनियम की धारा 7 भारतीय रिजर्व बैंक के सम्बन्ध में केंद्र सरकार की कुछ शक्तियों के बारे में बताती है।

धारा 7(1):

भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 7 (1) में कहा गया है, "केंद्र सरकार समय-समय पर बैंक के गवर्नर से परामर्श के बाद बैंक को ऐसे दिशानिर्देश दे सकती है, जो वो जनता के हित में जरूरी समझती है।" इसके दो भाग हैं:

परामर्श - भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और आरबीआई समिति से केंद्र सरकार के परामर्श के बारे में।

दिशा-निर्देश जारी करना- केंद्र सरकार सार्वजनिक हितों में बैंक को कुछ दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड:

इस निकाय में केंद्रीय बैंक और भारत सरकार के अधिकारी हैं, जिसमें सरकार द्वारा नामित अधिकारी भी शामिल हैं। इस बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एक गवर्नर - उर्जित पटेल (नवंबर 2018 तक)
- उप गवर्नर (अधिकतम 4) - केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत
- एन एस विश्वनाथन, विराल वी आचार्य, बी.पी. कानूनगो, महेश कुमार जैन
- 4 गैर-आधिकारिक निदेशक - केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत .. प्रत्येक गैर-आधिकारिक निदेशक भारत के चार क्षेत्रों दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्थित स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करता है।
- 10 गैर-आधिकारिक निदेशक - आरबीआई द्वारा मनोनीत, इन 10 में देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त लोग शामिल हैं।
- केंद्र सरकार के 1 प्रतिनिधि - केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत

केंद्रीय निदेशक मंडल की उपरोक्त संरचना और उनके नामांकन स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि आरबीआई में केंद्र सरकार की भूमिका है। बैंक की शुरुआत और आजादी के बाद से, धारा 7 कभी भी प्रवर्तित नहीं की गयी है।

ये कैसे हुआ:

केंद्र सरकार ने पिछले महीने धारा 7 के तहत परामर्श हेतु बैंक को 3 प्रस्ताव पत्र भेजे थे।

पत्र इस बारे में थे:

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर नए तनावग्रस्त मानदंडों से बिजली कंपनियों को छूट देना। बैंक द्वारा कुछ शक्तिशाली कंपनियों के खिलाफ ये मानदंड जारी किये गए थे। केंद्र ने इन मानदंडों से उन्हें मुक्त करने के लिए कहा।

PCA (प्रॉम्ट करेक्टिव एक्शन) के लिए पूंजी की सीमा के मानदंडों को कम करना - आरबीआई ने 11 बैंकों के खिलाफ पीसीए लिया है। इसलिए, केंद्र ने आरबीआई से उन बैंकों के लिए पूंजी सीमा को कम करने के लिए कहा।

बैंक के रिजर्व से सरकार को अधिक पूंजी प्रदान करना।

RBI ने सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया और सरकार से कहा कि बैंक इन तीन बिंदुओं पर कोई निर्णय नहीं लेगा।

प्राधिकरण के प्रति विश्वास:

दोनों निकायों; केंद्र सरकार और आरबीआई को एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करना चाहिए, जिसका आरबीआई अधिनियम में उल्लेख किया गया था।

ऐसे अनिवार्य और तर्कसंगत कारण हैं जो आरबीआई को स्वतंत्र होने के लिए मजबूर करते हैं।

यदि आरबीआई की अधिकारिता को कोई भी बाधा पहुँचती है तो यह दोनों निकायों के मध्य तनाव उत्पन्न करेगा। यह अंततः देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल देता है। विदेशी निवेशक देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता के बारे में अटकलें और संदेह करना शुरू कर देंगे, और आगे भारत से अपना निवेश निकाल सकते हैं।

नोट्स

दालों की बढ़ती कीमतें



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)
भारत में बढ़ती दालों कीमतें

यह किस बारे में है?:

- खरीफ फसलों की कीमत दो साल के अंतराल के बाद बढ़ी है। पिछले दो सालों में, दालों का उत्पादन बढ़ रहा था जिसके फलस्वरूप कीमत कम हो गयी थी।
- उत्पादन में गिरावट के कारण, कीमतों में वृद्धि हुई।
- एक नीति की आवश्यकता है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करे।
- किसानों को वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य बीमा प्रदान किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को खाद्य मुद्रास्फीति से दूर रखा जाना चाहिए अर्थात् उपभोक्ताओं को कीमतों का भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए।

पृष्ठभूमि:

- 2016-17 में, सरकार ने दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक नीति प्रस्तावित की जिसके अनुसार सरकार ने किसानों से दालों को बढ़ी कीमतों पर खरीदा। इस बढ़ी हुई कीमत ने किसानों को 2017-18 में भी अधिक दाल का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया।
- अरहर की दाल का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 2014 से 2018 तक लगभग 30% बढ़ गया था। पिछले चार वर्षों में मूंग दाल का एमएसपी भी 25% बढ़ा। यह स्पष्ट है कि सरकार दालों के उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रयासरत है।
 - दालों की अधिक आपूर्ति के कारण, इनकी बाजार कीमत कम हो गई। कम होती कीमत एमएसपी के भी नीचे आ गई और इस प्रकार किसानों को एमएसपी की तुलना में भी कम कीमत पर खुले बाजार में दाल बेचनी पड़ी। इससे किसानों के हितों पर असर पड़ा क्योंकि उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा था।
 - अब, उत्पादन कम हो गया है इसलिए कीमतों में वृद्धि हुई है। चूंकि किसानों को बाजार से लाभ नहीं मिल रहे थे और वे अगली फसलों के लिए निवेश करने में सक्षम नहीं थे।
 - खरीफ दालों का उत्पादन इस वर्ष 9.22 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 9.34 मिलियन टन था। सूखे ने फसल के उत्पादन पर भी असर डाला है और सूखे की वजह से आपूर्ति कम हो गई है।

पृष्ठभूमि:

- भारत एक प्रोटीन की कमी वाला राष्ट्र है और इसलिए भारत को फसलों के विविधीकरण पर ध्यान देना चाहिए ताकि खाद्य अनाज को निर्धारित किया जा सके। दालों के साथ ही अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही उत्पादकों के हित सुनिश्चित किये जाने चाहिए।
- पोषण असंतुलन को संबोधित किया जाना चाहिए।
- खरीफ फसलों के मौजूदा मूल्य में वृद्धि रबी दालों को भी प्रभावित कर सकता है। उन्हें बुवाई अवधि में विस्तार का सामना करना पड़ सकता है। कर्णाटक और महाराष्ट्र, बोये गए क्षेत्र के आधार पर प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं और इन दोनों ही राज्यों

को कम बुआई के कारण उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इससे स्थिति और गंभीर होगी।

- संतुलनकारी नीति बनाना; क्योंकि नीति को दोनों पक्षों, उत्पादक और उपभोक्ता, का ध्यान रखना चाहिए। उत्पादकों को अगली बुआई और अगली फसलों के लिए उचित मूल्य मिलना चाहिए जबकि देश के आम लोगों के लिए कीमत वहनीय होनी चाहिए।

आगे का रास्ता:

- केंद्र और राज्यों के बीच आवश्यक सम्प्रेषण के साथ एक उचित खरीद अवसंरचना का विकास करना। अतिरिक्त उत्पादन को सरकारों द्वारा संबोधित किया जा सकता है।
- रीयल-टाइम डेटा का उपयोग जो दालों और अन्य वस्तुओं की कीमत अस्थिरता को नियंत्रित और विनियमित कर सकता है।
- मूल्य स्थिरता - सरकार किसानों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन को संगृहीत कर सकती है और अनाज का बफर स्टॉक बनाकर और कीमतों को एक किफायती स्तर पर स्थिर कर सकती है। कम उत्पादन के मामले में, सरकार बफर स्टॉक निकाल सकती है और उपभोक्ताओं में आपूर्ति बढ़ाकर कीमत कम कर सकती है। अरविंद सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों को अवश्य लागू किया जाना चाहिए।

अरविंद सुब्रमण्यम - भारत सरकार के 16वें मुख्य आर्थिक सलाहकार
कार्यकाल - अक्टूबर 2014 से 20 जून 2018

अरविंद सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशें क्या हैं:

- दालों का मूल्य प्रबंधन: दालों की कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए दालों के लिए निर्धारित स्टॉक सीमाएं और निर्यात प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को उनके कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियमों से दालों को हटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादन का राज्य के स्वामित्व वाली मंडियों के बाहर व्यापार किया जा सके।
- दालों की खरीद: सरकार को मूंग, अरहर और उड़द जैसी दालों को उनके एमएसपी पर खरीदने के लिए जोर देना चाहिए। खरीद बढ़ाने के लिए, सरकार को खरीद एजेंसियों को अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये आवंटित करना चाहिए तथा इसके अलावा, खरीद संचालन की निगरानी की जानी चाहिए। यह केंद्र सरकार को साप्ताहिक रिपोर्टिंग और दृश्य छवियों के माध्यम से खरीद के भौतिक सत्यापन जैसे उपायों के माध्यम से किया जा सकता है।
- दालों के लिए एमएसपी: अरहर और उड़द के लिए मुद्रास्फीति के लिए समायोजित एमएसपी 60 रुपये / किग्रा होना चाहिए। चने जैसे रबी दालों के लिए एमएसपी 40 रुपये / किलोग्राम निर्धारित किया जाना चाहिए और तुरंत घोषित किया जाना चाहिए। दालों के लिए संस्थागत व्यवस्था: सरकार को दालों के लिए एक नई संस्थागत व्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य रखना चाहिए।

नोट्स

किसान क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) क्या है?

- यह योजना भारतीय किसानों को किफायती और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए 1998 में शुरू की गई थी।
- सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा KCC के माध्यम से किसानों को सब्सिडीकृत ऋण दिए जाते हैं।
- KCC के लिए पात्रता किसानों को उनके भूमि जोतों के आधार पर जारी किया गया, KCC एक सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है।
- इस योजना के तहत, KCC सीमा को 3-5 साल के लिए स्वीकृत किया जाता है, (एक बार के दस्तावेजीकरण के साथ) और किसानों की आवश्यकताओं के आधार पर हर साल नवीनीकृत किया जाता है।
- इस प्रकार, किसान को हर साल बार-बार समयसाध्य बैंक स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है।
- कृषि अवधि ऋण की तुलना में इस प्रकार के ऋण पर ब्याज दर भी काफी कम है।
- इस योजना के तहत किसानों के पास पुनर्भुगतान का समय पुनः तय करने का विकल्प है।
- लाभार्थी फसल चक्र के विभिन्न चरणों, जैसे बीज की बुवाई, फसलों की कटाई और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए ऋण राशि का उपयोग कर सकते हैं।
- वे फसल-उपरांत / घरेलू और उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ऋण आय का उपयोग कर सकते हैं।

KCC का दुरुपयोग कैसे होता है?

- केसीसी योजनाओं के तहत उधार लिया गया धन अक्सर गैर-कृषि गतिविधियां, जैसे कि रियल एस्टेट निवेश, अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, महंगी कारें और गहनों की खरीद, विदेशी देशों में बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वदेशी ऋण आदि के लिए बदल दिया जाता है।
- उधारकर्ता आमतौर पर खेती के तहत जमीन की मात्रा को बढ़ाकर बैंकों से उच्च ऋण प्राप्त करते हैं।

- केसीसी, विवेकहीन उधारकर्ताओं के लिए बैंकिंग तंत्र का उपयोग करके काले धन को सफ़ेद करने का साधन बन गया है। वे अचल संपत्ति, साहूकारी और मूल्यवान धातुओं के व्यापार आदि अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न काले धन को KCC ऋण के पुनर्भुगतान के माध्यम से बैंक में प्रविष्ट कर देते हैं।
- केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों की एवरग्रीनिंग की प्रथा भी देखी जाती है। एवरग्रीनिंग का आशय एक उधारकर्ता को ब्याज भुगतान में मदद करने के लिए नया ऋण देने को संदर्भित करता है। स्वामित्व वाली भूमि के मामले में, उधारकर्ता अक्सर "डबल डिपिंग" उधारकर्ताओं का सहारा लेते हैं और परिवार के सदस्य उनके स्वामित्व वाली भूमि के उसी टुकड़े के लिए एक ही बैंक से या अलग से कई ऋणों का लाभ उठाते हैं।

चिंताएं क्या हैं?

- केसीसी ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में बैंकों में जमा नकदी के स्रोत के बारे में पर्याप्त जानकारी की कमी।
- रिवाल्विंग कैश फैसिलिटी, जिसके तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर असीमित निकासी और पुनर्भुगतान शामिल हैं, केसीसी को मनी लॉडरिंग के प्रति सुभेद्य बनाती है।
- इस सुविधा का उपयोग कर कोई ग्राहक कम मात्रा में धन को प्रणाली के भीतर और बाहर कर सकता है और आतंकवादी गतिविधियों या आतंक के वित्तपोषण में संलग्न हो सकता है।
- आतंकवादी वित्त पोषण में थोक या भारी मात्रा में नकदी की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु आवश्यकता पड़ने पर छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए अधिकांश चेतावनी निगरानी प्रणाली आतंकवादी वित्त पोषण गतिविधि के पैटर्न पर ध्यान नहीं दे पाती।

समाधान:

- बैंकों को केवाईसी मानदंडों को मजबूत करने, धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करने, केसीसी नीतियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, और केवल जरूरतमंदों के लिए केसीसी सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- भूमि के एक टुकड़े पर कई लोगों द्वारा ऋण लिए जाने को रोका जा सकता है। फील्ड इंटेलिजेंस, मिस्ट्री शॉपिंग तथा साथ ही व्यापक डेटा एनालिटिक्स का उपयोग बैंकों को शुरुआती चरण में ही खतरे पता लगाने और इस खतरे से लड़ने में मदद कर सकता है।
- तत्काल उपचार उपायों की अनुपस्थिति में, केसीसी मनी लॉडरिंग का अगला वाहक भी हो सकता है।

अर्थव्यवस्था



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

वीजा और मास्टरकार्ड ने रुपए कार्ड पर प्रधानमंत्री से अनुरोध किया

रुपे (RuPay):

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया।
- 26 मार्च, 2012 को लॉन्च किया गया।
- यह भारत में घरेलू भुगतान प्रणाली की आवश्यकता के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश के तहत बनाया गया था।
- वीजा और मास्टरकार्ड की सेवाओं के तहत लेनदेन की लागत अधिक थी।

► NPCI, जो रुपये कार्ड योजना का प्रबंधन करता है, के आंकड़ों से पता चलता है कि प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों पर रुपये कार्ड का उपयोग 135% बढ़ गया है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2018 में 459 मिलियन लेनदेन में प्रयोग किया गया है जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 195 मिलियन थी।

रुपे के साथ प्रतिद्वंद्विता:

मास्टरकार्ड ने जून में संयुक्त राज्य सरकार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुपये कार्ड पर घरेलू भुगतान नेटवर्क के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग कर रहे थे।

देशभक्ति के दृष्टिकोण से:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि भारतीय डिजिटल लेनदेन के लिए रुपये कार्ड का अधिक उपयोग करते हैं, तो यह राजस्व उत्पन्न करेगा और आखिरकार लोगों की सेवा में और उससे राष्ट्र की सेवा में योगदान करेगा। यूएसटीआर (संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि) के कार्यालय में एक लिखित बयान में मास्टरकार्ड ने एक लिखित बयान में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा रुपये कार्ड के प्रचार के कारण कंपनी ने कुछ मुनाफा खो दिया है। कई भारतीय कंपनियां यू.एस.ए. में काम करती हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार किसी भी तरह भारत के पक्ष में है।

मास्टरकार्ड	वीज़ा	अमेरिकन एक्सप्रेस	डिस्कवर
<ul style="list-style-type: none"> ► इंटरबैंक कार्ड कारपोरेशन के रूप में 1966 में स्थापित ► मुख्यालय - न्यूयॉर्क, यू.एस.ए. ► अध्यक्ष, सीईओ - अजयपाल सिंह बग्गा 	<ul style="list-style-type: none"> ► 1958 में बैंक अमेरिकार्ड के रूप में स्थापित ► H.Q. - फोस्टर सिटी, कैलिफोर्निया, यू.एस.ए. ► संस्थापक - डी हॉक ► सीईओ - अल्फ्रेड एफ केली 	<ul style="list-style-type: none"> ► बफेलो, न्यूयॉर्क, यू.एस.ए. में 1850 में स्थापित ► H.Q. - न्यूयॉर्क, यू.एस.ए. ► अध्यक्ष, सीईओ - स्टीफन जे स्केरी 	<ul style="list-style-type: none"> ► 1985 में स्थापित H.Q. - रिवरवुड, इलिनॉय, यू.एस.ए. ► सीईओ - रोजर होचस्विल्ड

लेनदेन की लागत:

रुपए - 2.5 रुपये, मास्टरकार्ड और वीज़ा - 3.25 रुपये, अमेरिकन एक्सप्रेस - 3.75 से 4 रुपये

अर्थव्यवस्था



12 छोटे उद्योगों की पहल

(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)
प्रधानमंत्री द्वारा MSME क्षेत्रक हेतु ऐतिहासिक सहायता एवं आउटरीच पहलों का प्रारम्भ किया गया
2 नवंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) समर्थन और आउटरीच कार्यक्रम प्रारम्भ किया।

MSME से बड़ी संख्या में रोजगार आते हैं।
MSME भारत में प्रमुख रोजगार सृजकों में से एक हैं।

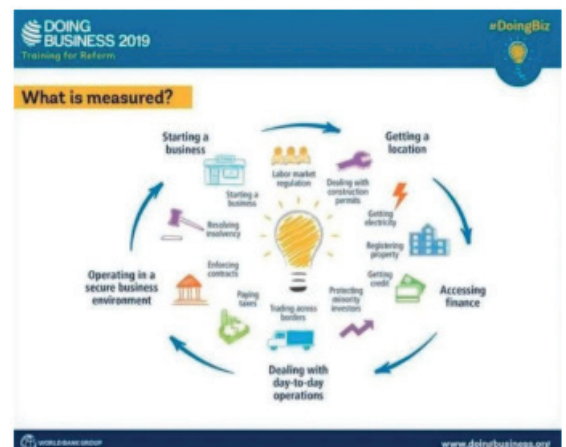
नोट्स

प्रधानमंत्री ने 12 निर्णय किए जो MSME क्षेत्र के लिए एक नए अध्याय का प्रारम्भ करेंगे।

मूल बातें

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की सफलता का भारत की "इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस" रैंकिंग

सुधारों की सफलता का भारत की "इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस" रैंकिंग में वृद्धि से अनुमान लगाया जा सकता है। यह चार वर्षों में 142 से 77 तक आ गयी है।



प्रधानमंत्री ने कहा कि MSME क्षेत्र को पाँच मुख्य पहलुओं पर सुविधा प्रदान की जाएगी। इनमें ऋण तक पहुँच, बाजार तक आयकर विवरण: एक्सएमएल प्रारूप में तीन साल के लिए आयकर रिटर्न की आवश्यकता है। आयकर कोड और ई-फाइलिंग विवरण भी आवश्यक हैं।

GST विवरण: आवेदक से उसका GST आईडी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।

स्वामित्व विवरण: आवेदकों को अपने उद्यमों के स्वामित्व पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों को व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होगी पहुँच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने में आसानी, और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना शामिल है।

ऋण तक पहुंच - भाग 2

प्रधानमंत्री ने सभी GST पंजीकृत MSME के लिए ताजा या वृद्धिशील ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता के रूप में दूसरी घोषणा की।

निर्यातकों के लिए (जो प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट अवधि में ऋण प्राप्त करते हैं), प्रधान मंत्री ने ब्याज छूट 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा की।

विवरण:

केवल 5 9 मिनट में 1 करोड़ रुपये रुपये तक के ऋण

<https://www.psbloansin59minutes.com/home>

ऋण राशि 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच होगी।

ब्याज दर (RoI) 8% से शुरू होती है।

आवेदन के सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद, 7-8 कार्य दिवसों में ऋण राशि वितरित की जाएगी।

संपार्श्विक के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल सीधे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइज़ स्कीम से जुड़ा हुआ है।

पंजीकरण के लिए, उधारकर्ता को कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसा उधारकर्ता जिसका प्रस्ताव उधारदाताओं के उत्पादों से मेल खाता है और जो सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है; उसे 1,000 रुपये (साथ ही कर अतिरिक्त) की धनराशि का भुगतान करना होगा।

पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन एक बार आवेदक का प्रस्ताव बैंक के उत्पादों से मेल खाता है, तो उधारकर्ता को 1,000 रुपये (साथ ही कर अतिरिक्त) का शुल्क जमा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज़:

बैंक खाता विवरण: पीडीएफ प्रारूप में छह महीने का बैंक स्टेटमेंट जमा करना आवश्यक है।

ई-केवाईसी पेपर: एक डिजिटलीकृत संस्करण को अपलोड करने की आवश्यकता है।



ऋण तक पहुंच- भाग 3

500 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले सभी कंपनियों अब अनिवार्य रूप से ट्रेड रिसीवबल ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) में लाई जाएंगी।

यह उद्यमियों को बैंकों से क्रेडिट तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। यह नकदी चक्र की समस्याओं का समाधान करेगा।

ट्रेड रिसीवबल डिस्काउंटिंग सिस्टम या TReDS

ट्रेड रिसीवबल डिस्काउंटिंग सिस्टम या TReDS, भारतीय

रिज़र्व बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हितों की रक्षा के लिए की गयी एक पहल है। बड़े संगठनों के कारण MSME के लिए एक छोटी अवधि में अपनी व्यापार प्राप्ति के लिए तरल निधि में परिवर्तित करना बहुत कठिन होता है।

► ऐसे में TReD (जोकि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है) ने दो या दो से अधिक फाइनेंसर्स के माध्यम से कॉर्पोरेट खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्ति के वित्त पोषण को मशीनीकृत किया है, जिसे ट्रेड रिसीवबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसमें सभी पंजीकृत MSMEs उद्भूत मूल्य के साथ TReDS के माध्यम से बिल ऑफ़ एक्सचेंज या इनवॉइस पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

बाजारों तक पहुंच

► सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अब अपनी कुल खरीद के 20 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत को अनिवार्य रूप से MSMEs से खरीदना होगा।

► MSMEs से अनिवार्य 25 प्रतिशत खरीद में से 3 प्रतिशत अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित होगी।

► केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब अनिवार्य रूप से GeM (सरकारी ई-बाज़ार) का हिस्सा होना चाहिए।

तकनीकी उन्नयन

► तकनीकी उन्नयन पर, प्रधान मंत्री ने कहा कि देश भर में टूल रूम्स उत्पाद डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

► उनकी सातवीं घोषणा यह थी कि पूरे देश में 20 हब बनाए जाएंगे, और टूल रूम के रूप में 100 स्पेक्स स्थापित किए जाएंगे।

इज़ ऑफ़ इंडिंग बिजनेस

► फार्मा MSMEs के क्लस्टर का गठन होगा।

► इन क्लस्टरों को स्थापित करने की 70 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।

► 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों के तहत रिटर्न को अब साल में केवल एक बार दायर करने की आवश्यकता होगी।

► एक अध्यादेश लाया गया है, जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघन के लिए, उद्यमी को अब न्यायालयों की शरण नहीं लेनी होगी बल्कि सरल प्रक्रिया के माध्यम से सही किया जा सकते हैं।

MSME क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

► यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा कि उनके पास जन धन खाते, भविष्य निधि और बीमा है।

नोट्स



एटीएम बंद

(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

भारत के आधे से ज्यादा एटीएम बंद हो सकते हैं



नोट्स

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर के अंत तक भारत में 221,492 एटीएम थे। कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री (CATMi) के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को मार्च 2019 तक देश भर में लगभग 1.13 लाख एटीएम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

कुछ मूल बातें आपको जाननी चाहिए

एटीएम को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है

1. बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम
2. ब्राउन लेबल एटीएम
3. व्हाइट लेबल एटीएम

एटीएम की ये श्रेणियां एटीएम के स्वामित्व, अवस्थिति एवं एक सेवा प्रदाता के साथ बैंक के सेवा अनुबंध के आधार पर हैं।

बैंक के स्वामित्व वाले एटीएमएस क्या हैं?

- इन एटीएम मशीनों की स्थापना बैंक द्वारा की जाती है तथा इनपर बैंकों का स्वामित्व होता है। बैंक उनके संचालन और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार होता है।
- बैंकों को कैश लोडिंग, एएमसी और एटीएम की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी दी जाती है।

ब्राउन लेबल एटीएमएस क्या हैं?

- ब्राउन लेबल एटीएम के मामले में, सेवा प्रदाता के पास एटीएम मशीन के हार्डवेयर का स्वामित्व होता है। एटीएम साइट की पहचान करना, भू-स्वामी के साथ लीज़ एग्रीमेंट, एटीएम कियोस्क को बिजली की आपूर्ति का उत्तरदायित्व

भी सेवा प्रदाता का है। इस प्रकार, एक सेवा प्रदाता एटीएम के रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेता है जबकि प्रायोजक बैंक नकदी प्रबंधन की ज़िम्मेदारी लेता है और बैंकिंग नेटवर्क को एटीएम की कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

- प्रायोजक बैंक का लोगो ब्राउन लेबल एटीएम कियोस्क परिसर में प्रदर्शित होता है। ब्राउन लेबल एटीएम बैंकों के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी समाधान हैं।

व्हाइट लेबल एटीएमएस क्या हैं?

- व्हाइट लेबल एटीएम का स्वामित्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पास होता है और वे ही इसका संचालन भी करती हैं।
- आरबीआई ने ऐसे एटीएम खोलने के लिए गैर-बैंकिंग इकाइयों को लाइसेंस या अनुमति दी है।
- न्यूनतम 100 करोड़ के शुद्ध मूल्य वाली कोई भी गैर बैंकिंग इकाई व्हाइट लेबल एटीएम के लिए आवेदन कर सकती है।



इसके सदस्य:

एटीएम प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी),
ब्राउन-लेबल एटीएम नियोजक (बीएलए)
और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्ल्यूएलए)
कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री (CATMi)

नोट्स

- CATMi द्वारा संचालन की अक्षमता के कारण मार्च 2019 तक लगभग 50 प्रतिशत ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) को बंद किया जा सकता है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की आबादी पर कुप्रभाव पड़ेगा।

- वर्तमान में भारत में लगभग 2,38,000 एटीएम हैं, जिनमें से लगभग 1,13,000 एटीएम (1,00,000 ऑफ-साइट और 15,000 से अधिक व्हाइट लेबल एटीएम समेत) बंद किये जा सकते हैं।

एटीएम बंद करने के कारण?

CATMi के अनुसार, "जबरन बंद किये जाने के लिए एटीएम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन्नयन के लिए हालिया नियामक दिशानिर्देशों को पूरा करने की अक्षमता, नकदी प्रबंधन मानकों पर हालिया अधिदेश और कैश लोड करने के कैसेट स्वेप विधि जैसे कारक उत्तरदायी हैं।"

उन्नयन पर बहुत खर्च होगा

एटीएम में कैसेट स्वेप का प्रारम्भ तथा अन्य उन्नयनों के लिए ₹ 3,200-4,800 करोड़ रुपये का भारी व्यय होगा।

उन्नति

बैंकों का मानना है कि ऑन-साइट एटीएम को नियामक निर्देश से छूट दी जानी चाहिए, जिसके अनुसार बैंकों को अपने एटीएम में लॉक सक्षम कैसेटों का उपयोग करने की आवश्यकता है (जिसे नकदी भरने के समय बदला जाएगा)।



उपरोक्त चित्र लॉक सक्षम कैसेटों का है जिनका मूल्य लगभग 20 से 40 हजार तक है।



भारत में एटीएम उद्योग "टिपिंग प्वाइंट" तक पहुंच गया है, और जब तक कि इन निवेशों के लिए बैंकों द्वारा एटीएम नियोक्ता को मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावना है कि अनुबंध सरेंडर कर दिए जायेंगे तथा बड़े पैमाने पर एटीएम बंद हो जायेंगे।

प्रधानमंत्री जन धन योजना को बड़े पैमाने पर हानि होगी

Forging Financial Inclusion

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana

Objective: Banking for all by providing basic banking accounts with a debit card that includes inbuilt accident insurance

RuPay Debit Card with inbuilt Rs 1 lakh accident insurance cover	First phase of the mission: Starts this month, would end in January 26, 2015
By January 26, people opening accounts will get additional Rs 30,000 life insurance	Second phase: Will start from 2015 till 2018, covering aspects like micro insurance and pension schemes like 'Swavalamban'
A record 1.5 crore accounts opened on Aug 28	

- ▶ एटीएम बंद नहीं होने चाहिए।
- ▶ इसके कारण ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा।
- ▶ ग्रामीण लोग अब इसका प्रयोग कर रहे हैं।
- ▶ यदि 1.13 लाख एटीएम बंद हो जाएंगे तो नोटबंदी के समय की परिस्थिति फिर सामने आ जाएगी अर्थात् एटीएम के सामने लंबी कतारें देखने को मिलेंगे।
- ▶ हमें आने वाले समय में यह देखना होगा कि आरबीआई अपने दिशानिर्देशों पर छूट देगा या नहीं और बैंक इनका वित्त पोषण करेंगे या नहीं।

नोट्स

भूगोल और पर्यावरण

2050 तक
कोआला
ऑस्ट्रेलिया
में विलुप्त

(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

2050 तक ऑस्ट्रेलिया में कोआला (koalas) विलुप्तीकरण का सामना करेगा

UPSC के दृष्टिकोण से GS प्रश्नपत्र- 3 सूखा(सूखे का प्रभाव), शहरीकरण, कृषि प्रभाव)

हाल ही में क्या हुआ है?

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (विश्व वन्यजीव कोष) ऑस्ट्रेलिया और नेचर कंज़र्वेशन काउंसिल (एनसीसी) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भूमि पर से पेड़ों की कटाई और उसका कमजोर और लुप्तप्राय प्रजातियों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए उत्तरी एनएसडब्ल्यू(न्यू साउथ विल्स) की चुनिंदा उपग्रह छवियों का उपयोग किया गया है। कोआला न्यू साउथ विल्स में पाए जाते हैं। कोआला यूकेलिप्टस (सफेदा) के पेड़ पर रहते हैं। पेड़ काटे जाने के कारण इन पर रहने वाले कोआला विलुप्त हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ऑस्ट्रेलिया का अनुमान है कि एनएसडब्ल्यू में 20,000 से कम कोआला बचे हैं और वर्तमान दर से वे 2050 तक विलुप्त होने की स्थिति पर बढ़ रहे हैं।



कोआला

- कोआला, ऑस्ट्रेलिया के जंगली जानवरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा और प्रतिष्ठित जानवर हैं।
- वे अपना अधिकांश जीवन अपने यूकेलिप्टस पेड़ों पर दिन भर सोते हुए बिताते हैं और शाम के समय कुछ घण्टे पत्तियां खाते हैं।
- वे यूकेलिप्टस की पत्तियों खाते हैं।
- कोआला पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं।
- इनके शिकारी पेड़ पर इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। कोआला की लम्बाई लगभग 60 - 85 सेमी और वजन लगभग 14 किलो होता है।
- यद्यपि आपने सुना होगा कि लोग उन्हें कोआला 'भालू' कहते हैं, ये प्यारे जानवर बिलकुल भी भालू नहीं हैं

वे वास्तव में मार्सुपियल्स हैं जैसे कंगारू (पाउच रखने वाले)।
➤ अधिकांश मार्सुपियल्स के पाउच होते हैं, जिसमें उनके नवजात शिशु विकसित होते हैं।

यूकेलिप्टस वृक्ष

यूकेलिप्टस, ऑस्ट्रेलिया के सबसे खास पहचान वाले पेड़ों में से एक है और यह जैव-विविधता तथा पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।



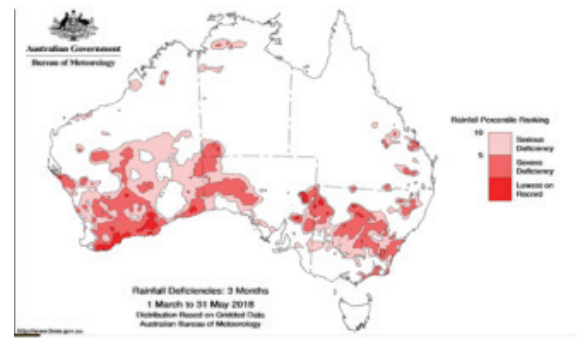
कोआला के विलुप्त होने के पीछे के कारण:

- कोआला जो ऑस्ट्रेलिया में 25 मिलियन सालों से रह रहे थे, ने यूरोपियन उपनिवेशीकरण के कारण हुए शहरीकरण, कृषि एवं खनन विकास, जलवायु परिवर्तन और उनकी खाल के व्यावसायिकीकरण की वजह से 1930 के दशक तक अपना अधिवास खो दिया।
- शहरीकरण: जब शहरीकरण होता है, तो लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं। बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए हमें जंगल को साफ़ करने की जरूरत होती है जो अंततः कोआला भालू को प्रभावित करता है। कोआला की त्वचा का उपयोग कई उत्पादों बनाने में भी किया जाता है।
- 2017 में राज्य सरकार ने मूलव्यवस्थापन अधिनियम, 2003 को निरस्त करने का फैसला किया, जोकि किसानों को पेड़ काटने से रोकता था।
- खाद्य पदार्थ और शरण वाले पेड़ों के विनाश तथा जंगलों के विखंडन से कोआला संकटग्रस्त हो गए, और वाहनों से टकराने, कुत्तों के आक्रमण एवं तनाव के कारण उनकी मृत्यु दर बढ़ने लगी।
- कुछ हिस्सों में, कोआला क्लेमाइडिया, जो कि एक जीवाणु संक्रमण है, के कारण मर जाते हैं। यह जननांगों और आंखों को हानि पहुंचाता है, जिससे नपुंसकता और अंधापन होने लगता है और धीमे धीमे मृत्यु का कारण बनता है। इस बैक्टीरिया की बढ़ती हुई भौगोलिक पहुंच, कई प्राणियों में संक्रमण का कारण बन रही है।

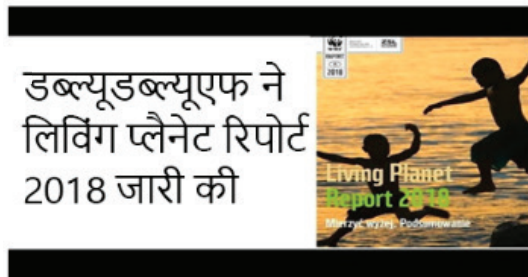
सूखे के कारण:

- ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र को सूखे का सामना करना पड़ रहा है, यूकेलिप्टस के पेड़ के लिए पानी की उपलब्धता कम हो रही है, इसलिए कोआला भालू को भोजन नहीं मिल पा रहा है

(भोजन अर्थात यूकेलिप्टस पेड़ की पत्तियाँ)।
ऑस्ट्रेलियन सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए एवं आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
मनुष्य को जंतुओं के प्रति किसी प्रकार की चिंता न करने के अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में यह प्रत्यक्ष तौर पर मानवों को ही प्रभावित करेगा।



भूगोल और पर्यावरण



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से: प्रारंभिक परीक्षा और GS Paper-3rd : पर्यावरण

रिपोर्ट 2018 व्यक्त करती है:

यह रिपोर्ट वर्ल्ड वाइडलाइफ फण्ड द्वारा द्विवर्षीय रूप से जारी की जाती है। यह ग्रह की स्थिति के बारे में बताती है और यह पृथ्वी और उसके पारिस्थितिक पर्यावरण की स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित है। इस रिपोर्ट में पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और मानव जाति के साथ इनके पारस्परिक संबंध शामिल होते हैं। विश्व भर की सरकारें, इस रिपोर्ट पर ध्यान दे सकती हैं और उन्हें सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीति निर्माण करना चाहिए।

- अब पृथ्वी की भूमि का महज एक चौथाई भाग ही मानव गतिविधियों से मुक्त है और 2050 तक, केवल 1/10 भाग ही खाली बचा रहेगा। अब, पृथ्वी पर केवल एक चौथाई भूमि मानव गतिविधियों के प्रभाव से मुक्त है। और 2050 तक केवल एक-दसवां हिस्सा निरंकुश छोड़ा जाएगा।
- भूमि क्षरण में वनों का नुकसान शामिल है। हालाँकि वैश्विक स्तर पर पुनर्वनीकरण और वृक्षारोपण के कारण इस नुकसान में कमी आयी है, लेकिन एक विशिष्ट बात है कि पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ और भूगोल में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलाव आता रहता है। अतः एक जगह पर वृक्षारोपण, अन्य इलाके में जंगल की कमी की पूरी तरह क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता
- 1950 से अब तक दुनिया के महासागरों से लगभग 6 बिलियन टन मछली और अकशेरुकी जीव पकड़े गए हैं।
- प्लास्टिक प्रदूषण समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच तक भी पहुँच गया
- 1970 से 2014 के बीच कई प्रजातियों की आबादी को 60% की कमी का सामना करना पड़ा है।
- दक्षिण और मध्य अमेरिका में 1970 की तुलना में सबसे ज्यादा 89% की बेहद नाटकीय ढंग से कमी आई है।
- 'फ्रेशवाटर इंडेक्स' के अनुसार, ताजे पानी की प्रजातियाँ 1970 से 83% की कमी आयी है।

- पिछले 30 वर्षों में, एक आकलन के तहत पृथ्वी ने अपने उथले पानी में पाए जाने वाले प्रवाल (कोरल) का आधा हिस्सा खो दिया है।
- ऐमज़ॉन का 20% हिस्सा सिर्फ पिछले 50 वर्षों में गायब हो गया है।

सभी आर्थिक गतिविधियाँ अंततः प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर निर्भर करती हैं, जिनका वार्षिक 125 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होने का अनुमान है। विभिन्न औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों द्वारा अर्जित जीडीपी से सतत विकास के प्रति अपने कर्तव्यों का भुगतान किया जाना चाहिए। मानव जनसंख्या में विस्फोट और उनके द्वारा प्रकृति का उपभोग ही इस ग्रह के अभूतपूर्व परिवर्तन के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। व्यापार एवम वित्त उद्योग ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए हैं कि वैश्विक पर्यावरण, किस तरह देश, औद्योगिक क्षेत्रों और वित्तीय बाजारों की समष्टि अर्थव्यवस्था (मेक्रोएकॉनॉमी) के प्रदर्शन पर प्रभाव डालेगा। और नीति निर्माता परेशान हैं कि हम किस प्रकार, प्रकृति एवं जैवविविधता में कमी के साथ, सततविकास के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे?

CBD 2050:

- **कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी** का अनुमान है कि पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने, के लिए ग्रह को स्वस्थ बनाए रखने और सभी लोगों को आवश्यक लाभ प्रदान करने के लिए जैव विविधता का मूल्यवान, संरक्षित, सुधारपूर्वक और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए। संरक्षण वैज्ञानिक द्वारा 'जैव विविधता के लिए ब्लूप्रिंट 2020-2050' का प्रस्ताव दिया गया है, यह 'जैव विविधता पर सम्मेलन' (CBD) के माध्यम से भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण है।

नोट्स

ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ क्या है?



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

ग्लेशियल झीलों में बाढ़ का प्रस्फोट

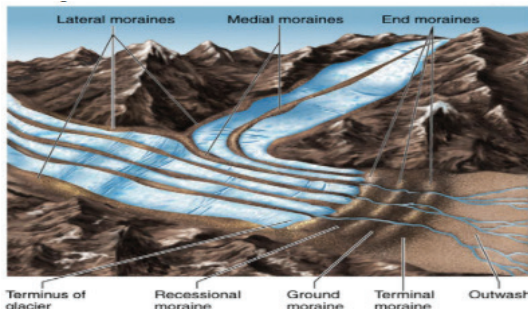
यूपीएससी के दृष्टिकोण से - जीएस प्रश्नपत्र 1 और 3

हाल ही में क्या हुआ है:

- सिक्किम में आपदा प्रबंधक और वैज्ञानिक ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड (बाढ़ के प्रस्फोट) को रोकने के लिए झील से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल रहे हैं।
- सिक्किम हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट बाढ़ (जीएलओएफ), चिंता का विषय है क्योंकि इस क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने के कारण कई झीलों का निर्माण हुआ है।

एक ग्लेशियल झील क्या है?

बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से ग्लेशियल झीलें बनती हैं और जब यह इकट्ठा हो जाती है तो झील की तरह रूप लेती है।



मोरैन ग्लेशियल झीलों के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोरैन मुख्य रूप से संचित पत्थर और तलछट हैं जो ग्लेशियर द्वारा जमा किए जाते हैं। ग्लेशियल झीलों के लिए तलछट का संचय आवश्यक है।

ग्लेशियरों का पिघलना:

- पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्लेशियरों के पिघलने के कारण, झीलों में जल की मात्रा में वृद्धि हुई है और बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है।
 - सिक्किम के दो महत्वपूर्ण ग्लेशियर झील हैं:
 - ज़ेमु ग्लेशियर - ज़ीमु नदी की उत्पत्ति
 - लोनाक ग्लेशियर झील
- दोनों ग्लेशियर अब झीलों में ग्लेशियल बर्फ के पिघलने का सामना कर रहे हैं और इस प्रकार झीलों में पानी का स्तर सिक्किम में बाढ़ का खतरा पैदा कर रहा है।

ग्लोफ के कारण:

- मानव गतिविधियों के कारण हाल के वर्षों में हिमालय में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा और पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन परिवर्तित हो गया है।
- ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर की वापसी से ग्लेशियर झीलों की संख्या बढ़ती जा रही है और मौजूदा ग्लेशियर झीलों के आकार में वृद्धि हो रही है।
- इसमें योगदान देने वाली मानवीय गतिविधियों में सामूहिक पर्यटन विकास संबंधी हस्तक्षेप जैसे सड़क और जल विदूत परियोजना शामिल है।
- ब्लैक कार्बन जो भूमध्य क्षेत्र से भारत तक फैल रहा है वह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो अल्बेडो प्रभाव के कारण पहाड़ पर बर्फ पिघला देता है। ब्लैक कार्बन तब उत्पन्न होता है जब उद्योगों में ईंधन पूरी तरह जलाया नहीं जाता है। ब्लैक कार्बन स्वयं में ऊष्मा संचित कर लेता है जिससे आसपास के तापमान में वृद्धि होती है।

बाढ़ के लिए किए गए उपाय:

- पाइपों को उच्च ऊंचाई पर ले जाने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पाइप और अन्य सामग्रियों को 17,000 फीट पर स्थित झील में ले जाने के लिए याक का उपयोग किया जाता है।
- सिक्किम ने दक्षिण लोनाक झील में एक झील निगरानी और सूचना प्रणाली (जल स्तर सेंसर) स्थापित की है। सेंसर झील के पानी का स्तर बताता है और पानी के स्तर में अचानक उतार-चढ़ाव होने पर भी झील के स्तर पर नजर रखता है।

भूगोल और पर्यावरण

महाराष्ट्र सूखा 2018



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

यह किस बारे में है?

महाराष्ट्र सरकार ने 32 जिलों के 201 तालुकों की पानी की कमी के कारण 'सूखे जैसी स्थितियों' के रूप में पहचान की है।

ये गाँव निम्नलिखित जिलों से संबंधित हैं:

जलगांव - 13, अहमदनगर - 12, बीड - 11 और सोलापुर - 11

वर्तमान में संकट:

- पिछले साल राज्य के 14,679 गांवों को सूखे का सामना करना पड़ा जबकि इस बार 20,000 गांव इस आपदा का सामना कर रहे हैं।
- महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों, उत्तरी गुजरात (सौराष्ट्र, कच्छ) और उत्तरी कर्नाटक को पानी की कमी की वजह से सूखे का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है।
- खरीफ फसलों में पर्याप्त मात्रा में पानी और सिंचाई की आवश्यकता होती है और भारत फसलों के दौरान पानी की आपूर्ति के लिए मानसून पर भारी निर्भर करता है।

- इन क्षेत्रों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून से अच्छी बारिश होती है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का पहला भाग अपनी पहली छमाही चरण में अच्छा था, लेकिन दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दूसरे छमाही के दौरान यह अच्छा नहीं था। किसानों ने पहले ही फसलों की बुआई कर दी है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में 682.9 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले महाराष्ट्र में जून और सितंबर महीनों के बीच 534.6 मिमी बारिश हुई।

प्रभाव:

- रबी की फसलें प्रभावित होंगी। अपर्याप्त बारिश के कारण, मिट्टी में समुचित रूप से नमी नहीं होगी। रबी की फसल सर्दियों में शुरू होती है और बसंत ऋतु में इनकी कटाई होती है।
- कृषि मंत्रालय ने खुलासा किया है कि अब तक फसल क्षेत्रों में 16% गिरावट आई है।
- सूखे की स्थिति ने राज्यों के मवेशियों और भैंसों के लिए पानी की समस्या में भी वृद्धि की है। इस प्रकार सूखे ने मवेशियों के मालिकों को भी प्रभावित किया है।
- विशेष रूप से महाराष्ट्र में इन राज्यों से प्रवासन में काफी वृद्धि हुई है। पारिश्रमिक की कमी ने उन्हें इसके लिए मजबूर कर दिया है।

आगे की राह:

- सरकारों को धरातलीय वास्तविकताओं के आधार पर जल संसाधनों को सुरक्षित करना होगा।
- इन क्षेत्रों में सूखे की आधिकारिक घोषणा अधिकारियों को इस समस्या पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी और वे सुधारात्मक उपाय कर सकेंगे।
- चारा शिविर मवेशियों के उचित रखरखाव में मदद कर सकते हैं।
- सरकार मनरेगा की उत्पादकता का भी उपयोग कर सकती है जो श्रमिकों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में ग्रामीण मजदूर सूखे के प्रबंधन में भी संलग्न हो सकते हैं।
- सूखे के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य परिवारों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से समर्थन और धन प्रदान किया जाना चाहिए।
- अधिकारियों और सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता और समर्थता सुनिश्चित करना चाहिए। किसानों के लिए उनके कामों के बदले संतोषजनक पारिश्रमिक बीमा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। अगर आपूर्ति मात्रा में कम हो जाती है, तो यह अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को प्रभावित करेगी जो मुख्य रूप से ग्रामीण है।

भूगोल और पर्यावरण

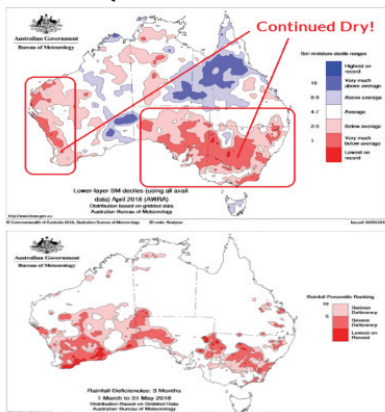
ऑस्ट्रेलिया के वन्य जीवन पर सूखे का प्रभाव



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)
ऑस्ट्रेलिया में सूखे का प्रभाव, किसानों और वन्यजीवन के लिए निराशा
यूपीएससी के दृष्टिकोण से - जीएस प्रश्नपत्र 3, पर्यावरण

हाल ही में क्या हुआ है?:

ऑस्ट्रेलिया में एक भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे देश का वन्यजीवन खतरे में है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में कई सालों से "बिग ड्राई" की स्थिति है।



कुछ क्षेत्रों में भारी मात्रा में सूखे की स्थिति है जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी क्षेत्र, देश का न्यू साउथ वेल्स।

ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान:

- ग्रेट सैंडी रेगिस्तान
- तनामी रेगिस्तान
- लिटिल रेगिस्तान
- गिब्सन रेगिस्तान
- ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान
- सिम्पसन रेगिस्तान
- Strzelecki रेगिस्तान

ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति का होना कुछ नया नहीं है, लेकिन जब यह लंबे समय तक रहता है, तो यह महाद्वीप पर समस्या उत्पन्न करना शुरू कर देता है। और इन रेगिस्तानों के भीतर जीवन जल निकायों पर निर्भर है। इसलिए, यदि सूखे की स्थिति लम्बे समय तक रहती है, तो यह वन्यजीवन को नुकसान पहुंचाती है।

सूखे का असर:

- किसानों ने असफल फसलों, गंभीर पानी की कमी और पशुओं को खिलाने में असमर्थ होने जैसे परेशानियों के बारे में बताया है।
- ऑस्ट्रेलिया के विदेशी जंगली जानवर सूखे के प्रति अनुकूलित होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परित्यक्त कंगारुओं के बच्चों से वालाबीज़ तक धूप से अंधे हो रहे हैं और कोआला (ऑस्ट्रेलियन अबॉरियल हर्बीवोरस मर्सिपियल बियर) यूकेलिप्टस के पत्तों की तलाश में दूर तक घूम रहे हैं। प्यास और जीवित रहने के प्रयासों के कारण, कई जंगली जीव मानव क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रकार उनका शिकार भी किया जा रहा है।

- यह इतना शुष्क है कि जानवर प्रवास के लिए मजबूर हो रहे हैं - हाल ही में ईमूज के एक झुण्ड को ब्रोकरन हिल टाउन शहर में पानी और खाने की खोज में सड़कों में भागता और फुटबॉल मैच के बीच घुसता देखा गया।
- वहां सभी संकेत मौजूद हैं। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल ग्रेट बैरियर रीफ, 2,300 किलोमीटर लम्बा स्ट्रेच जो जैव-विविध समुद्री जीवन से समृद्ध है, खतरे में है। इसने 2016 और 2017 में दो बड़ी ब्लीचिंग (विरंजन) घटनाओं में अपने आधे से अधिक प्रवालों को खो दिया है। ऐसा अनुमान है कि 2018 में भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

Notes:

- कोयला भी सूखे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑस्ट्रेलिया चीन, भारत और अन्य देशों को कोयले की पर्याप्त मात्रा निर्यात करता है।
- ऑस्ट्रेलिया ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को अपनाया है। अतः इसकी सरकारी ऊर्जा नीति का उद्देश्य देश को 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 26% तक कटौती करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप बनाना है।
- ऑस्ट्रेलियाई समझौते और जलवायु परिवर्तन कार्रवाई को अधिक व्यापक रूप से समर्थन देते हैं।

भूगोल और पर्यावरण

रैपिड महासागरीय तापन
आईपीसीसी वैज्ञानिकों द्वारा एक अध्ययन

(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

महासागरों द्वारा 60% ऊष्मा
का प्रतिधारण(Retention):

- UPSC के दृष्टिकोण से- जीएस प्रश्नपत्र-3, प्रश्नपत्र-1, पर्यावरण भी महासागरों द्वारा 60% ऊष्मा का प्रतिधारण:
- वैज्ञानिकों ने कहा कि सदी के पिछले 25 वर्षों में महासागरों ने पूर्व में अनुमानित ऊष्मा से 60 प्रतिशत ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण किया है, जो पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के लिए और भी ज्यादा संवेदनशील कर रहा
 - इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) ने कहा कि दुनिया के महासागरों ने मानव निर्मित कार्बन उत्सर्जन के कारण हुए तापमान वृद्धि का 90% अवशोषण अवशोषित कर लिया है। इसका मतलब है कि ग्रीनहाउस जैसे CO₂, CO₂, NO_x इत्यादि अब वातावरण में मात्रा में अधिक है।
 - महासागर, ग्रह की संपूर्ण सतह के दो तिहाई से अधिक पर विस्तृत हैं और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - लेकिन 'नेचर' जर्नल में एक नया शोध प्रकाशित हुआ है।
 - उसमें यह पाया गया कि पिछले प्रत्येक 25 सालों में महासागरों ने, मनुष्य द्वारा वार्षिक उत्पन्न की जाने वाली बिजली के 150 गुना मात्रा के बराबर ऊष्मा-ऊर्जा अवशोषित कर ली है।
 - पिछले अध्ययनों की तुलना में यह 60% अधिक है।

IPCC के बारे में जानकारी

- इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन पर अन्तरसरकारी पैनल)
- संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी निकाय, जो विश्व को जलवायु परिवर्तन और इसके राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावों पर वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए समर्पित हैं।
- 1988 में बनाया गया, मुख्यालय- जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- मुखिया- होसंग ली

प्रभावों के उदाहरण:

- कैलिफोर्निया की वर्तमान फायरनाडोस एक समसामयिक उदाहरण है। चूंकि महासागर अधिक गर्मी धारण या अवशोषित कर रहे हैं, इसलिए उनके पश्चिमी तट पिछले वर्षों की तुलना में गर्म हैं और यह कैलिफोर्निया के जंगलों में में आग की घटनाओं को बढ़ा रहे हैं।
- जिन इलाकों में उचित वर्षा होनी चाहिए वहां सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने की आशंका है।
- अल-निनो और ला-नीना, पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए - यदि तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है, तो अटाकामा रेगिस्तान के समीप के ठंडी धारा, जिसे हम्बोल्ट करेंट / पेरू करेंट के नाम से जाना जाता है, गर्म हो जायेगी। तो इस बदलाव के कारण जिस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होनी चाहिए, वहाँ अधिक बारिश होने लगेगी।

नोट्स

भारत ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार जीता



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से : GS3 - संरक्षण और संबंधित

समाचार में क्यों?:

- यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, 2018 में प्रदान किया गया। यह सीमापारीय पर्यावरणीय अपराधों से निपटने में ब्यूरो द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है।

डब्ल्यूसीसीबी क्यों चुना गया है?

- डब्ल्यूसीसीबी ने अभिनव प्रवर्तन तकनीकों को अपनाया है जिन्होंने नाटकीय रूप से भारत में सीमापारीय पर्यावरणीय अपराधों के प्रवर्तन में वृद्धि की है।

एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार के बारे में:

- एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार एशिया में सीमापारीय पर्यावरणीय अपराध का मुकाबला करने वाले सरकारी अधिकारियों और संस्थानों / टीमों द्वारा प्रवर्तन में उत्कृष्टता को सार्वजनिक रूप से पहचान और सम्मान देते हैं।
- पुरस्कार उत्कृष्ट व्यक्तियों और / या सरकारी संगठनों / टीमों को दिए जाते हैं जो निम्नलिखित पात्रता मानदंड क्षेत्रों में से एक में सीमापारीय पर्यावरणीय अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय कानूनों के प्रवर्तन में उत्कृष्टता और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं: सहयोग; प्रभाव; नवीनता; अखंडता और लिंग नेतृत्व।

प्रारंभिक परीक्षा बिट्स: वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में:

- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध का मुकाबला करने के लिए MoEFCC के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक बहु अनुशासनिक निकाय है। वन्यजीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने अपराध में रुझानों का विश्लेषण करने और भारत भर में वन्यजीवन अपराधों को रोकने और पहचानने के प्रभावी उपायों को तैयार करने के लिए वास्तविक समय डेटा प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन
- वन्यजीव अपराध डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली ने रुझानों का विश्लेषण करने और ऑपरेशन सेव कुर्मा, थंडरबर्ड, विल्डनेट, लेस्कनो, बिर्बिल, थंडरस्टोरम, लेस्कनो-द्वितीय जैसे अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संचालन करने में मदद की है जिसके परिणामस्वरूप 350 वन्यजीव अपराधियों की गिरफ्तारी और पशु की हड्डियों को बरामद किया गया है।
- ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ब्यूरो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विध्वंस, प्रासंगिक नीति और कानून वाले वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को भी सलाह दे सकता है।

डब्ल्यूसीसीबी के कार्य:

- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (जेड) के तहत, यह अनिवार्य है:
- संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित खूफिया जानकारी एकत्रित करने और समेकित करना।
- अपराधियों को पकड़ने के लिए और तत्काल कार्रवाई के लिए राज्य और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को इसका प्रसार करना।
- एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना।
- अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यों को समन्वयित करना।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई की सुविधा के लिए संबंधित विदेशी प्राधिकरणों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सहायता करना।
- यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, CITES और इस तरह के किसी आइटम को नियंत्रित करने वाली EXIM नीति के प्रावधानों के अनुसार वनस्पतियों और जीवों के सामानों के निरीक्षण में सीमा शुल्क प्राधिकरणों की सहायता और सलाह देता है।

भूगोल और पर्यावरण

ओजोन परत ठीक हो रही है



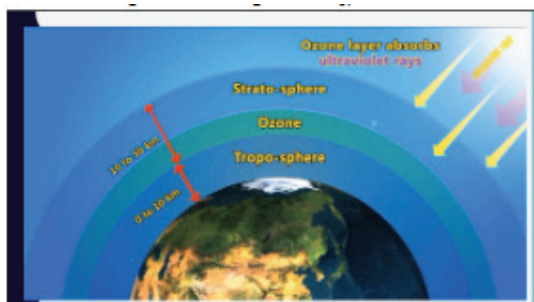
(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण

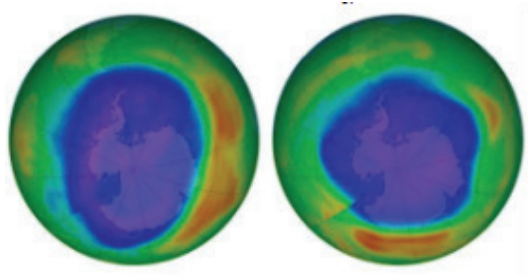
ओजोन परत क्या है

- ओजोन की परत पृथ्वी को ढँकती है और हानिकारक पराबैंगनी या यूवी विकिरण को ग्रह की सतह पर जीवित वस्तुओं तक पहुंचने से रोकती है। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद है, जो कि वायुमंडल की एक परत है और पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर (लगभग 6 से 30 मील) ऊँचाई पर पाई जाती है।

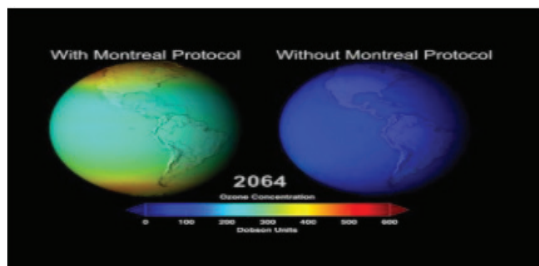
ओजोन परत मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।



इंसानों के लिए ओजोन परत बेहद महत्वपूर्ण है:



यह हरे रंग का हिस्सा ओजोन है। 1970 में वैज्ञानिकों ने पाया कि ओजोन परत में एक छेद है और इस छेद से आने वाली



किरणें छनकर नहीं आ रही हैं और जीवित प्राणियों के लिए बेहद हानिकारक हैं। और उपरोक्त आरेख में ओजोन छिद्र को नीले रंग के हिस्से से दिखाया गया है।

ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन छिद्र, अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर ओजोन की हल्की परतों का एक क्षेत्र है, जिसका निर्माण त्वचा कैसर के बढ़ते मामलों से जुड़ा हुआ है।

ओजोन निम्नीकरण या क्षय के कारण:

- ▶ ओजोन निम्नीकरण कई कारणों के कारण होता है, जिनमें सबसे अधिक प्रभावशाली सीएफसी (क्लोरो फ्लूरो कार्बन) से क्लोरीन का निकलना है जो ओजोन को नष्ट कर देती है।
- ▶ सीएफसी गैस, हेयरस्प्रे, पुराने फ्रिज इत्यादि उत्पादों से निकलती है।
- ▶ सीएफसी समताप मंडल तक पहुँच जाती है और समताप मंडल में वह छोटे कणों में बँट जाती है और उससे क्लोरीन बाहर निकलती है।

सीएफसी क्या है?

- ▶ क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी, क्लोरीन, फ्लोरिन और कार्बन तत्वों के संयोजन से बने यौगिक होते हैं। एयरोसोल, रेफ्रिजरेटर्स और फोम में सीएफसी होती हैं।
- ▶ जब ये सीएफसी हवा में प्रवेश करती है, तो वे वातावरण में ऊपर उठकर ओजोन परत से मिलती है और ओजोन अणुओं को नष्ट करती है।
- ▶ सबसे पहले 1928 ईस्वी में इस्तेमाल किया गया।

सीएफसी तब से सामान्य प्रयोग में आने लगी जबसे विभिन्न सीएफसी यौगिकों का निर्माण किया गया। कुछ बेहतर सीएफसी में से एक फ्रियॉन यौगिक है, जिन्हें रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में शीतलक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता था।

बचाव:

मोंट्रियल प्रोटोकॉल पर क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी)/फ्रियॉन में कमी लाने के लिए हस्ताक्षर किये गए थे।

हस्ताक्षरित: 26 अगस्त 1987

स्थान: मोंट्रियल

प्रभावी: 26 अगस्त 1989

उद्देश्य: सीएफसी उत्सर्जित करने वाले रेफ्रिजरेटर का प्रयोग बंद करना और सीएफसी का प्रयोग करने वाली कंपनियों को प्रतिबंधित करना।

संयुक्त राष्ट्र अध्ययन -2018 का शोध:

- ▶ 'भूभौतिकी शोध पत्र जर्नल' में प्रकाशित अध्ययन ने वायुमंडल की रासायनिक संरचना का अवलोकन करके इस घटना की पुष्टि की है
- ▶ पिछले शोध ने ओजोन परत के क्षरण में आई कमी का संकेत दिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन परत 2080 तक पूरी तरह पूर्ववत हो जाएगी।

ओजोन छिद्र के सही होने के कारक:

- ▶ **मोंट्रियल प्रोटोकॉल:** इसमें अत्यंत ऊँचाई पर स्थित नाजुक ओजोन परत को नुकसान देने वाले मानव निर्मित गैसों को प्रतिबंधित किया गया, और पाया गया कि ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेवार पदार्थों की वायुमंडलीय उपस्थिति में काफी हद तक कमी आयी है और इससे समताप मंडलीय ओजोन लगातार सही हो रही है।
- ▶ रिपोर्ट के अनुसार, अंटार्कटिक ओजोन छिद्र 2060 तक धीमे धीमे 1980 के पहले वाले स्तर पर वापिस आकर बंद हो जायेगा।
- ▶ 2019 में, इस प्रोटोकॉल को किगाली समझौते के अनुसमर्थन के द्वारा सशक्त बनाया जाता है। यह हाइड्रो फ्लूरो कार्बन (एचएफसी), ओजोन सुरक्षित यौगिकों, के उत्पादन को सीमित करता है जो कि शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस हैं।
- ▶ रिपोर्ट के लेखकों ने पाया कि, यदि किगाली संशोधन पूरी तरह कार्यान्वित किया जाता है, तो विश्व इस शताब्दी में 0.4 प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग को वर्जित (avoid) कर सकता है, जिसका अर्थ यह है कि वैश्विक तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने में यह एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।

नोट्स

उत्तर भारत में जलती पराली



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

'दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण स्टबल बर्निंग यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य - जीएस प्रश्नपत्र -1 और भूगोल

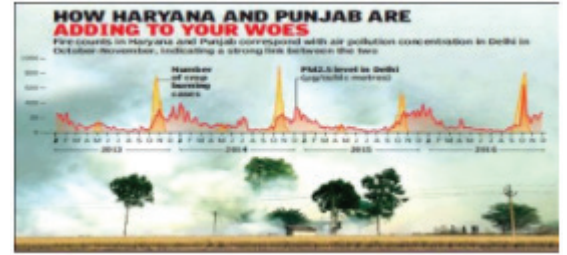
स्टबल बर्निंग क्या है?

- ▶ कटाई के बाद, शेष फसल के अवशेषों को स्टबल कहा जाता है।
- ▶ हरियाणा में कृषि मशीनीकरण राज्य के क्षेत्रों में फसलों के कुछ हिस्सों को छोड़ देता है। अब, नई फसलों को विकसित करने के लिए, क्षेत्र को साफ किया जाना चाहिए और मिटा दिया जाना चाहिए।
- ▶ इसलिए, या तो किसानों को हाथों से उसे हटाना होगा या सबसे आसान समाधान फसल-अवशेष / स्टबल को जलाना है। इसलिए यह विधि हरियाणा के किसानों के लिए आसान है और इस अवशेष से निकलने वाला धुआं उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैलता है जो दिल्ली- एनसीआर की हवा को प्रदूषित कर रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में अक्टूबर-नवंबर में प्रदूषण क्यों अधिक होता है?:

वायुमंडल जुड़ा हुआ है। फसलों के जलने से जो धुआं निकलता है, वो बहुत ऊपर तक जाता है। जलने से तापमान भी पढ़ जाता है

और धुआं बहुत ऊपर तक जाता है। चूंकि, उच्च ऊंचाई पर, तापमान कम हो जाता है, जिससे उच्च अक्षांश पर अधिक दबाव होने लगता है और हवा की दिशा नीचे की ओर बढ़ती है। यह नीचे की हवा में धुआं रहता है जो दिल्ली एनसीआर की हवा में मिल जाता है।



(Picture Courtesy – Times of India)

मुख्य रूप से, चावल और अन्य खरीफ फसलों को कटाई कर खरीद लिया जाता है और फिर किसानों को रबी फसलों के लिए खेतों को तैयार करना होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में स्टबल जला दिए जाते हैं।

नियंत्रित करने के लिए संभावित कदम:

- ▶ राज्य अब किसानों को फसल के बाद स्ट्रॉ को हटाने के लिए मशीनों की खरीद करने के लिए सब्सिडी देना चाहते हैं या फसल के बाद प्रक्रिया कर मशीनरी को सुरक्षित बना सकते हैं।
- ▶ किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम ताकि वे स्टबल जलने के असर के बारे में जान सकें।
- ▶ कृषि विकल्पों को जैव ईंधन और उर्वरकों में परिवर्तित करने जैसे तकनीकी विकल्पों का उपयोग करके, कृषि अवशेषों को संसाधन में बदलने के लिए जलवायु परिवर्तन निधि का उपयोग करने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण हो सकता है।

भूगोल और पर्यावरण

हरे पटाखे

क्या है ?



ग्रीन क्रैकर्स और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

ग्रीन क्रैकर्स में एल्यूमीनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे प्रदूषक या तो नहीं होते हैं या उनमें ये प्रदूषक 30% की मात्रा तक ही होते हैं। ग्रीन क्रैकर द्वारा पार्टिक्यूलेट मैटर्स की निर्मुक्ति को 30% से 40% तक कम किया जा सकता है।

उनके द्वारा प्रदूषण की भूमिका:

सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर, 2018 को बेरियम और सीरीज-क्रैकर्स (हिंदी में, लड़ी या चटाई) का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को आदेश दिया कि वे केवल उन क्रैकर्स को अनुमति देंगे जो सुरक्षा मानदंड को पूरा करते हों। लेकिन, क्रैकर लॉबी, क्रैकर के निर्माण में बेरियम के उपयोग की अनुमति के लिए एक अन्य याचिका दायर करना चाहती थी।

निर्णय में संशोधन:

- ▶ 31 अक्टूबर, 2018 को, सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को दिए गए अपने निर्णय में संशोधन किया, जिसमें दीपावली और अन्य त्योहारों में 2 घण्टे (8 p.m. से 10 p.m.) के लिए पटाखे जलाने की अनुमति दी गयी और दिल्ली-एनसीआर के अतिरिक्त शेष क्षेत्रों में 2018 तक बेरियम के उपयोग की अनुमति भी दी गयी।
- ▶ इसके साथ ही, तमिलनाडु और आस-पास के राज्यों को यह तय करने की अनुमति दी गई है कि लोग त्योहार के दिनों में राज्य के अंदर पटाखे कब जला सकते हैं। हालाँकि पटाखे जलाने का समय कुल दो घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। सम्बंधित प्राधिकारी टाइम स्लॉट का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, उदाहरण सुबह में एक घंटा और शाम को एक घंटा।

- इसके अलावा, न्यायालय ने निर्देश दिया कि केवल ग्रीन क्रैकर्स का निर्माण किया जा सकता है और उन्हें बेचा जा सकता है और यह केवल दिल्ली और एनसीआर में लागू होगा।

यह कैसे हुआ?:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा दिए गए विचार के आधार पर सीएसआईआर (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) ने ग्रीन क्रैकर्स की परिकल्पना की। कालांतर में बाद में सीएसआईआर ने इसे बनाने के विचार पर कार्य प्रारम्भ किया।

CSIR में दरार :

इसकी स्थापना 1942 में की गयी थी। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। यह एक स्वायत्त निकाय है और इसने स्वयं को भारत में सब से बड़े शोध संगठन के रूप में साबित किया है। इसके साथ ही, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 'ग्रीन क्रैकर' जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि एक ग्रीन क्रैकर का उद्देश्य शून्य प्रदूषण उत्सर्जित करना है, किन्तु यह पूर्णतः संभव नहीं है।

क्रैकर्स और हरित होना:

ऐसी प्रदूषणकारी सामग्रियां जिनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, यथा एल्यूमीनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन, को क्रैकर्स में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। कुछ ग्रीन क्रैकर्स निम्नलिखित हैं:

➤ **SWAS:** SWAS (सेफ वॉटर रिलीज़र) क्रैकर्स, पोटेशियम नाइट्रेट (KNO₃) और सल्फर का उपयोग निषिद्ध करते हैं तथा SO₂, NO_x और पार्टिकुलेट मैटर में कमी (30-35%) करता है। इसकी आवाज़ लगभग सामान्य पटाखों (क्रैकर्स) के समान ही है और 105-110 dBA की सीमा में है। SWAS अपने निर्माण के अगले तीन हफ्तों तक खराब नहीं होता।

➤ **STAR:** STAR (सेफ थर्माइट क्रैकर), KNO₃ और सल्फर का प्रयोग निषिद्ध करता है तथा SO₂, NO_x एवं पार्टिकुलेट मैटर में कमी (35-40% तक) लाता है। इसकी ध्वनि तीव्रता 105-110 dBA की सीमा में होती है।

➤ **SAFAL:** SAFAL (सेफ मिनिमल एल्युमीनियम), में सामान्य क्रैकर्स की तुलना में पार्टिकुलेट मैटर (35-40%) में महत्वपूर्ण कमी के साथ एल्यूमीनियम (केवल शुरुआत के लिए फ्लैश पाउडर के रूप में) का न्यूनतम उपयोग होता है। इसकी ध्वनि तीव्रता 110-115 dBA है।

भूगोल और पर्यावरण

ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC दृष्टिकोण: अनुभाग जलवायु परिवर्तन के तहत जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3।

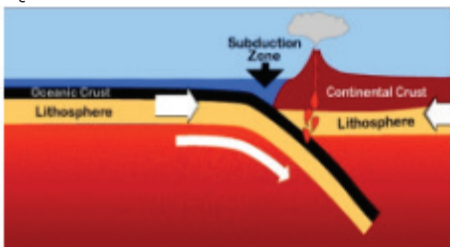
जीवन, जलवायु और महाद्वीप संचलन के बीच सम्बन्ध

लिथोस्फीयर सबसे ऊपर की परत है। इसमें हलचल हो रही है। लिथोस्फीयर के टुकड़े प्लेट हैं। जैसे:



महासागर प्लेट (सागर में (परत + ऊपरी मंडल)) और महाद्वीपीय प्लेट (भूमि क्षेत्र और ऊपरी मंडल)

इन प्लेटों में हलचल हो रही है और इसकी वजह से बड़ी मात्रा में पानी पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।



ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा एक नए अध्ययन ने पृथ्वी और महाद्वीपों की हलचल के बीच एक संभावित सम्बन्ध को दर्शाया है।

➤ खोज बताती है कि अवसाद, जिनमें अक्सर मृत जीवों के टुकड़े शामिल होते हैं, महाद्वीपीय बहाव की गति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

➤ प्लेटों की गति बढ़ाने के लिए अवसाद स्नेहक के रूप में कार्य करते हैं।

➤ यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पृथ्वी पर टेक्टोनिक संचलन, जलवायु और जीवन के बीच संभावित प्रतिक्रिया तंत्र का वर्णन करते हैं।

अर्थ एन्ड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में 15 नवंबर को प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि कैसे टेक्टोनिक प्लेटों के नीचे अन्तः क्षेपित या नीचे जाते अवसाद प्लेटों के संचलन को नियंत्रित कर सकते हैं और पर्वत श्रृंखलाओं और महाद्वीपीय परतों के विकास में तीव्र वृद्धि में भी भूमिका निभा सकते हैं।

अवसाद कैसे बनाया जाता है?

➤ अवसाद का निर्माण तब होता है जब जल, पवन और बर्फ मौजूदा चट्टान को अपरदित कर देते हैं अथवा प्लांकटन जैसे माइक्रोस्कोपिक जीवों के खोल और कंकाल समुद्र तल पर जमा होते हैं।

उपद्रव जोन में प्रवेश करने वाले सेडिमेंट लंबे समय से भूगर्भीय गतिविधि को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है जैसे कि भूकंप की आवृत्ति, लेकिन अब तक इनका प्रभाव महाद्वीपीय पर थोड़ा ही माना जाता था।

➤ ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्तः क्षेपण की गति को अन्तः क्षेपित होने वाली प्लेट की शक्ति पर निर्भर माना जाता था

(जैसे ही यह चिपचिपे मैटल, जोकि पृथ्वी की परत के नीचे चट्टान की अर्द्ध पिघली परत है में जाती है)।

► महाद्वीपीय संचलन एक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे जाने से संचालित होता है तथा इस प्रक्रिया में, प्लेट के जिस हिस्से को पृथ्वी के मैटल में खींचा जा रहा है (और इसे मोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा) उसकी ऊर्जा प्लेट की गति की प्राथमिक नियंत्रक होगी। हालाँकि इसमें अवसाद का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है।

► अवसाद से निर्मित चट्टान प्लेटों के बीच एक स्नेहन प्रभाव उत्पन्न कर सकती है जिससे अन्तःक्षेपण में तेजी और प्लेट की गति में वृद्धि हो सकती है।

► जैसे-जैसे प्लेट वेग बढ़ता है, तलछट जमा करने के लिए कम समय होगा, इसलिए उपद्रव तलछट की मात्रा कम हो जाएगी।

► यह पहाड़ की इमारत को प्रभावित कर सकता

भूगोल और पर्यावरण

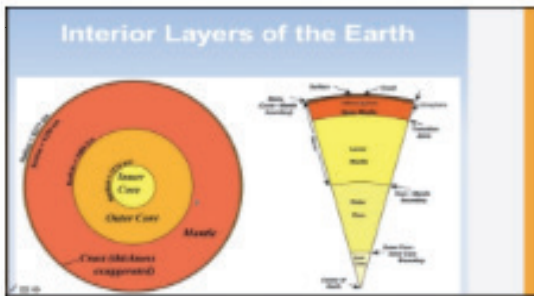
पृथ्वी की आंतरिक भूमिगत पानी खींच रहा है



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)
UPSC के दृष्टिकोण से : जीएस प्रश्नपत्र 1

पृथ्वी के आंतरिक में पानी भारी मात्रा में खींचा गया

- मारियाना ट्रेंच (पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु) से सम्बंधित भूकम्पीय अध्ययन (जोकि अपनी तरह का पहला अध्ययन है) के अनुसार महासागर के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के धीमी गति से टकराने से, अब तक के अनुमानों की तुलना में तीन गुना अधिक जल पृथ्वी के भीतर जाता है।
- इस शोध से पता चलता है कि अन्तः क्षेपण क्षेत्र से अनुमानित मात्रा की तुलना में काफी अधिक मात्रा में जल पृथ्वी के गहन आंतरिक क्षेत्र में- सतह के नीचे मीलों तक, जाता है।
- विश्व की सबसे गहरी गर्त के अध्ययन से प्राप्त प्रेक्षणों के वैश्विक जल चक्र में महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं।



लिथोस्फीयर सबसे ऊपर की परत है।

लिथोस्फीयर के टुकड़े प्लेट कहलाते हैं।

महासागरीय प्लेट (सागर में (क्रस्ट + ऊपरी मैटल)) और महाद्वीपीय प्लेट (भूमि क्षेत्र और ऊपरी मैटल)

इन प्लेटों के अंदर हलचल हो रही है और इसके कारण पृथ्वी के अंदर बड़ी मात्रा में जल प्रवेश कर रहा है।

► प्लेट के ऊपर महासागर का जल भ्रंश रेखाओं के साथ पृथ्वी की क्रस्ट और ऊपरी मैटल में चला जाता है जो उस क्षेत्र में स्थित होती हैं जहां प्लेटें टकराती हैं और झुकती हैं।

► इसके उपरान्त यह जल फंस जाता है। ताप और दाब की कुछ स्थितियों के तहत, रासायनिक क्रियाओं से जल गैर-तरल रूप में हाइड्रस खनिज (गीली चट्टान) के रूप में परिवर्तित होता है और भूगर्भीय प्लेट में चट्टान में लॉक हो जाता है।

► इस दौरान, प्लेट पृथ्वी के मैटल में और गहराई तक धँस जाती है जिससे पानी भी इसके साथ जाता है।

► मारियाना ट्रेंच जैसे अन्तः क्षेपण क्षेत्रों में पिछले अध्ययनों से पता चला है कि अन्तः क्षेपित होने वाली प्लेट में जल एकत्रित हो सकता है। हालाँकि यह निर्धारित नहीं किया जा सका है इसमें कितना जल संचित है और यह कितनी गहराई तक चला गया है।

► अकेले मारियाना ट्रेंच क्षेत्र में, पहले की गणनाओं की तुलना में चार गुना अधिक पानी अन्तः क्षेपित हुआ है। दुनिया भर में अन्य सागरीय गर्तों के नीचे की स्थितियों के पूर्वानुमान के लिए इन लक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है।

► पृथ्वी पर जल के सन्दर्भ में जितना नीचे जाना चाहिए, उतना ही ऊपर भी आना चाहिए। भूगर्भीय समय पर समुद्री स्तर अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, और इनमें 1000 फीट से भी कम का अंतर आया है।

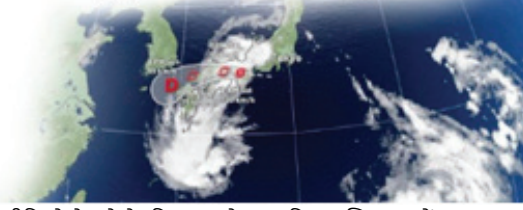
► इसका अर्थ यह है कि अन्तः क्षेपण क्षेत्रों से पृथ्वी पर जाने वाले सभी जल को किसी भी तरह वापस आना चाहिए, और लगातार पृथ्वी के अंदर एकत्रित नहीं होना चाहिए।

► वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्त से नीचे जाने वाला अधिकांश जल सैकड़ों मील दूर ज्वालामुखी विस्फोटों में निकलने वाली जलवाष्प के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आता है।

► लेकिन नए अध्ययन से पानी के संशोधित अनुमानों के साथ यह स्पष्ट हुआ है कि पृथ्वी पर जाने वाले जल की मात्रा वापस आने वाली मात्रा से काफी अधिक है।

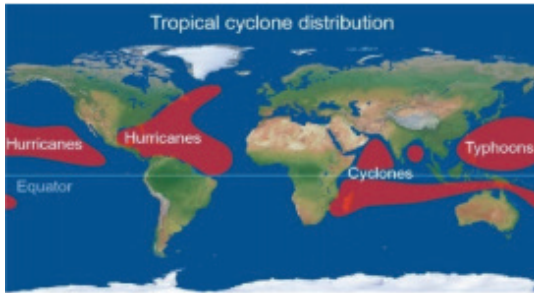
नोट्स

प्रशांत महासागर में आवृत्ति और टाइफून की तीव्रता में वृद्धि



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से: GS प्रश्नपत्र 1 अथवा प्रश्नपत्र 3



ऊष्णकटिबंधी चक्रवात:

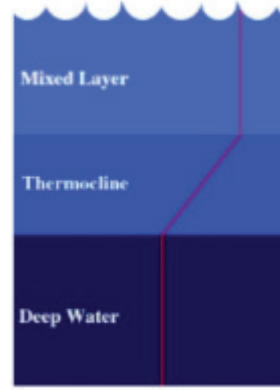
ऊष्णकटिबंध में चक्रवात ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाते हैं। उनकी उत्पत्ति के लिए तापमान का 27 डिग्री या उससे अधिक होना आवश्यक है। हरिकेन, चक्रवात एवं टाइफून सब एक ही चीज हैं।

हरिकेन, चक्रवात एवं टाइफून

- ▶ ये सभी एक जैसे ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं।
- ▶ किन्तु ये सभी अलग अलग स्थानों पर तूफानों के लिए प्रयुक्त अलग अलग शब्द हैं।
- ▶ अटलांटिक, कैरीबियन सागर, मध्य और पूर्वोत्तर प्रशांत में हरिकेन शब्द का उपयोग किया जाता है।
- ▶ लेकिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तूफान के लिए विशिष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं।
- ▶ वे उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून हैं।
- ▶ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, उन्हें चक्रवात कहा जाता है।
- ▶ ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात का उपयोग, दक्षिण पश्चिम हिन्द महासागर में किया जाता है।
- ▶ दक्षिणपश्चिम प्रशांत और दक्षिणीपूर्वी हिन्द महासागर में वे प्रचंड ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं।

संकल्पना

- ▶ सतही परत के ऊपरी हिस्से में मिश्रित परत पायी जाती है, जहाँ सक्रिय वायु-जल की अदला बदली से सतही हलचल पैदा होती है, जिससे पानी के आपस में मिलने से तापमान एवं लवणता में ऊर्ध्वाधर समानता उत्पन्न हो जाती है।
- ▶ समुद्र की सतही परत जोकि मिश्रित परत कहलाती है, औसतन लगभग 200 मीटर (656 फुट) गहरी होती है।
- ▶ यह परत, वायुमंडल के साथ लगातार गैसों की अदलाबदली कर रही होती है और ऐसा पवनों, तापमान परिवर्तन एवं वाष्पन के द्वारा होता है।
- ▶ मिश्रित परत का तापमान 27 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए।
- ▶ मिश्रित परत, चक्रवात उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।



Temperature ----->

अध्ययन

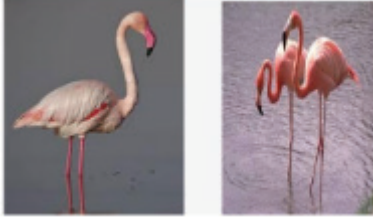
- ▶ अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की एक पत्रिका अर्थ'स फ्यूचर में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार 2002-2015 से सागर मिश्रित परत ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रैक के साथ 1.7-2.0 मीटर गहरी हो गयी है, जबकि अन्य कारकों में थोड़ा ही परिवर्तन हुआ है।
- ▶ इसके निष्कर्षों के अनुसार 1980 से 2015 तक तीव्र टाइफून में वृद्धि के लिए यह गहराई जिम्मेदार हो सकती है। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया है कि तीव्र टाइफून की वृद्धि की दर आने वाले दशकों में पहले से अधिक रहेगी।
- ▶ बढ़ते तापमान के कारण पृथ्वी के महासागरों की ऊपरी परत में परिवर्तनों से प्रशांत महासागर के तीव्र टाइफूनों में वृद्धि हो सकती है। इससे यह सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दशकों में सशक्त टाइफून वैज्ञानिकों के अनुमानों की तुलना में कम अंतरालों से आया करेंगे।
- ▶ 2013 के सुपर टाइफून हैयान जैसे तीव्र टाइफून, उच्च हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत होते हैं, (अक्सर 130 मील प्रति घंटा या अधिक)।
- ▶ टाइफून हैयान अब तक दर्ज सबसे सशक्त ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक था। वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक से प्रशांत महासागर में प्रत्येक सीजन में आने वाले तीव्र टाइफून के अनुपात में वृद्धि देखी है, लेकिन ऐसा क्यों है यह समझ नहीं सके हैं।

नोट्स



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

होप आइलैंड में ग्रेटर फ्लेमिंगोस



25 वर्षों के बाद होप आइलैंड में ग्रेटर फ्लेमिंगोस

- ▶ आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से, होप आइलैंड के तट पर पांच ग्रेटर फ्लेमिंगो का एक झुंड देखा गया है।
- ▶ तटों पर फ्लेमिंगो का दिखाई देना, स्वस्थ तटीय पर्यावरण का संकेत माना जा सकता है।
- ▶ पृथ्वी पर पायी जाने वाली फ्लेमिंगो की छः प्रजातियों में से, ग्रेटर फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो परिवार का सबसे सामान्य और व्यापक तौर पर मिलने वाला सदस्य है।

- ▶ ये प्रसिद्ध गुलाबी पक्षी कई महाद्वीपों पर गर्म एवं पानी वाले क्षेत्रों में पाया जा सकता है और यह एशिया के भारत और पाकिस्तान के तटीय क्षेत्रों, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कैरीबियाई और दक्षिणी यूरोप में पाया जाता है।
- ▶ जब फ्लेमिंगोस एक झुंड के तौर पर होते हैं, तो उन्हें 'कॉलोनी' या 'स्टैंड' कहा जाता है।
- ▶ ग्रेटर फ्लेमिंगोस, लवणीय या क्षारीय झीलों, ज्वारनदमुखों, उथली तटीय लैगून और दलदली स्थानों सहित विभिन्न प्रकार के खारी जल अधिवासों में पाए जाते हैं।
- ▶ ग्रेटर फ्लेमिंगो शायद ही कभी ताजा पानी के क्षेत्रों में निवास करते हैं, वह केवल स्नान और पीने के लिए ताजे पानी के इनलेट्स का उपयोग करते हैं।
- ▶ उष्णकटिबंध के बाहर रहने वाले ग्रेटर फ्लेमिंगोस अक्सर सर्दियों के महीनों में गर्म मौसम के लिए प्रवास करते हैं।

कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (सीडब्ल्यूएस) (1978) के बारे में

- ▶ कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (सीडब्ल्यूएस) एक वन्यजीव अभयारण्य और आंध्र प्रदेश में स्थित ज्वारनदमुख है। इसमें 235.7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है।
- ▶ यह 24 मैंग्रोव पेड़ प्रजातियों और 120 से अधिक पक्षी प्रजातियों के साथ भारत में मैंग्रोव जंगलों का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है।

नोट्स

भूगोल और पर्यावरण

अमेरिकी टूरिस्ट की सेंटिनल द्वीप पर हत्या



(वीडियो देखने के लिए उपरोक्त छवि पर क्लिक करें)

UPSC के दृष्टिकोण से: GS1- अंडमान द्वीपसमूह का भूगोल और GS2- समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित मुद्दा

समाचारों में क्यों?

16 नवंबर को संरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सेंटिनलीज जनजाति ने कथित रूप से एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी थी।

सेंटिनलीज कौन हैं?

सेन्टीनलीज एक नीग्रो जनजाति हैं जो अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं। यहाँ के निवासियों को शारीरिक एवं साथ में भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा से जोड़ा जाता है। उनकी संख्या 150 से कम और कई बार तो केवल 40 तक ही मानी जाती है।

जनजातियां कैसे संरक्षित हैं?

सरकार भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 में जनजातियों द्वारा अधिवासित पारंपरिक क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया था। इसमें प्राधिकारियों के अलावा सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। जनजाति सदस्यों की फोटोग्राफी या फिल्मांकन करना भी एक अपराध है। बाद में दंड बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया था।

लेकिन हाल ही में कुछ द्वीपों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट में कुछ ढील दी गयी थी। इस साल की शुरुआत में एक बड़े कदम में, भारत सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट या आरएपी शासन से केंद्र शासित प्रदेश इस द्वीप और 28 अन्य द्वीपों को हटा दिया था। आरएपी को हटाने का मतलब है कि विदेशी लोग सरकार से अनुमति के बिना द्वीप पर जा सकते हैं।

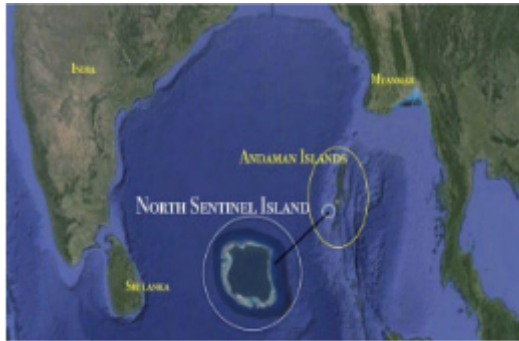
प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) शासन क्या है?

- ▶ आरएपी शासन विदेशियों (प्रतिबंधित क्षेत्रों) आदेश, 1963 के तहत अधिसूचित किया गया था।
- ▶ इसके तहत, विदेशी नागरिकों को आम तौर पर संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि सरकार संतुष्ट न हो कि उनकी यात्रा को न्यायोचित ठहराने के असाधारण कारण मौजूद हैं।
- ▶ भूटान के नागरिकों के अलावा हर विदेशी, जो संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना और रहना चाहता है,

उसे ऐसे सक्षम प्राधिकारी से विशेष परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिसे विदेशी को ऐसे परमिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है।

► अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के नागरिक और पाकिस्तानी मूल के विदेशी नागरिक अपवाद हैं और उन्हें इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

प्रारंभिक परीक्षा बिंदु : अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में:



- अंडमान और निकोबार द्वीप (ए और एन द्वीप), जिन्हें 'खाड़ी या Bay द्वीप' के नाम से जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी में, उत्तर-दक्षिण दिशा में एक टूटे हुए हार की तरह फैले हुए प्रायद्वीपीय भारत और म्यांमार के बीच मध्यमार्ग में स्थित हैं।
- ए और एन द्वीपों का कुल भौगोलिक क्षेत्र 8249 वर्ग किमी है, जिसमें से अंडमान द्वीप समूह का 6408 वर्ग किमी है जबकि निकोबार द्वीप समूह 1841 वर्ग किमी कवर करता है।
- नारकॉन्डम और बैरेन द्वीप, दो द्वीप पाए गए हैं जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई थी। पहला वाला अब विलुप्त या मृत हो चुका है जबकि बाद वाला अभी भी सक्रिय है।
- अंडमान और निकोबार, टेन डिग्री चैनल से अलग होते हैं, जो कि 150 किमी में विस्तृत है।
- द्वीपों की जनसंख्या लगभग 4 लाख है, जिसमें छह विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं।
- अंडमान के मूलनिवासी लोग महान अंडमानी, जारवा, ओंगे और सेंटिनेलिज़ हैं (सबसे ज्यादा पृथक समूह)।

नोट्स

स्पाइस ऑफ़ दा मंथ

स्पाइस ऑफ़ दा वीक श्रृंखला के बारे में

- ▶ "स्पाइस" श्रृंखला एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य लोक सेवाओं और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए उत्तर और निबंध लेखन में सुधार करना है।
- ▶ तैयारी करते समय, उम्मीदवार अधिकतर समय स्टैटिक किताबों और करेंट अफेयर्स से सम्बंधित पत्रिकाओं को पढ़ने और रीवाइज़ करने में बिताते हैं लेकिन वास्तविक परीक्षा परिदृश्य में अपने उत्तरों को कैसे समृद्ध बनाया जाय इस तरीके में चूक जाते हैं।
- ▶ उदाहरण: एक अच्छी तरह से लिखे गए और उच्च अंक देने वाले उत्तर में कुछ सहायक उदाहरण या प्रासंगिक आँकड़े / उद्धरण, परिचय देने के लिए एक उचित परिभाषा या निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ बड़े विचार शामिल हैं।
- ▶ यहां तक कि निबंध लेखन में भी, कई छात्र अच्छे उदाहरण, उद्धरण, आँकड़े इत्यादि का एक समर्पित भंडार तैयार नहीं करते हैं - जबकि ये उनके निबंध को समृद्ध और पठनीय बना सकते हैं।
- ▶ इस साप्ताहिक श्रृंखला में, हम ऐसी सामग्री (जिसे 'स्पाइस' कहा जाता है) को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं जिसका उपयोग सीधे आप के उत्तरों और निबंध में किया जा सकता है।
- ▶ हमारा मानना है कि यदि इस सामग्री का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाए तो यह आपके उत्तरों को प्रति प्रश्न कम से कम 1 से 2 अंक अधिक दे सकता है - जो कि टॉपर को बाकी उम्मीदवारों से अलग करने के लिए आवश्यक है।

आखिर में महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रयास में तब सफल होंगे जब प्रत्येक गंभीर उम्मीदवार अपने दैनिक अध्ययन में 'स्पाइस' को पहचान सकें तथा उत्तर/निबंध में इसका प्रयोग कर अधिकतम अंक अर्जित कर सकें।

डिस्क्लेमर: स्पाइस आपकी मौजूदा तैयारी में एक ऐड-ऑन है। यह स्थैतिक किताबों और / या करेंट अफेयर्स की तैयारी का प्रतिस्थापन नहीं है।

इस महीने की परिभाषाएं

▶ वित्तीय समावेशन	▶ वित्तीय समावेशन मुख्यधारा संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एक किफायती लागत पर कमजोर समूहों द्वारा आवश्यक उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। (आरबीआई)
▶ समावेशी विकास	▶ आर्थिक विकास जो समाज भर में कायदे से वितरित किया जाता है और सभी के लिए अवसर पैदा करता है। (ओईसीडी)
▶ स्वयं सहायता समूह	▶ स्वयं सहायता समूह(SHG) एक छोटा स्वैच्छिक समूह (15-20 सदस्य) है जो उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो अधिमानत एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं ताकि अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत और क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए।
▶ ग्लोबल वॉर्मिंग	GHGs की सांद्रता में वृद्धि, जो ग्रीनहाउस प्रभाव में वृद्धि करती है, के कारण पृथ्वी की औसत ग्लोबल वॉर्मिंग में वृद्धि हुई है। ▶ पिछले 100 वर्षों के दौरान, वैश्विक माध्य तापमान 0.3-0.60 सेल्सियस बढ़ गया है। ▶ 2016 में, नासा ने घोषणा की कि 2001 से, पृथ्वी में 17 वर्षों में से 16 वर्ष गर्म देखे गए हैं। ▶ पिछले 50 वर्षों में वॉर्मिंग की दर पिछले 100 वर्षों में देखी गई दर से दोगुनी थी

इस महीने के उदाहरण

राज्यव्यवस्था:

<p>► प्रणालीगत विफलता</p> <p>► न्याय में देरी</p> <p>► न्यायिक लंबितता</p>	<p>► मेरठ के निकट हाशिमपुरा नरसंहार के 31 साल बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ट्रायल कोर्ट द्वारा 38 मुसलमानों की हत्या में 16 पुलिस वालों को निर्दोष ठहराये जाने के आदेश को उलट दिया और उन्हें उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसने कहा "यह मामला प्रणालीगत विफलता को इंगित करता है जो सदैव न्याय की विफलता है का कारण बनती है।"</p>
<p>► संघवाद</p>	<p>► राज्यों द्वारा 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रदत्त रक्षोपायों से बचने के लिए अनुच्छेद 254(2) का उपयोग कर रहे हैं। इन रक्षोपायों में सहमति का अधिकार, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और तमिलनाडु के मामले में, पुनर्वास और पुनर्स्थापन शामिल हैं।</p> <p>► अनुच्छेद 254 संसद द्वारा निर्मित कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्मित कानूनों के बीच असंगतता के बारे में है। हालाँकि इसका उद्देश्य कभी भी केन्द्रीय कानूनों के असुविधाजनक होने पर उन्हें कमजोर करने का नहीं था।</p>
<p>► राजनीतिक असहिष्णुता</p> <p>► अनुच्छेद 19</p>	<p>► तमिलनाडु में AIADMK ने तमिल फिल्म सरकार के निर्माताओं को एक दृश्य काटने और कुछ संवाद मौन करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि वे सरकारी नीति की आलोचना करते हैं अथवा उनकी संवेदनशीलताओं को अपमानित करते हैं। AIADMK समर्थकों ने सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की, उन्होंने फिल्म की जांच की, और साथ ही, राज्य के मंत्रियों ने निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की।</p>
<p>► न्यायिक सक्रियता</p>	<p>► न्यायिक सक्रियता को रोकने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण:</p> <p>► राम जवाया बनाम पंजाब राज्य (1955) में, न्यायालय ने कहा: "हमारा संविधान राज्य के एक अंग या हिस्से द्वारा उन कार्यों की धारणा पर विचार नहीं करता है, जो अनिवार्य रूप से दूसरे से सम्बंधित हैं।"</p> <p>► भारत संघ बनाम देवकी नंदन अग्रवाल (1 99 1), "कानून बनाने की शक्ति न्यायालय को नहीं दी गई है।" सुरेश सेठ बनाम आयुक्त, इंदौर नगर निगम (2005) में, न्यायालय ने कहा: "हमारी संवैधानिक योजना के तहत, संसद और विधान सभाएं कानून लागू करने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती हैं।"</p> <p>► न्यायिक सक्रियता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले</p> <p>► अरुण गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2017) में, उच्चतम न्यायालय ने दीवाली आतिशबाजी के लिए समय निश्चित कर और गैर हरित आतिशबाजी को प्रतिबंधित कर दिया, हालांकि इस सम्बंधित कोई कानून नहीं है।</p> <p>► एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2018) में, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि 30 मार्च, 2020 के बाद कोई भी बीएस -4 वाहन नहीं बेचा जाना चाहिए, और उसके बाद केवल बीएस -6 वाहन बेचे जा सकते हैं। सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) में, अदालत ने धारा 18 को रद्द कर के अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाती अत्याचार अधिनियम, 1 9 8 9 में संशोधन किया, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्तियों को कोई अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। संशोधन के अनुसार प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होगी; और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लिखित अनुमति के बिना अधिनियम के तहत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।</p> <p>► एनजीटी ने आदेश दिया कि कोई भी 15 वर्षीय पेट्रोल संचालित या 10 वर्षीय डीजल संचालित वाहन दिल्ली में नहीं होगा, और उच्चतम न्यायालय ने ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है, हालांकि न तो एनजीटी और न ही उच्चतम न्यायालय विधायी निकाय हैं।</p> <p>► पूर्व उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू = > "यदि न्यायाधीश अपने मर्जी के कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, तो यह न केवल शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ होगा, बल्कि यह कानून में अनिश्चितता और अराजकता भी पैदा कर सकता है क्योंकि फिर हर न्यायाधीश अपने विचारों और रुचियों के अनुसार कानून बनाना करना शुरू कर देगा "</p>
<p>► जनोन्मुखी शासन</p>	<p>► राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यह सिफारिश करने की योजना बना रहा है कि "भारतीय वन सेवा" अपना नाम बदलकर "भारतीय वन और जनजातीय सेवा" कर दे।</p> <p>► इसके अनुसार यह अनिवार्य है क्योंकि वन सेवा नियमित रूप से वन में निवास करने वाली इन जनजातियों के साथ अंतर्क्रिया करती है और इसलिए, वनों और इन समुदायों दोनों के हितों पर विचार करने की आवश्यकता है।</p>
<p>► भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण</p>	<p>तेलंगाना ने 'भूधार' शुरू किया है। यह 11 अंकों का एक अद्वितीय नंबर है जिसका लक्ष्य भूखण्डों के विवरण की आसान पहचान को सक्षम करना है। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है।</p>

समाज और मानव विकास:

<p>► सामाजिक-सांस्कृतिक ध्रुवीकरण</p> <p>► विरोधी सांस्कृतिक वैश्वीकरण</p>	<p>► एक बंदूकधारक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग सभास्थल में यहूदियों पर एक घातक हमला कर 11 उपासकों की हत्या कर दी। इस घटना से अमेरिकी यहूदी समुदाय शोक में है। पिट्सबर्ग सीनागॉग बन्दधारी ने कहा कि वह चाहता है कि सभी यहूदियों की मृत्यु हो जाये।</p>
<p>► समय के साथ धर्म बदलना</p>	<p>► कैथोलिक बिशपों की एक बड़ी बैठक इस निर्णय के साथ समाप्त हुई कि चर्च के निर्णय निर्माण में महिलाओं को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। पोप फ्रांसिस ने युवाओं से कहा कि उन्हें "सैद्धांतिक सूत्रों" से अतिप्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए सामाजिक सक्रियता के साथ अपने नियमों को मिश्रित करना चाहिए।</p>
<p>► महिला सशक्तिकरण</p>	<p>► कुडुम्बश्री (1 99 7) केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन (एसपीईएम) द्वारा लागू गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।</p> <p>► कोझिकोड में कुडुम्बश्री महिला मॉल देश का पहला मॉल है जिसमें सभी महिला सदस्य हैं। इसमें लगभग 75 महिला उद्यमियों या समूहों द्वारा संचालित व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जिनमें कुडुम्बश्री वर्ग शामिल हैं।</p> <p>► लिथुआनिया की राजधानी विलीयस ने इस बाल्टिक राज्य में महिलाओं को मतदान अधिकार प्राप्त होने की 100 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए महिला प्रतीकों वाली ट्रैफिक लाइट्स स्थापित की हैं।</p> <p>► महिलाओं को मतदान करने का अधिकार लिथुआनियाई संविधान में 2 नवंबर, 1 9 18 को दिया गया था। इसे सबसे पहले, फ्रांस और अमेरिका से भी पहले, महिला मताधिकार करने वाले देशों में रखा जाता है।</p>
<p>► महिला सुरक्षा</p>	<p>► एमएचए ने निर्भया फंड के तहत 8 शहरों में सेफ सिटी परियोजनाओं की योजना बनाई है। लखनऊ इस परियोजना के लिए चुना गया पहला शहर है, जिसमें शामिल है:</p> <p>► इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल कक्ष</p> <p>► विशेष रूप से महिला पुलिस द्वारा प्रशासित पैंक पुलिस स्टेशन</p> <p>► पुलिस महिला द्वारा पैंक पैट्रोल</p> <p>► पैंक टॉयलेट स्थापित करना</p> <p>► काउंसलर के साथ सभी पुलिस स्टेशनों में वुमन हेल्प डेस्क</p> <p>► कैमरों सहित बसों में सुरक्षा उपाय</p> <p>► कुछ चुने हुए क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग</p> <p>► लिंग संवेदनशीलता और जागरूकता अभियान</p>
<p>► यौन उत्पीड़न</p>	<p>► उच्चतम न्यायालय द्वारा 1997 में जारी विशाखा दिशानिर्देशों को एक संसदीय कानून के रूप में विकसित किया गया जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के नाम से जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय इसे आश्रम, मदरस और कैथोलिक संस्थानों तक विस्तृत करने से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।</p>
<p>► बाल श्रम</p>	<p>► नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने झारखंड में माइका खनन से बाल श्रम को खत्म करने और हितधारकों के "चैपियंस-इन-चेंज" बनने की आवश्यकता पर बल दिया।</p>
<p>► स्वच्छ भारत</p>	<p>► स्वच्छ न्यायालय की परियोजना को स्वच्छ न्यायालय बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें से सही है 3,388 निचली अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।</p>
<p>► जल तक पहुंच</p>	<p>► चूंकि 82 करोड़ लोगों के पास अभी भी पाइपलाइन से जल आपूर्ति की सुविधा नहीं है, अतः सरकार वैकल्पिक समाधान के रूप में - छोटे एटीएम और सामुदायिक शोधन संयंत्र जैसे छोटे जल उद्यमों को स्वीकार करना प्रारम्भ कर रही है।</p> <p>► जल एटीएम स्वचालित जल वितरण इकाइयां हैं, जो समुदायों को 24/7 सुरक्षित जल पहुंच प्रदान करते हैं। वे सौर संचालित और क्लाउड जुड़े हुए हैं, इस प्रकार पानी की गुणवत्ता और प्रत्येक भुगतान प्रति उपयोग लेनदेन की रिमोट ट्रैकिंग सक्षम करते हैं।</p>
<p>► दवाई का दुरुपयोग</p>	<p>► मणिपुर में ड्रग का उपयोग बढ़ रहा है और युवा, ज्यादातर किशोर युवा, इसका शिकार हो रहे हैं। मणिपुर लंबे समय से भारत और म्यांमार के बीच ड्रग परिवहन के लिए एक पारगमन गलियारा रहा है।</p>
<p>► शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार</p>	<p>► श्रवण वृद्धि कार्यक्रम (listening enhancement program) के एक हिस्से के रूप में, करीमनगर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है जहां छात्र अखिल भारतीय रेडियो पर अंग्रेजी समाचार सुनते हैं। इसके बाद उनकी शब्दावली, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स पर उनकी समझ की जाँच के लिए परिचर्चा की जाती है।</p>

► महिलाओं के अधिकार	► पश्चिम गोदावरी में टोकलापल्ली गांव के बुजुर्गों ने महिलाओं को दिन में नाइटी पहनने से प्रतिबंधित कर दिया। ऐसा एक दिन महिलाओं के नाइटी पहन कर बाहर निकलने पर, उन पर अपमानजनक टिप्पणियां किये जाने की घटना पर किया गया। इसका उल्लंघन करने पर महिला को 2000 का जुर्माना देना पड़ेगा।
► एसएचजी को बढ़ावा देना	► ओडिशा सरकार अपने मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत 6 लाख महिलाओं (एसएचजी) को मुफ्त स्मार्टफोन देगी।
► महिला सशक्तिकरण ► महिला सुरक्षा	► अपने "महिला सशक्तिकरण" अभियान के हिस्से के रूप में, केरल सरकार पूरे राज्य में "शी लॉज" या केवल महिलाओं के छात्रावास स्थापित कर रही है। इसका प्रबंधन और रखरखाव कुडुम्बश्री द्वारा किया जायेगा, जोकि 2.77 लाख महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है। पहला शी लॉज त्रिशूर में है।
► मानसिक स्वास्थ्य	► 23 स्वर्ण पदक जीतने और 39 विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने से अपने जीवन को समाप्त करने की सशक्त इच्छा से जूझने तक, ओलंपिक चैंपियन माइकल फेलप्स ने एक लंबा सफर तय किया है। 33 वर्षीय तैराक अब मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन के उभरे हैं।
► पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना	► संस्कृति मंत्रालय का वैदिक विरासत पोर्टल वेदों और विज्ञान से सम्बंधित 'वन-स्टॉप समाधान' होगा। उसमें "शुद्ध वैज्ञानिक जानकारी", मौखिक परम्पराओं, पांडुलिपियों और प्रकाशनों के ऑडियो-विजुअल दस्तावेज और यज्ञ से सम्बंधित "साधन / उपकरण / सामग्री" इत्यादि शामिल होंगे।
► शिक्षा पर मौसमी प्रवासन का प्रभाव	► यूनेस्को वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के ग्रामीण परिवारों में साक्षरता का स्तर मौसमी प्रवासन के साथ कम होता जाता है। ► सात शहरों में कार्यस्थलों के पास लगभग 80% मौसमी प्रवासी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच नहीं है, और 40% शिक्षा की बजाय काम करने लगते हैं जहाँ उनके साथ शोषण और दुर्व्यवहार होता है। ► अंतर-राज्य प्रवासी दर 2001 और 2011 के बीच दोगुनी हो गयी है। अनुमानित 9 मिलियन प्रवासियों ने राज्यों के बीच साल 2011 से 2016 तक प्रवास किया। समाधान- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने स्थानीय अधिकारियों के लिए प्रवासी बच्चों का प्रवेश लेना अनिवार्य कर दिया।
► महिलाओं का, महिलाओं द्वारा, ► महिलाओं के लिए	► असम के बेयरफुट कॉउंसिलर्स जमीनी स्तर के परामर्शदाता हैं जिनका कार्य परेशान महिलाओं को भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना है।
► स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी	► एम्बुलेंस की अपर्याप्तता की समस्या का समाधान करने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप-आधारित सेवा की घोषणा की है जो जनता को प्राइवेट एम्बुलेंस डिजिटल रूप से बुक करने में सक्षम बनाता है। सरकार निजी एम्बुलेंस की डिजिटल पूलिंग को, अपने मौजूदा बेड़े का पूरक बनाने की योजना बना रही है।
► आदिवासी स्वास्थ्य ► संक्रमण में स्वास्थ्य	सहायक आंकड़े: ► जनजातीय समुदायों को बीमारी के "तिगुने बोझ" का सामना करना पड़ता है: ► कुपोषण और संक्रमणीय बीमारियों की उच्च दर (टीबी, कुष्ठ रोग, एचआईवी आदि) ► गैर-संक्रमणीय बीमारियों में वृद्धि (कैंसर, मधुमेह, और उच्च रक्तचाप) ► मानसिक बीमारी और उसके बाद नशे की लत ► सहायक आंकड़े: 42% जनजातीय बच्चे कम वजन वाले हैं (गैर-जनजातीय बच्चों की तुलना में 1.5 गुना अधिक) जनजातीय समुदाय जनसंख्या के 8.6% हैं लेकिन इनमें मलेरिया के मामले 30% हैं। वास्तव में, मलेरिया से संबंधित सभी मौतों में 50% जनजातीय समुदायों के व्यक्तियों की हैं। 25% आदिवासी वयस्क उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं।

अर्थव्यवस्था:

► सार्वभौमिक मूल आय	► केन्या के गांवों में, एक चैरिटी संगठन (गिव डायरेक्टली) ~ 22 डॉलर का मासिक दान देकर यूबीआई की प्रभावशीलता का परीक्षण कर रहा है। यह छह अफ्रीकी देशों में काम कर रहा है। यह सीधे गरीबों को पैसे भेजता है, जिससे वे अपनी प्राथमिकताओं को चुन सकते हैं। ► विश्व बैंक के अनुसार, केन्या के लगभग 50 मिलियन नागरिकों में से एक तिहाई से अधिक लोग 1.90 डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
---------------------	--

►सार्वजनिक नीति के लिए व्यवहार का अध्ययन	► GST अधिकारी कुछ करदाताओं के व्यवहार पैटर्न का अध्ययन कर उन्हें कानूनों का अनुपालन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यह केवल चोरी की जांच के लिए निवारक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने की वर्तमान पद्धति से विचलन को दर्शाता है। (रिचर्ड थालर के बारे में भी पढ़ें)
►प्रवास	► ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में संपन्न पहला, अंतर सरकारी वार्ता समझौता है जो प्रवासन के सभी आयामों को समग्र और व्यापक तरीके से कवर करता है।
►डिजिटल टैक्स	► ब्रिटेन 2020 से बड़ी तकनीकी फर्मों पर "डिजिटल सेवा कर" आरोपित करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लाभ (जो कृत्रिम रूप से कम किया जा सकता है) के बजाय राजस्व (जिसे छिपाना अपेक्षाकृत कठिन है) पर ध्यान केंद्रित करता है।
►MSMEs	► सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो इकाइयों को केवल 59 मिनट में ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और 2% की ब्याज सहायता प्रदान करता है। ► अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपनी कुल खरीद के 20% की बजाय इसका 25% अनिवार्य रूप से MSME से खरीदने के लिए कहा गया है। ► इस 25% खरीद में से 3% अब महिला उद्यमियों से खरीदा जाना चाहिए।
►किसानों के लिए प्रौद्योगिकी	► टी रिसर्च एसोसिएशन (टीआरए) द्वारा इस उद्योग को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार करने तथा चाय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सेंसर आधारित मशीनरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित फ्रंट लाइन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की योजना बनायी जा रही है। ► धान के टूट की समस्या ने हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी अभिनव मशीनों को जन्म दिया है जो धान के टूट होने के बावजूद गेहूं बोने में सहायक होती हैं।
►धोखाधड़ी रोकना	► भारतीय रिजर्व बैंक ने एक डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (PCR) की स्थापना हेतु कदम उठाए हैं। ► इसका उद्देश्य वित्तीय अपराधों की रोकथाम हेतु विलफुल डिफॉल्टर्स समेत सभी उधारकर्ताओं और लंबित कानूनी मामलों के विवरण एकत्र करना है।
►संवृद्धि बनाम स्थिरता	► आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आरबीआई किसी कार में सीट बेल्ट की तरह था, जिसके बिना दुर्घटनाएं हो सकती थीं। ऐतिहासिक रूप से, आरबीआई और सरकार के बीच का रिश्ता ऐसा ही रहा है। सरकार विकास में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है और यह आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ऐसा कर सकती है जो वित्तीय स्थिरता पर आधारित है।
►जलमार्ग	► विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जलमार्ग विकास परियोजना का लक्ष्य 2023 तक वाराणसी से हल्दिया तक NW 1 पर नौवहन को अपग्रेड करना है। तीन मल्टीमोडाल टर्मिनल विकसित किए जाएंगे - वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया। ► नार्थ ईस्ट माइलस्टोन -> ► एनटीपीसी के कहलगांव संयंत्र से गुवाहाटी के पांडु इनलैंड पोर्ट तक पहुँचाया गया फ्लाई ऐश, भारत में जलमार्ग क्षेत्र के संचलन में सबसे लम्बी दूरी की माल ढुलाई में से एक को चिह्नित करता है। सरकार ने इसे "3 जलमार्गों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण एकीकृत संचलन कहा है। ये तीन जलमार्ग हैं- गंगा पर NW 1, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग और ब्रह्मपुत्र पर NW 2
►सार्वजनिक निजी साझेदारी	► वर्तमान में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलूर, हैदराबाद और कोचीन में हवाई अड्डे पीपीपी मॉडल के तहत प्रबंधित किए जाते हैं। पीपीपी मॉड ने विश्व स्तरीय हवाईअड्डे बनाने में मदद की है तथा साथ ही ► AAI को उसके राजस्व को बढ़ाने में भी मदद कर रही है। मंत्रिमंडल ने पीपीपी के तहत अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरू - छह गैर-मेट्रो हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए "सैद्धांतिक रूप में" अनुमोदन दिया है।
►डेटा संचालित नीति ►प्रतिस्पर्धी संघवाद ►कृषि सुधार	► केंद्र सरकार द्वारा इज़ ऑफ़ इडिंग एग्री-बिजनेस के आकलन हेतु एक नए सूचकांक के आधार पर उच्च-निष्पादन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसकी अंक-प्रणाली में विपणन सुधार (25%) तथा भूमि सुधार (20%) का भारांक आधे से अधिक है। ► नीति आयोग पहले से ही एक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एन्ड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स जारी कर रहा है। यह ऐसे सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों को रेटिंग देता है। 2016 में इस सूचकांक के प्रारंभिक संस्करण में, महाराष्ट्र रैंकिंग में पहले स्थान पर और गुजरात दूसरे स्थान पर रहा।

<ul style="list-style-type: none"> ► मेक इन इंडिया ► संतुलित क्षेत्रीय विकास KBK क्षेत्र 	<ul style="list-style-type: none"> ► ओडिशा सरकार ने रक्षा निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए एक रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण नीति (2018) का निर्माण किया है। ► ओडिशा बड़े पैमाने पर एल्यूमीनियम और इस्पात उत्पादन, गहरे समुद्री बंदरगाह, मिसाइल परीक्षण सुविधा (आईटीआर बालासोर) और श्रेणीबद्ध अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों जैसे तुलनात्मक फायदे प्रदान करता है।
<ul style="list-style-type: none"> ► डिजिटल एकाधिकार ► अच्छी तरह से विनियमित पूंजीवाद की आवश्यकता है ► पूंजीपतियों से पूंजीवाद को बचाना ► डिजिटल मुद्राएं 	<ul style="list-style-type: none"> ► Google, खोजों में 92% बाजार हिस्सा रखता है और फेसबुक सोशल नेटवर्क का लगभग 70% हिस्सा रखता है। दोनों का बिना किसी विश्वसनीय प्रतिस्पर्धा / विनियमन के विज्ञापनों पर द्विआधिकार (duopoly) है। ► इस बीच, अमेज़ॅन खुदरा विक्रेताओं को कुचल रहा है और प्रमुख ई-कॉमर्स विक्रेता और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के लिए अग्रणी ऑनलाइन मंच दोनों के रूप में हितों के संघर्ष का सामना कर रहा है। ► ऐप्पल का आईफोन और Google का एंड्रॉइड पूरी तरह से मोबाइल ऐप मार्केट को नियंत्रित करता है, और वे यह निर्धारित करते हैं कि व्यवसाय अपने ग्राहकों तक पहुंच सकता है या नहीं और यदि हाँ तो किन शर्तों पर।
<ul style="list-style-type: none"> ► डिजिटल एकाधिकार ► अच्छी तरह से विनियमित पूंजीवाद की आवश्यकता है ► पूंजीपतियों से पूंजीवाद को बचाना ► डिजिटल मुद्राएं 	<ul style="list-style-type: none"> ► IMF प्रमुख क्रिस्टियन लैगार्ड के अनुसार केंद्रीय बैंकों को "नकद में गिरावट से उत्पन्न शून्य को भरने" के लिए डिजिटल मुद्रा जारी करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ केंद्रीय बैंक यथा - स्वीडन का रिक्सबैंक, बैंक ऑफ कनाडा और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना आदि - जनता को डिजिटल मुद्रा जारी करने पर विचार कर रहे हैं।
<ul style="list-style-type: none"> ► उद्यमिता ► स्टार्ट-अप 	<ul style="list-style-type: none"> ► हिमाचल प्रदेश ने युवाओं को नौकरी तलाशने वालों से नौकरी प्रदाताओं में बदलने के उद्देश्य से "स्टार्टअप यात्रा" का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के तहत उद्यमशीलता विकसित करने के लिए युवाओं को सभी संभव सहायता प्रदान करेगी।
<ul style="list-style-type: none"> ► किसानों के लिए प्रौद्योगिकी 	<ul style="list-style-type: none"> ► सौर बबल ड्रायर (एसबीडी) एक कम लागत वाली अनाज सुखाने वाली तकनीक है। इसका उद्देश्य अनाज पर चलने वाले स्पिल्ज, जानवरों, मौसम और वाहनों से रक्षा करते हुए धूप में सुखाने का एक सरल और लचीला विकल्प प्रदान करना है। ► पारंपरिक धूप में सुखाने की विधि में, कटाई और पिसाई के बीच मात्रात्मक हानि 15 से 30% की सीमा में होने का अनुमान है। गुणवत्ता की हानि के कारण, किसान को उनके उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिलती है।
<ul style="list-style-type: none"> ► उद्योग को बढ़ावा दें ► क्षेत्रीय विकास 	<ul style="list-style-type: none"> ► सरकार ने सभी अनाज के लिए जूट पैकेजिंग अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत में जूट क्षेत्र लगभग 3.7 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है।
<ul style="list-style-type: none"> ► चीन का उदय ► डिजिटल संरक्षणवाद 	<ul style="list-style-type: none"> ► 2000 में, बिल क्लिंटन ने कहा, "इंटरनेट अनिवार्य रूप से चीन को लोकतंत्र की तरफ धकेल देगा। कोई भी देश ऐसे मुक्त प्रवाह को कैसे नियंत्रित कर सकता है और ऐसा करके भी तकनीकी रूप से जीवंत होने की उम्मीद कर सकता है?" वह गलत थे। ► आज, चीन में दुनिया की एकमात्र ऐसी इंटरनेट कंपनियां हैं जो अमेरिका की महत्वाकांक्षा और पहुंच के बराबर हो सकती हैं - टेंसेंट, बायडू, अलीबाबा। ► यदि पश्चिम में लोगों ने यह नहीं देखा, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने चीन के प्राधिकार को प्रौद्योगिकी के प्रति शत्रुता समझा।
<ul style="list-style-type: none"> ► डेटा संप्रभुता 	<ul style="list-style-type: none"> ► डेटा स्थानीयकरण के लिए राष्ट्रों के नागरिकों या निवासियों के डेटा को देश के भीतर एकत्रित, संसाधित और / या संप्रहीत करने की आवश्यकता होती है। ► अप्रैल में, RBI ने भारत के भीतर भारतीय ग्राहकों के लेनदेन डेटा को स्टोर करने के लिए वैश्विक भुगतान फर्मों को 6 महीने दिए थे।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, प्रतिरक्षा और सुरक्षा

► भारत-पाकिस्तान-चीन	► भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच एक प्रस्तावित लकजरी बस सेवा का विरोध किया है जो पीओके और गिलगिट-बाल्टिस्तान के कुछ हिस्सों से गुजरेगी। भारत ने इसे "भारत की संप्रभुता का उल्लंघन" कहा है।
► सॉफ्ट पॉवर	► सत्यजीत रे की महान कृति, पाथर पांचाली को बीबीसी की 100 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। यह इसमें शामिल होने वाली भारत की एकमात्र फिल्म है।
► आंतरिक सुरक्षा खतरे	► उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने हाल ही में कहा था कि पंजाब में "विद्रोह को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं"। उन्होंने यह हाल ही में "रेफेरेंडम 2020" के लिए लंदन में आयोजित एक खालिस्तान रैली के सन्दर्भ में कहा। ► सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा आयोजित 'रेफेरेंडम 2020' रैली, का उद्देश्य यह समझना है कि कम से कम 20 देशों में रह रहे पंजाबियों को क्या अलग राज्य चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें चाहिए, तो वे 2020 में एक जनमत संग्रह करेंगे।
► डायस्पोरा	► अमेरिका के मध्यवर्ती चुनावों के लिए लगभग 100 भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति लड़ रहे हैं। वर्तमान में सभी की नज़रें तथाकथित "समोसा कॉकस" पर हैं। यह वर्तमान कांग्रेस में 5 भारतीय-अमेरिकी का अनौपचारिक समूह है।
► कठोर शक्ति ► आत्मरक्षा	► भारत ने घोषणा की है कि स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने अपना पहला प्रतिरोध गश्त आयोजित करके एक मील का पत्थर हासिल किया है तथा इसके उपरांत इसके परमाणु सिद्धांत में उल्लिखित परमाणु त्रयी संचालित हो गयी है।
► एकध्रुवीय बनाम बहु-ध्रुवीय दुनिया का विचार ► डॉलर का प्रभुत्व	► भारत ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से अस्थायी छूट प्राप्त करने वाले आठ देशों में से एक है। अमेरिका के "ईरान डील" से बाहर निकलने पर 20 से अधिक देशों ने ईरानी कूड के आयात में कमी कर दी है। यूरोपीय संघ, जो इस डील में रहा है, ईरान के साथ यूरोपीय व्यापार की गतिविधियों को दबाने के अमेरिकी प्रयासों से निराश है।
► फेक न्यूज़	► बीबीसी शोध के मुताबिक, भारत में राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर सामान्य नागरिकों को फेक न्यूज़ फैलाने के लिए प्रेरित कर रही है। यह भी पाया गया कि राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की भावनात्मक इच्छा की तुलना में तथ्यों को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा, वामपंथी नेटवर्क की तुलना में दक्षिणपंथी नेटवर्क अधिक संगठित हैं, तथा राष्ट्रवादी नकली कहानियों को और आगे बढ़ाते हैं। ► ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे ने कहा कि सोशल मीडिया पर "फेक न्यूज़" और "गलत जानकारी" की समस्या से निपटने के लिए कोई सही समाधान नहीं था। उन्होंने इस समस्या को सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि यहां तक कि सबसे अच्छा ताला तोड़ा जा सकता है और चुनौती यह है बेहतर ताले बनाते रहा जाए।
► साइबर सुरक्षा	► फ्रांस ने एक वैश्विक साइबर हथियार समझौते की शुरुआत की है - लेकिन अमेरिका, रूस और चीन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह सभी यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित 50 से अधिक राज्यों द्वारा समर्थित है। इसे माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसे तकनीकी दिग्गजों द्वारा भी समर्थन दिया गया है। हस्ताक्षरकर्ता सामान्य सिद्धांतों के एक समूह का पालन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल ग्रिड और अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों को रोकने और ऑनलाइन बौद्धिक-संपत्ति चोरी का मुकाबला करने के लिए सहमत होना।
► वैश्विक आप्रवासन बहस	► फीफा विश्व कप 2018 की विजेता फ्रेंच फुटबॉल टीम के 23 खिलाड़ियों में से लगभग दो तिहाई अरब या अफ्रीकी मूल के आप्रवासी हैं।
► लोगों से लोगों के संबंधों की शक्ति	► भारत से पाकिस्तान के करतारपुर साहिब तक सिखों के लिए वीजा मुक्त गलियारा, भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के माध्यम से संभव नहीं हुआ है अपितु यह एक पक्ष के दूसरे पक्ष द्वारा उठाये गए कदम का विरोध न करने के निर्णय के कारण संभव हुआ है। करतारपुर, उस स्थान के रूप में सम्मानित किया जाता है जहां गुरु नानक ने अपने अंतिम दिन बिताए और अपनी आखिरी सांसें लीं। ► इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों ने सक्रिय रूप से, और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से, एक ऐसे कदम के सम्बन्ध में अगुआ होने का दावा करते हैं जो लोगों से लोगों के संबंधों के लिए एक बड़ी छलांग है। ► यह सिखों को नवंबर 201 9 में गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती पर यहाँ दर्शन करने की अनुमति देगा। इस गलियारे की लंबाई अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों तरफ क्रमशः 4 किमी और 2 किमी है

भूगोल, पर्यावरण तथा जैवविविधता

► मृदा जैवविविधता	► लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (एलपीआर) 2018 के अनुसार, भारत की मृदा जैव विविधता गंभीर खतरे में है। मृदा जैव विविधता में सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म पादप (जैसे निमाटोड), और मैक्रो-जीव (चींटियों, दीमकों और केंचुओं) की उपस्थिति शामिल है।
► जल संरक्षण	► मिशन काकतीय तेलंगाना में सभी छोटे सिंचाई तालाबों और झीलों को पुनर्सृजित करने का एक कार्यक्रम है। पानी की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सिल्ट को हटाने के लिए तालाबों और झीलों की खुदाई की जा रही है। ► मिशन भागीरथ - हर घर को पाइप पीने के पानी प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। यह गुजरात में लागू व्यापक पेयजल ग्रिड से प्रेरित है।
► संस्कृति बनाम जैवविविधता	► दीवाली समारोहों के चरम पर होने के साथ ही, त्यौहार के मौसम के दौरान तांत्रिक अनुष्ठानों और समारोहों के लिए अवैध रूप से पकड़े जाने और बलि दिए जाने वाले उल्लुओं की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है। TRAFFIC, जोकि वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है, ने प्रवर्तन एजेंसियों को सलाह दी है कि उल्लू के तस्करी और बलिदान को रोकने में मदद के लिए अधिक प्रयास किये जाने चाहिए।
► जैवविविधता	► लगभग 25 वर्षों के बाद, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से, होप आइलैंड के तट पर पांच बड़े फ्लेमिंगो (लंबी पैर वाली और लंबी गर्दन वाली पक्षी) के झुंड को देखा गया।
► संवृद्धि बनाम जैवविविधता	► एक अध्ययन ने चालकवाड़ी (महाराष्ट्र) में विंड फार्म के जटिल पारिस्थितिकीय परिणामों का खुलासा किया है। अपने लगातार-घुमते हुए ब्लेड के साथ, पवन टर्बाइनों ने पक्षियों की संख्या में कमी की है, जबकि फैन-थ्रोटेड छिपकली की संख्या में वृद्धि (लगभग 3 गुना) की है। इन छोटे, रंगीन सरीसृपों का पक्षी भक्षण करते हैं। छिपकलियों ने परिवर्तित व्यवहार, और परिवर्तित आकारिकी प्रदर्शित की है और उनके शरीर के रंग कम चमकदार दिखे हैं।
► नदी संरक्षण - गंगा से शुरुआत	► राष्ट्रीय गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) विधेयक, 2018, एक प्रबंधन संरचना बनाने का प्रस्ताव रखता है जो 2,500 किमी लंबी गंगा के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। यह नदी के "निर्बाध, पारिस्थितिक प्रवाह" को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाता है।
► वन्यजीव व्यापार	► चीन ने "विशेष परिस्थितियों" के तहत बाघों और गैंडों से बने उत्पादों में व्यापार पर 25 साल का प्रतिबंध वापस ले लिया। यह प्रभावी ढंग से संगठित अपराध सिंडिकेट्स को मंजूरी देता है, अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और इन उत्पादों की मांग को बढ़ाता है। चीन 1981 में CITES से जुड़ा हुआ था। ► भारत ~ 60% बाघों का घर है और दुनिया के 80% से अधिक एक सींग वाले गैंडे यहाँ रहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर दुनिया के अवैध पशु व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
► संवृद्धि बनाम पर्यावरण ► जैवविविधता का क्षरण	► अरावली पर्वत श्रृंखला में अंधाधुंध खनन से 31 पहाड़ियां गायब हो गयी हैं, जिनके गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए कहा है। ► राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में तांबा, सीसा, जस्ता, रॉक फॉस्फेट, साबुन, सिलिका रेत, चूना पत्थर, संगमरमर और जिप्सम का समृद्ध रिजर्व है। ► WWF ने चेतावनी दी है कि वनों की कटाई और पशुओं द्वारा हमले के बीच कुछ ऑस्ट्रेलियाई राज्यों में कोआला को मिटाया जा सकता है। यदि वर्तमान भूमि सफाई की दर जारी रहती है तो वे न्यू साउथ वेल्स में 2050 तक विलुप्त होने की कगार पर होंगे। ► ध्वनि प्रदूषण बिहार में विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन अभयारण्य में डॉल्फिन आबादी को नुकसान पहुंचा रहा है। यह भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु के लिए एकमात्र अभयारण्य है।
► नवाचारी हरित निवेश ► उत्तरदायी पूंजीवाद	► सेशेल्स ने दुनिया का पहला संप्रभु ब्लू बांड लॉन्च किया है- यह एक सतत वित्तीय उपकरण है जो संधारणीय समुद्री और मत्स्यपालन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बांड, जिसने 15 मिलियन डॉलर जुटाए, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को वित्त पोषित करने के लिए देशों द्वारा पूंजी बाजारों का उपयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन करता है।
► बेस्ट फ्रॉम वेस्ट ► उत्तरदायी पूंजीवाद	► वैश्विक वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, स्वीडिश कंपनी IKEA ने अपने उत्पादों के लिए चावल की भूसी को नए नवीकरणीय सामग्री स्रोत में बदलने की अपनी योजना की घोषणा की। यह कंपनी की 'बेटर एयर नाउ' पहल का हिस्सा है। यह परियोजना भारत से शुरू होगी और नई दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद पर केंद्रित है।

<p>► बाढ़ के मैदानों पर अवैध</p> <p>► विकास संवृद्धि बनाम पर्यावरण</p>	<p>► नई दिल्ली में यमुना के बाढ़ के मैदानों पर करीब 3,000 अवैध नर्सरी हैं। NGT ने उल्लिखित किया था कि सीमेंट के बर्तन और नर्सरी से संबंधित गतिविधियां डीडीए की अनुमति के बिना चल रही थीं, जिस से प्रदूषण हो रहा है क्योंकि टूटे हुए बर्तनों को मलबे में परिवर्तित किया जा रहा है और नदी के तल पर जमा किया जा रहा है।</p>
<p>► पशु संरक्षण</p>	<p>► भारत के हाथियों के पास अब ताजमहल के पास अपना पहला समर्पित अस्पताल है। 'जंबो' अस्पताल यूपी वन विभाग और संरक्षण एनजीओ वाइल्डलाइफ एसओएस के मध्य सहयोग से निर्मित है।</p> <p>► आधुनिक सुविधा घायल, बीमार और वृद्ध हाथी का इलाज करेगी। एनजीटी ने हाथियों की अप्राकृतिक मौतों में वृद्धि पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए MoEF&CC से सभी हाथी गलियारों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित करने पर विचार करने के लिए कहा है।</p>
<p>► आपदाओं का जैवविविधता पर असर</p>	<p>► चक्रवात गाजा के कारण होने वाले विनाश में, प्वाइंट कैलीमेर अभयारण्य को अपना निवास स्थान बनाने वाले सैकड़ों पक्षियों की मृत्यु हो गई है, पेड़ उखड़ गए हैं या उनकी शाखाएं टूट गई हैं या पत्तों से रहित हैं। कुछ जगहों पर पक्षियों के शव पाए गए हैं।</p>
<p>► वाक द टॉक ऑन एनवायरनमेंट</p> <p>► पर्यावरणीय नीतिशास्त्र</p>	<p>► वैश्विक नेता एक अभिनव जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे जो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, अर्थात् यह कार्बन तटस्थ है। वर्चुअल क्लाइमेट शिखर सम्मेलन मार्शल द्वीप समूह के राष्ट्रपति हिल्डा हेइन के दिमाग की उपज है। यदि ग्लोबल वार्मिंग निरंतर जारी रहती है, तो उनका निम्नभूमि वाला प्रशांत द्वीप राष्ट्र बड़े हुए समुद्र में डूब जाएगा।</p> <p>► आभासी शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।</p>
<p>► वेस्ट टू आर्ट</p>	<p>► अपशिष्ट निपटान हर भारतीय शहर के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भुवनेश्वर ने अपने कुछ धातु अपशिष्ट का विशेष उपयोग किया है - यहाँ उन्हें कलाकृतियों में बदल दिया गया है। कलिंग नगर टाउनशिप में आने वाले वेस्ट-टू-आर्ट के भुवनेश्वर ओपन एयर संग्रहालय में मेटल स्क्रेप से बनी 28 प्रभावशाली मूर्तियां हैं।</p>

विज्ञान प्रौद्योगिकी:

<p>► डिजिटल लत</p> <p>► मानसिक स्वास्थ्य</p>	<p>► सिलिकॉन घाटी में स्क्रीन के डर ने हलचल मचा दी है। यहाँ इस तथ्य के सम्बन्ध में सर्वसम्मति बढ़ रही है कि बच्चों के लिए स्क्रीन-टाइम हानिकारक है। माता-पिता आया को फोन, टैबलेट, कंप्यूटर और टीवी को हमेशा बंद रखने और छिपाने का निर्देश दे रहे हैं। कुछ लोग नो-फोन तक का अनुबंध कर रहे हैं, जो उनकी आया के हस्ताक्षर करने के उपरांत, शून्य अनधिकृत स्क्रीन एक्सपोजर की गारंटी देते हैं।</p>
<p>► रोबोटिक</p>	<p>► दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टैक्सीबॉट्स - अर्ध-रोबोटिक टॉ ट्रक का वाणिज्यिक उपयोग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा होगा। यह एयरलाइंस को टैक्सींग के दौरान एयर टर्बाइन ईंधन के उपयोग को कम करने में मदद करेगा।</p> <p>► पार्किंग बे से रनवे तक विमान को टैक्सी या इसके इंजन का उपयोग करके जोर देकर खींचा जाता है। हालांकि, एक टैक्सीबॉट की मदद से दोनों इंजनों को बंद करने के बाद भी एक विमान को चलाया जा सकता है। यह विमान के नोज़ व्हील को उठाता है, ले जाता है और इसे टर्मिनल से रनवे और पुनः रनवे से टर्मिनल तक स्थानांतरित करता है।</p>
<p>► आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का गलत होना</p>	<p>► अमेज़ॉन ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का पता लगने के बाद अपने प्रयोगात्मक AI भर्ती-उपकरण को बंद करने का फैसला किया। एल्गोरिथम ने सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसी तकनीकी नौकरियों के लिए महिलाओं के सीवी को व्यवस्थित रूप से डाउनग्रेड किया था।</p>
<p>► रोबोटिक</p> <p>► स्वदेशी तकनीक</p>	<p>► केरल के युवा इंजीनियरों के एक समूह ने एक रोबोट तैयार किया है जिसे उन्होंने 'बंदीकूट' नाम दिया है - यह मैनहोल सफाई के लिए विकसित पहला स्वदेशी रोबोट है। यह सीवर और मैनहोल में प्रवेश करने और सफाई करने में सक्षम है।</p>
<p>► आर्टिफिशल इंटेलिजेंस</p>	<p>► चीन की राज्य समाचार एजेंसी सनिहुआ ने एक वर्चुअल न्यूज़रीडर का अनावरण किया है। वास्तविक सनिहुआ प्रस्तुतियों के आधार पर प्रस्तुतियों की आवाज, होंठ की गति और अभिव्यक्तियों को संश्लेषित करने के लिए एक AI प्रणाली का उपयोग किया गया है।</p>

<p>► अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विकास</p> <p>► तकनीकी का स्वदेशीकरण</p>	<p>► भारत के सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर जीएसएलवी एमके III ने जीएसएटी 2 9 लॉन्च किया है, जो भारतीय भूमि से एक भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह है।</p> <p>► जीएसएलवी एमके III एक त्रिचरणीय हेवी-लिफ्ट रॉकेट है। इसके पहले चरण में दो ठोस ईंधन स्ट्रैप-ऑन इंजन, दूसरे चरण में तरल प्रोपेलेंट कोर और तीसरे चरण के लिए क्रायोजेनिक इंजन है।</p> <p>► यह भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) के लिए 4000 किलो की रेंज में वजन वाले या लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) के लिए लगभग 10,000 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।</p> <p>► जीएसएलवी एमके III रॉकेट को भारत के दूसरे चंद्रमा मशिन चंद्रयान 2 के लिए लॉन्च वाहन के रूप में नामित किया गया है जो अगले वर्ष जनवरी के लिए निर्धारित है। साथ ही इसे भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान जसि 2022 के लिए लक्षित किया जा रहा है, में भी प्रयोग किया जायेगा।</p>
<p>► स्वदेशी तकनीक</p>	<p>► स्वदेशी रूप से विकसित भारत की इंजनरहति ट्रेन "ट्रेन 18" का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक मुरादाबाद-रामपुर खंड में ट्रेक पर आयोजित किया गया था।</p>

नीति शास्त्र

<p>► प्रकृति द्वारा एक, संस्कृति द्वारा विभाजित</p>	<p>► चार दशक में पकड़े गए, अंतरराज्यीय विवाद, उमरू ग्राम के लोग (असम-मेघालय सीमा पर) अमूर फाल्कन के लिए एक सुरक्षित स्टॉपओवर सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित होते हैं। गोरखा और खासी दोनों समुदाय ने एकजुट होकर पक्षियों को मारने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, 25,000 का जुर्माना तय किया है।</p> <p>► अक्टूबर के आसपास, अमूर फाल्कन की बड़ी संख्या साइबेरिया से उत्तरी भारत में अपने अंतिम गंतव्य सोमालिया, केन्या और दक्षिण अफ्रीका के रास्ते पहुंच गई। इन पक्षियों में से सभी का सबसे लंबा प्रवास मार्ग है, जो सालाना 20,000 किमी तक रहा है।</p>
<p>► इच्छाशक्ति</p>	<p>► केरल के चेपड़ में कार्तियनी अम्मा की कहानी, अलपुझा - केरल की साक्षरता परीक्षा में भाग लेने वाली सबसे पुरानी व्यक्ति हैं- यह एक व्यक्ति की इच्छाशक्ति की जीत की एक हार्दिक कहानी है। उन्होंने न केवल परीक्षा में प्रवेश किया, 100 में से 98 अंक पाए, बल्कि अपनी प्राथमिक शिक्षा जारी रखने की इच्छा व्यक्त की।</p>
<p>► पशुओं के अधिकार</p> <p>► मानव पशु संघर्ष</p>	<p>► कहा जाता है कि 13 गांवों के लोगों की हत्या करने वाले बाघ को वन विभाग के अधिकारियों और एक नागरिक शिकारी की एक टीम ने यवतमाल के बोराती गांव के पास गोली मार दी थी। वन्यजीव कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अवनी को शांत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। न्यायालय ने अंतिम उपाय के रूप में इस पशु को गोली मारने का आदेश दे दिया था, तथा इसके लिए एक वन्यजीव जीवविज्ञानी और एक ट्रेनकिंजाईलिंग विशेषज्ञ के साथ एक दल के गठन का निर्देश दिया।</p>
<p>► पर्यावरणीय नीतिशास्त्र</p>	<p>► कुंठकुलम (टीएन) गांव के लोगों ने बादाम और नीम के पेड़ों के ऊपर प्रवासी पक्षियों के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए क्रेकर्स पर स्वेच्छिक प्रतिबंध लगाया है।</p>
<p>► नेतृत्व</p>	<p>► क्या वह अभी भी सिरीसेना के साथ काम कर सकता है, रणिल विक्रमसिंघे ने कहा: "मुझे उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यह एक सवाल है जिसे आपको उनसे पूछना चाहिए। संविधान व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के लिए प्रावधान नहीं करता है। "</p>
<p>► गाँधीवादी नीतिशास्त्र</p>	<p>► सिरिल रामफोसा, जो दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला की पसंद थे, एक समर्पित गांधी अनुयायी हैं। अप्रैल 2018 में, रामफोसा ने जोहान्सबर्ग के दक्षिण में एक भारतीय टाउनशिप, लेनासिया में वार्षिक 'गांधी वॉक' में लगभग 5000 लोगों का नेतृत्व किया, जो समुदायिक जागरूकता और फिटनेस को बढ़ावा देने की मांग कर रहे थे।</p>
<p>► वीरता</p> <p>► साहस</p> <p>► नेतृत्व</p>	<p>► हाल ही में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की मृत्यु हो गई। उनको 'बैटल ऑफ लांगवाला' का नायक माना जाता है और उन्हें बाद में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1971 के युद्ध के दौरान रात के दौरान सैनिकों के एक छोटे समूह की अगुआई करते हुए उन्होंने पाकिस्तानी हमले का सामना किया। 1997 की फिल्म बॉर्डर, जिसमें सनी देओल ने ब्रिगेडियर चांदपुरी की भूमिका निभाई, लोंगवाला युद्ध पर आधारित थी।</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▶ साहस ▶ RTI कार्यकर्ता ▶ वास्तविक राष्ट्रभक्ति 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ मेघालय के प्रसिद्ध आरटीआई कार्यकर्ता एग्रेस खारशींग पर कोयले और चूना पत्थर समृद्ध पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में अपराधियों के एक समूह ने हमला किया था। ▶ मेघालय के कोयला रिजर्व का अधिकांश हिस्सा निजी और सामुदायिक भूमि मालिकों द्वारा अंधाधुंध रूप से खनन किया जाता है। एनजीटी ने कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया और कोयला गड्डे की सीलिंग का आदेश दिया। हालांकि, इसे 3.4 MT निकाले गए कोयले के परिवहन की इजाजत दी गई। ▶ सुश्री खारशींग ने पिछले चार वर्षों में कोयला के अवैध खनन और परिवहन के दस्तावेज एकत्र किये जिसके कारण वे कोयला माफिया के क्रोध का भाजन बनीं। मार्च में, 38 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता Poipynhun Majaw, को स्थानीय जनजातीय परिषद और ▶ सीमेंट कंपनियों, (जिन्हें कथित रूप से अनुमति के बिना चूना पत्थर निकालने की इजाजत दी गई थी) के बीच गठबंधन का खुलासा करने के कारण मार दिया गया।
<ul style="list-style-type: none"> ▶ कारपोरेट नीतिशास्त्र ▶ जवाबदेहिता 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ पिछले साल, कंपनी अधिनियम में संशोधन हाल के दिनों में इंडिया इंक के कामकाज में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक था। नए अधिनियम के तहत, सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपने लेखा परीक्षकों को परिवर्तित करते रहने की आवश्यकता थी। ये किसी भी व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय स्वास्थ्य की स्थिति को तैयार करते हैं और प्रमाणित करते हैं।
<ul style="list-style-type: none"> ▶ दृढ़ता ▶ उत्कृष्टता ▶ सरल जीवन ▶ उच्च विचार 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ मैरी कॉम एकमात्र महिला है जिन्होंने छह बार विश्व एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बनकर रिकॉर्ड बनाया है। वे एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने सात विश्व चैंपियनशिप में से प्रत्येक में पदक जीता है। (6 स्वर्ण, 1 रजत)

महीने का डेटा:

▶ उप-राष्ट्रीय आर्थिक संवृद्धि	▶ आंध्र प्रदेश ने पिछले चार वर्षों के दौरान 10.5% की औसत वृद्धि के साथ देश प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसने महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई विकसित राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
▶ वायु प्रदूषण	▶ डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में भारत में सबसे अधिक मौतें वायु प्रदूषण से संबंधित होती हैं। हर वर्ष 2 मिलियन मौतें होती हैं, जो खराब हवा की गुणवत्ता के कारण वैश्विक मौतों का 25% है। भारत ने 2019 को आधार वर्ष मानते हुए आने वाले 5 वर्षों में पीएम को 30% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
▶ WB इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस	विश्व बैंक के इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में भारत 23 स्थानों की छलांग लगा कर 77 वें स्थान में पहुंच गया। 2017 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 100 वां था।
▶ वैश्विक नगरीकरण	दुनिया की लगभग 55% आबादी अब शहरी क्षेत्रों में रहती है। लगभग 1.4 मिलियन लोग हर हफ्ते दुनिया भर के शहरों में जाते हैं।
▶ महासागर और वैश्विक तापन	आईपीसीसी: विश्व के महासागरों ने मानव निर्मित कार्बन उत्सर्जन के कारण तापमान वृद्धि का 9 0% अवशोषण अवशोषित कर लिया है
▶ जल गुणवत्ता	पृथ्वी आयोग ने कहा कि भारत को जल गुणवत्ता सूचकांक पर 122 देशों में से 120 देशों में स्थान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 70% देश की जल आपूर्ति दूषित है।
▶ हरित इमारतें ▶ संधारणीय पर्यावास	एकीकृत आवास आकलन (जीआरआईएचए) के लिए ग्रीन रेटिंग के आकलन के अनुसार भारत की इमारतों में से 2% से भी कम हरित इमारतें हैं।
▶ ओजोन परत ▶ वैश्विक तापन	संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में कहा गया है कि ओजोन परत जो कैंसरकारी सौर किरणों से रक्षा करती है, प्रति दशक 1 से 3% की दर से ठीक हो रही है। इस प्रकार हानिकारक रसायनों के मुक्त होने के कारण होने वाले, क्षरण की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है।
▶ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2018	भारतीय औसत स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति दिन 3 रुपये खर्च किया जाता है विश्व औसत 6% है तो सरकार स्वास्थ्य देखभाल पर जीडीपी का 1.3% खर्च करती है एक एलोपैथिक डॉक्टर 11,000 की जनसंख्या (डब्ल्यूएचओ सीमा के 10 गुना) का इलाज

► बाल स्वास्थ्य	► दुनिया में भारत में निमोनिया और दस्त के कारण बच्चों की मौत का सबसे अधिक है।
► कृषि में महिला भागीदारी	► एनएसएसओ- श्रम ब्यूरो डेटा => बढ़े हुये मशीनीकरण के कारण, श्रम गहन उद्योगों के लिए कम अंतरराष्ट्रीय मांग तथा अन्य कारणों से, कृषि में महिला श्रमिकों का हिस्सा पिछले 3 दशकों में 44 से 30% तक गिर गया है।
► युवा जागरूकता	► ओआरएफ-WEF सर्वेक्षण: '70% युवा सरकारी कौशल विकास कार्यक्रम से अनभिज्ञ हैं, कम प्रशिक्षण भागीदारी ज्यादातर वित्तीय बाधाओं और समय की बाधाओं के कारण थी।
► वैश्विक तापन	► 2022 तक, भारत की विश्व के 25% एयरकंडीशनर होने की उम्मीद है। ठंडा करने के लिए प्रयोग करे जाने वाले रेफ्रिजरेन्ट्स ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। यदि इन पर रोक नहीं लगाई गई, तो वे तापमान 0.50 C से बढ़ा सकते हैं - रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। Mountain Institute.
► लाइफस्टाइल डिजीज	► चीन डाइबिटीज़ कैपिटल ऑफ़ दा वर्ल्ड है और चंडीगढ़ 'डाइबिटीज़ कैपिटल ऑफ़ इंडिया है। ► आईसीएमआर-इंडियाआईबी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चंडीगढ़ में डाइबिटीज़ का प्रसार 13.6% है, जबकि 15 राज्यों में राष्ट्रीय औसत 7.3% था। .
► भूख ► कृषि बनाम भूख	NFHS-2016 के अनुसार: ► एनएफएस-2016 के अनुसार: ► पांच वर्ष से कम उम्र के ठिगने बच्चों (उम्र की तुलना में कम लम्बाई) की औसत संख्या (38.4%) वैश्विक औसत (22.9%) से काफी अधिक है। ► अल्प वजन (उम्र की तुलना में कम वजन) वाले बच्चों की दर (35.7%) वैश्विक औसत (13.5%) से काफी अधिक है। ► भारत पांच वर्ष से कम आयु के 53.3 मिलियन से अधिक स्टंटेड, 49.6 मिलियन अंडरवेट और 29 .2 मिलियन वेस्टेड (ऊंचाई के लिए कम वजन) बच्चों का घर है। ► हरियाणा जैसे कृषि अधिशेष राज्यों में कुपोषण उच्च है (34% स्टंटिंग और 29 .5% कम वजन)। ► चिंताजनक बात यह है कि इसके कुछ कृषि-विकसित जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम) में कुपोषण ओडिशा के औसत से भी अधिक है। ► मध्य प्रदेश ने अनाज उत्पादन में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की है, लेकिन इसके अधिकांश जिलों में बच्चों में कम वजन (42.8%) और ठिगने पैर से ग्रसित (41.9%) होने के साथ तीव्र कुपोषण अभी भी महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान है।
► फार्मास्यूटिकल उद्योग	► भारतीय दवा क्षेत्र उद्योग विभिन्न टीकों के लिए वैश्विक मांग के 50%, यू.एस. में सामान्य मांग के 40% और यूके में सभी दवाओं के 25% से अधिक की आपूर्ति करता है। 80% से अधिक एंटीरेट्रोवायरल दवाओं (एड्स में उपयोगी) की भारत द्वारा आपूर्ति की जाती है।
► विनिवेश	► वर्तमान एनडीए सरकार का 1991 से हुए सभी विनिवेशों में 58% हिस्सा है (3.63 लाख करोड़ रुपये में से 2.1 लाख करोड़) ► जोकि यूपीए सरकार द्वारा अपनी दोनों कार्यकालों में किये गए विनिवेश का लगभग दोगुना है
► आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार	► भारत में जेल में कैदियों की कुल संख्या का 62% हिस्सा अंडरट्रायल कैदियों का है। जब की विश्व में यह औसतन 18-20% है। इन आंकड़ों ने हमारे तंत्र की मान्यता के सम्बन्ध में प्रश्न खड़े किये हैं। ► फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं जो कि खतरनाक हैं। केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का उपयोग महत्वपूर्ण साक्ष्य की जांच के लिए किया जाता है जो कई आपराधिक मामलों में जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक हो सकते हैं। औसत= 40%; यूपी = 80%।

महीने के कथन:

► सत्ता और राजनीति	<p>► सत्ता</p> <p>► लगभग सभी व्यक्ति हर विपत्ति को झेल सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं, तो उसको सत्ता दें। ~ लिंकन</p> <p>► सत्ता भ्रष्टाचारी बनाती है. पूर्ण सत्ता पूर्ण तरह भ्रष्टाचारी बना देती है। - लॉर्ड एक्टन राजनीति</p> <p>► राजनीति में, कोई स्थायी दुश्मन नहीं हैं और कोई स्थायी मित्र नहीं हैं, केवल हित स्थायी हैं। विलियम ब्ले</p>
--------------------	--

- राजनीतिक भागीदारी
- राजनीति में भाग लेने से इंकार करने के दण्डों में से एक ये दंड है, कि आप अपने से कमतर लोगों के द्वारा शासित होते हैं। ~ प्लेटो
- बुराई की जीत के लिए सिर्फ एकमात्र चीज ज़रूरी है कि अच्छे पुरुष कुछ ना करें। "- एडमंड बर्क
- भारतीय नेता
- भारत एक युवा देश है जो वृद्ध व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। - देवेश कपूर

प्रिलियम्स कैप्सूल:

Ques.1 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह योजना भारतीय किसानों को किफायती और समय पर क्रेडिट प्रदान करने के लिए 1998 में भारत में लॉन्च की गई थी।
2. इस योजना के माध्यम से ऋण केवल खेती करने वाले किसानों को दिया जाता है, काश्तकारों को नहीं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques. 2 स्टबल बर्निंग के कारण वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निर्मुक्त होती है?

1. मेथेन
2. कार्बन डाई ऑक्साइड
3. परऑक्सी एसिड नाइट्रेट (PAN)
4. वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOC)
5. सल्फर डाई ऑक्साइड

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

- (a) 1, 2 और 4
- (b) 1, 3 और 5
- (c) 2, 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 4, और 5

Ques. 3 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सीबीआई गैर-संवैधानिक और गैर-सांविधिक निकाय है।
2. यह डीपीएसई अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है।
3. यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत संचालित होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Ques. 4 रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) अधिनियम 1934 के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अनुसूचित बैंकों को इस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है।
2. इस अधिनियम में धारा 7 के तहत विशेष प्रावधान है जो केवल वित्त मंत्रालय को सार्वजनिक हित में आरबीआई को निर्देश जारी करने की अनुमति देता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques. 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि है।
2. एंटी-ग्लोबल वार्मिंग विधि जैसे स्ट्रेटोस्फेरिक एयरोसोल इंजेक्शन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एकमात्र तरीका है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.6 ट्यूबरकलोसिस (TB) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत विश्व में टीबी के सर्वाधिक बोझ वाला देश है।
 2. भारत की टीबी उन्मूलन योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के लक्ष्य वर्ष के पीछे है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.7 भारतीय संसद में निजी सदस्य विधेयक के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. किसी भी सदन में निजी सदस्य विधेयक की शुरूआत के लिए चौदह दिन की सूचना की आवश्यकता होती है।
 2. एक संवैधानिक संशोधन बिल एक निजी सदस्य विधेयक हो सकता है
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.8 'ग्रीन क्रेकर्स' शब्द सम्बंधित है:

- (a) नए प्रकार के पटाखे जो शून्य वायु प्रदूषण के साथ केवल हरित उत्सर्जन करते हैं।
- (b) इन पटाखों में वायु प्रदूषण फैलाने वाले हानिकारक रसायन नहीं होते।
- (c) प्रमाणित पटाखे जिनमें ध्वनि या प्रकाश
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ques.9 हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द 'न्यूक्लियर ट्रायड' संदर्भित करता है:

- (a) हाल ही में भारत द्वारा रूस से खरीदा गया बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम
- (b) एक विशेष प्रकार की पनडुब्बी जो परमाणु टारपीडो को समुद्र तल के ऊपर और नीचे से भी फायर कर सकती है।
- (c) यह एक तीन-स्तरीय सैन्य बल संरचना है जिसमें भूमि-लॉन्च परमाणु मिसाइल, परमाणु मिसाइल-सशस्त्र पनडुब्बियों और परमाणु बम और मिसाइलों के साथ सामरिक विमान शामिल हैं।
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ques.10 13th ईस्ट एशिया समिट के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह केवल आसियान देशों का क्षेत्रीय मंच है।
 2. भारत ने इस शिखर सम्मेलन में संवाद साथी के रूप में भाग लिया।
 3. इस मंच का पहला शिखर सम्मेलन 2005 में हुआ था।
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1
- (d) 1 और 3

Ques.11 केप्लर स्पेस टेलिस्कोप के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) की संयुक्त परियोजना है।
 2. इसे वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था।
 3. यह ट्रांजिट डिटेक्शन विधि का उपयोग करता है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) 2 और 3
- (b) 1 और 3
- (c) 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

Ques.12 INS अरिहंत के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह परियोजना 75I के तहत परमाणु संचालित पनडुब्बी है।
 2. यह एडवांस टेक्नोलॉजी वेसेल (एटीवी) कार्यक्रम के तहत बनाया गया है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.13 इज़ ऑफ़ इंडिंग बिजनेस इंडेक्स, 2018 के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा इसमें 11 विभिन्न पैरामीटर को कवर किया जाता है।
2. ब्रिक्स समूह में भारत का रैंक चीन के बाद दूसरा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.14 भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. भारत में 111 अंतर्देशीय जलमार्ग हैं।
2. वर्ष 2016 में गठित अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करता है।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.15 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के सूचकांक बाहरी प्रतिस्पर्धात्मकता के संकेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
2. एनईईआर और आरईईआर एक-दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.16 हाल ही में सुर्खियों में रहे पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पक्षी उद्यान के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह अभ्यारण्य ब्लैकबक एंटेलोप के संरक्षण के लिए बनाया गया था।
2. यह रामसर वेटलैंड कन्वेंशन के तहत संरक्षित क्षेत्र है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.17 यदा-कदा सुर्खियों में रहने वाला करेंसी स्वेप एग्रीमेंट क्या है?

- (a) यह आईएमएफ द्वारा अनुमोदित विधि है, जिसमें देश इसके पोर्टल के माध्यम से अपनी मुद्राओं को परिवर्तित करते हैं।
- (b) यह विश्व बैंक के अंतर्गत कम विकसित देशों को वित्त प्रदान करने के लिए उनकी कम मूल्यवान मुद्रा स्वीकार करने के लिए किया गया एक समझौता है।
- (c) यह दो देशों के बीच अपनी मुद्राओं के बीच कुछ निश्चित मुद्रा को स्वेप करने के लिए एक समझौता है।
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ques.18 संक्रामक रोग पोलियो के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा भारत को सभी प्रकार के पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया गया है।
2. आईपीवी ओपीवी से सस्ता और सुरक्षित है, जिसे विश्व स्तर पर टीकाकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.19 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड देश में भुगतान प्रणाली पर सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय है।
2. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques. 20 'SAWEN' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वन्यजीव अपराधों का मुकाबला करने के लिए यह दक्षिण एशियाई देशों का अंतर-सरकारी वन्यजीव कानून प्रवर्तन निकाय है।
2. इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.21 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं:

1. NBFC भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत हैं।
2. NBFC वाणिज्यिक पत्र जारी नहीं कर सकते हैं।
3. भारत में, NBFC मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 3
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

Ques.22 भारत में ई-कॉमर्स के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. हाल ही में भारत में ई-कॉमर्स को विनियमित करने वाली नीति लॉन्च की गई थी।
2. भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय के इन्वेंटरी मॉडल में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques. 23 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है।
2. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित करने के लिए सरकार का नोडल कार्यक्रम है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques. 24 IPCC ने जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग का प्रभाव पहले के अनुमान की तुलना में कम है और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए देशों को थोड़ा छूट प्रदान की जा सकती है।
2. रिपोर्ट फसल पैदावार में गिरावट के पर्याप्त सबूत प्रदान करती है। अभूतपूर्व जलवायु परिवर्तन और बढ़ी हुई संवेदनशीलता 2050 तक गरीबी को कई मिलियन तक बढ़ा सकती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.25 राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह फंड आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रशासित है।
2. NSSF का उद्देश्य भारत के सार्वजनिक खाते से छोटे बचत लेनदेन को कम करना और उनके परिचालन को एक पारदर्शी और आत्मनिर्भर तरीके से सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.26 वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड फॉर नेचर (WWF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एक विशेष एजेंसी है।
2. हर दो साल में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.27 पोषण अभियान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक बहु मंत्रालयी अभिसरण मिशन है जिसका विज़न 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत सुनिश्चित करना है।
2. यह स्ट्रॉंग, अल्प-पोषण, अति-पोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन में कमी लाने का लक्ष्य रखता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.28 GSLV MK III-D2/ GSAT 29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. GSAT 29 भारत से प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह है।
2. यह प्राकृतिक संसाधनों के लिए जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों का निरीक्षण करने के लिए एक दूरस्थ संवेदन उपग्रह है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.29 WTO की विवाद समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) अपने अधिनिर्णयन के तहत शामिल सरकारों के बीच व्यापार विवादों पर निर्णय लेता है।
2. विवाद निपटान निकाय डब्ल्यूटीओ समझौते के नियमों का पालन न करने वाले देशों को दंडित कर सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.30 ब्लैक होल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह मूल रूप से मजबूत गुरुत्वाकर्षण प्रभाव वाले द्रव्यमानरहित क्षेत्र है।
2. इसका निर्माण तब होता है जब एक बड़ा तारा नष्ट हो जाता है और पदार्थ गुरुत्वाकर्षण की भारी शक्ति के तहत एक छोटी सी जगह में संचित हो जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

Ques.31 महाद्वीपीय मग्नतट एवं महाद्वीपीय ढलान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. महाद्वीपीय मग्नतट और ढलान महाद्वीपीय मार्जिन का हिस्सा हैं।
 2. महाद्वीपीय मग्नतट की ढलान महाद्वीपीय ढलान से कम है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.32 हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश द्वारा विश्व का प्रथम सॉवरेन ब्लू बांड जारी किया जाता है:

- (a) मॉरीशस
- (b) सेशेल्स
- (c) मालदीव
- (c) चीन

Ques.33 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी किया जाता है।
 2. 2018 की हाइलाइट्स की रिपोर्ट, मृदा जैव विविधता और परागणकों के संकट को व्यक्त करती है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.34 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा इसकी जनजातियों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अंडमान को निकोबार समूह से ग्यारह डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है।
 2. सेंटिनेलीज़ जनजाति मंगोलोइड हैं।
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.35 दालों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. बीफ की तुलना में दालों की जल दक्षता अधिक है।
2. दालों के साथ अंतराशयन (इंटरक्रॉपिंग) कृषि जैव विविधता को बढ़ाता है और पशुओं और पक्षियों के लिए और अधिक विविधतापूर्ण परिदृश्य बनाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.36 UN एनवायरनमेंट अवार्ड 2018 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया।
2. इस पुरस्कार को केवल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) प्रायोजित करता है।
3. डब्ल्यूसीसीबी ने इन पुरस्कारों को इनोवेशन श्रेणी में सम्मानित किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) 2 और 3
- (b) 1 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

Ques.37 जम्मू-कश्मीर विधानसभा के हालिया विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्यपाल के अनुरोध के बाद राष्ट्रपति ने विधानसभा को भंग कर दिया।
2. विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या इसे 111 सदस्यों की कुल संख्या से कम है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.38 ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था इसे जारी करती है?

- (a) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)
- (b) जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी)
- (c) विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ)
- (d) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी)

Ques.39 भारतीय निर्वाचन आयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. चुनाव आयोग अखिल भारतीय संवैधानिक निकाय है।
2. चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तों को संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है।
3. संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की अवधि निर्दिष्ट की है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

- (a) 2 और 3
- (b) 1 और 3
- (c) 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

Ques.40 GROWTH इंडिया टेलिस्कोप के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह हनले, लद्दाख में स्थित है तथा बहु-राष्ट्रीय सहयोग पहल का हिस्सा है।
2. पूर्णतः रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप को प्रकाश वर्ष से बहुत कम समय-पैमाने-यथा वर्ष, दिन और यहां तक कि घंटे-पर होने वाली ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.41 एंटी डंपिंग ड्यूटी के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जिसे घरेलू सरकार विदेशी आयात पर लगाती है यदि उसे यह लगता है कि आयातित पदार्थ का मूल्य उचित बाजार मूल्य से नीचे है।
2. यह उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आरोपित और प्रवर्तित किया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.42 हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द मॉस्को फॉर्मेट किससे सम्बंधित है?

- (a) नाटो से लड़ने के लिए गैर-नाटो सदस्यों द्वारा नया गठबंधन।
- (b) रूस और यूक्रेन के बीच शांति प्रक्रिया।
- (c) अफगानिस्तान में शांति और समृद्धि के लिए नई पहल।
- (d) यूरेशियाई राष्ट्रों और रूस के बीच रक्षा गठबंधन।

Ques.43 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. संविधान के तहत मार्शल लॉ परिभाषित किया गया है।
2. मार्शल लॉ की घोषणा स्वचालित रूप से उस क्षेत्र में लोगों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देती है, जहाँ यह लागू होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.44 WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कण्ट्रोल के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह WHO के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है और 2005 में लागू हुई थी।
2. यह प्रोटोकॉल देशों को प्रवर्तन उपायों यथा जब्ती एवं जब्त उत्पादों के निपटान के लिए बाध्य करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.45 जिब्राल्टर की खाड़ी के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ?

- (a) यह एक सँकरी खाड़ी है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है।
- (b) जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को का हिस्सा है।
- (c) जिब्राल्टर आइबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है।
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ques.46 निम्नलिखित शहरों को दक्षिण से उत्तर के आधार पर व्यवस्थित करें:

1. बैकाक
2. कुआला लुम्पुर
3. हनोई
4. नोम पेन्ह
5. वियनतियाने
6. ने पीई टॉ

निम्नलिखित कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए:

- (a) 6-5-4-3-2-1
- (b) 5-6-3-4-2-1
- (c) 4-2-6-5-3-1
- (D) 2-4-1-5-6-3

Ques.47 हाल ही में समाचार में देखा गया 'तियांगोंग' है:

- (a) चीन द्वारा लांच की गई अंतरिक्ष वेधशाला।
- (b) चीन द्वारा लांच किया गया संचार उपग्रह।
- (c) चीन का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम।
- (d) चीन की नवीनतम परमाणु पनडुब्बी

Ques.48 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. कोआला पूर्वोत्तर भारत में स्थानिक रूप से पाए जाते हैं।
2. कोआला को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य घोषित किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Ques.49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में अधीनस्थ न्यायालय राज्य उच्च न्यायालयों के अधीन कार्य करते हैं।
2. भारतीय संविधान में अधीनस्थ अदालतों के संगठन के लिए कोई प्रावधान नहीं है और इस सम्बन्ध में प्रावधान राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिए गए हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) 2 और 3
- (b) 1 और 3
- (c) 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

Ques.50 निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये:

1. कनाडा
2. भारत
3. मैक्सिको
4. ऑस्ट्रेलिया
5. चीन
6. सिंगापुर
7. अमेरिका

उपरोक्त में से कौन से देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के सदस्य हैं?

- (a) 1, 2 और 3
 - (b) 3, 4 और 6
 - (c) 1, 3, 4, 5, 6 और 7
- उपरोक्त सभी

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन: अभ्यास प्रश्न

1. भारत के आर्थिक, भू-राजनैतिक और सुरक्षा निहितार्थों के लिए आसियान के महत्त्व का परीक्षण कीजिये।
2. नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) तथा इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन (ISRO) के मध्य सहयोग की प्रकृति, उनकी उपलब्धियों तथा भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा कीजिये।
3. हाल के दिनों में सीबीआई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी द्वारा अनुभव किये जाने वाले मुद्दों और यह सुनिश्चित करने में कि अब यह पिंजड़े में बंद तोते की तरह कार्य नहीं करेगी, न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिये?
4. भारत दुनियाभर में बच्चों के बीच दस्त और निमोनिया से सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार देशों में से एक है। इसके कारणों का विश्लेषण करें और जांच करें कि इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?
5. भारत में इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस में आसानी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करें और बतायें कि और क्या करने की आवश्यकता है।
6. चर्चा करें कि आरबीआई अधिनियम की धारा 7 कैसे आरबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है। इस अधिनियम से सम्बंधित हालिया मुद्दे कौन से हैं। चर्चा कीजिये।

[Click here](#) to submit your answer.



(Scan QR Code to submit your answers)

प्रिलियम्स कैप्सूल के उत्तर :

उत्तर : 1 (a)	उत्तर : 26 (b)
उत्तर : 2 (d)	उत्तर : 27 (a)
उत्तर : 3 (a)	उत्तर : 28 (b)
उत्तर : 4 (a)	उत्तर : 29 (a)
उत्तर : 5 (b)	उत्तर : 30 (a)
उत्तर : 6 (d)	उत्तर : 31 (c)
उत्तर : 7 (b)	उत्तर : 32 (b)
उत्तर : 8 (b)	उत्तर : 33 (b)
उत्तर : 9 (c)	उत्तर : 34 (d)
उत्तर : 10 (a)	उत्तर : 35 (c)
उत्तर : 11 (a)	उत्तर : 36 (b)
उत्तर : 12 (b)	उत्तर : 37 (b)
उत्तर : 13 (c)	उत्तर : 38 (c)
उत्तर : 14 (d)	उत्तर : 39 (a)
उत्तर : 15 (b)	उत्तर : 40 (c)
उत्तर : 16 (c)	उत्तर : 41 (a)
उत्तर : 17 (c)	उत्तर : 42 (c)
उत्तर : 18 (d)	उत्तर : 43 (d)
उत्तर : 19 (c)	उत्तर : 44 (a)
उत्तर : 20 (c)	उत्तर : 45 (b)
उत्तर : 21 (d)	उत्तर : 46 (d)
उत्तर : 22 (d)	उत्तर : 47 (c)
उत्तर : 23 (c)	उत्तर : 48 (b)
उत्तर : 24 (c)	उत्तर : 49 (a)
उत्तर : 25 (b)	उत्तर : 50 (c)

Note : For detailed solution please click [here](#)



(Scan QR Code for detailed solution)

कृपया अपने सुझाव साझा करें
upsciq@gmail.com